



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 337]
No. 337]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 7, 2006/चैत्र 17, 1928
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 7, 2006/CHAITRA 17, 1928

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2006

सं. 1(आर ई 2006)/2004-2009

का.आ. 512(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 के पैराग्राफ 1.2 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का सं. 22) की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, 7 अप्रैल, 2006 तक यथा अद्यतन वार्षिक परिशिष्ट को शामिल करते हुए, इस अधिसूचना के अनुलग्नक में यथा निहित विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 को एतद्वारा अधिसूचित करती है। यह नीति 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होगी।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/94/180/विदेश व्यापार नीति/एएम 07/पी सी-1]

के. टी. चाको, महानिदेशक, विदेश व्यापार
और पदेन अपर सचिव

अनुलग्नक

विदेश व्यापार नीति

प्रस्तावना

सन्दर्भ

विश्व व्यापार में भारत द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए देश के विदेश व्यापार के समग्र विकास हेतु विस्तृत दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। यद्यपि निर्यात में वृद्धि का विशेष महत्व है, फिर भी हमारी अर्थव्यवस्था को उद्वेलित करने के लिए हमें जरूरी

आयातों को सुविधाएं प्रदान करनी होंगी। विकास के लिए इन नीतियों के योगदान को अधिकतम करने हेतु व्यापार और अन्य आर्थिक नीतियों के बीच सामंजस्य और सुसंगति महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, वार्षिक निर्यात-आयात नीति घोषित करने की मौजूदा परम्परा को जारी रखते हुए इससे कहीं आगे जाकर भारत की विदेश नीति की विकासात्मक आवश्यकताओं का समेकित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। नई विदेश व्यापार नीति इसी सन्दर्भ में जारी की जा रही है।

उद्देश्य

व्यापार अपने आप में अन्तिम उद्देश्य नहीं है बल्कि यह आर्थिक विकास और राष्ट्रीय विकास का माध्यम है। प्रमुख उद्देश्य केवल विदेशी मुद्रा का अर्जन नहीं बल्कि संबंधित आर्थिक कार्यक्रमों को उद्वेलित करना है। विदेश व्यापार नीति इस विचारधारा से प्रेरित है और दो प्रमुख उद्देश्यों से प्रभावित है, जोकि इस प्रकार हैं :—

1. अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में हमारी भागीदारी की प्रतिशतता को आगामी पांच वर्षों के भीतर दो गुनी करना : तथा
2. रोजगार सृजन को बढ़ावा देते हुए आर्थिक विकास के प्रभावी उपकरण के तौर पर कार्य करना।

रणनीति

अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित रणनीतियों को अपनाने हुए इन उद्देश्यों को प्राप्त करना प्रस्तावित है :

1. हमारे व्यवसायकर्ताओं, उद्योगपतियों और व्यापारियों की स्वाभाविक उद्यमियता को बढ़ावा देने के लिए विश्वास और पारदर्शिता का माहौल बनाने हेतु नियंत्रणों को हटाना।
2. प्रक्रियाओं को सरल बनाना और सौदे की लागत को कम करना।

3. इस मूल सिद्धान्त के आधार पर कि शुल्कों और प्रशुल्कों का निर्यात नहीं किया जाना चाहिए, अतः निर्यात उत्पादों में इस्तेमाल की गई निविष्टियों पर सभी प्रशुल्कों और शुल्कों को निःशुल्क बनाना।

4. विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं के क्षेत्र में भारत को एक विश्व ताकत के रूप में विकसित करना।

5. उन क्षेत्रों का पता लगाना तथा इन्हें विकसित करना जिनपर विशेष बल दिया जाना है, जिससे अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा होंगे, विशेषकर अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, और प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रेरक स्त्रोतों को विकसित करना।

6. भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के प्रौद्योगिकीय और बुनियादी सुविधाओं का विकास करना, विशेष रूप से पूंजीगत वस्तुओं और उपकरणों का आयात करके, इस प्रकार गुणवत्ता के स्वीकृत मानदण्डों को अन्तरराष्ट्रीय रूप से प्राप्त करते हुए, मूल्य संवर्धन और उत्पादकता में वृद्धि करना।

7. शुल्क वापसी के ढांचे की प्रणाली से बचना और यह सुनिश्चित करना कि हमारे घरेलू क्षेत्र निर्यात में वृद्धि करने के उद्देश्य से किए गए मुक्त व्यापार समझौतों/क्षेत्रीय व्यापार समझौतों/प्राथमिक व्यापार समझौतों का उल्लंघन नहीं हुआ है।

8. अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सम्पूर्ण विदेशी व्यापार श्रृंखला से संबंधित वास्तविक और आभासी दोनों के बुनियादी नेटवर्क को विकसित करना।

9. व्यापार बोर्ड की भूमिका को पुनः परिभाषित करके इसे पुनः जीवित, करना, इसे उचित मान्यता देना तथा व्यापार नीति में विशेषज्ञों को शामिल करना।

10. हमारे निर्यात रणनीति में हमारे दूतावासों को मुख्य भूमिका निभाने के लिए गतिशील बनाना और विदेश में हमारे वाणिज्यिक प्रभागों को इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म से जोड़ना ताकि वास्तविक रूप से व्यापार आसूचना और पूछताछ के दायरे को बढ़ाया जा सके।

भागीदारी

नई नीति में कथित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक/व्यापारिक निर्यातक और विनिर्माता निर्यातक, व्यापार और उद्योग जगत सरकार के भागीदार हैं। लम्बे समय तक चलने वाली और अनावश्यक मुकदमेबाजी भागीदारी को बिगाड़ती है। मुकदमेबाजी की जरूरत को दूर करने के लिए सृजनात्मक और सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करने हेतु उपयुक्त शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की जाएगी, ऐसी उम्मीद की जाती है, जो मुकदमेबाजी को काफी कम करेगी और भागीदारी के रिश्ते को मजबूत बनाएगी।

उदार व्यापार प्रणाली का गति विज्ञान कई बार डम्पिंग के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को नुकसान पहुँचाता है। जब ऐसा घटित होता है तो इस नुकसान को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

प्रारूप (रोड मैप)

यह नीति भारत के विदेश व्यापार के विकास हेतु अनिवार्य प्रारूप है। हमें जिस दिशा में अग्रसर होना है उसके आधार भूत सिद्धांत और मुद्दे

इसमें शामिल हैं। कोई व्यापार नीति केवल अपने गति-विज्ञान की वजह से ही अपने सभी ब्यौरों के बावजूद पूर्णतः व्यापक नहीं हो सकती है। इसके लिए समय समय पर संशोधन करना स्वाभाविक तौर पर आवश्यक होगा। हम अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के अवश्यभावी परिवर्तनशील गति-विज्ञान पर आधारित निरन्तर अद्यतन करने के माध्यम से ऐसा करने का प्रस्ताव करते हैं। व्यापार और उद्योग जगत के साथ भागीदारी के माध्यम से हम इस प्रारूप (रोड मैप) पर कीर्तिमान स्थापित करने का प्रस्ताव करते हैं।

(कमल नाथ)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

भारत सरकार

नई दिल्ली

7 अप्रैल, 2006

अध्याय-एक (क)

विधिक ढाँचा

प्रस्तावना 1.1 प्रस्तावना में वृहत ढाँचे को इंगित किया गया है तथा यह विदेश व्यापार नीति का अभिन्न अंग है।

अवधि 1.2 विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार निर्यात एवं आयात नीति 2002-2007 यथासंशोधित को सम्मिलित करते हुए एवं आयात नीति 2004-2009 की अवधि के लिए विदेश व्यापार नीति को अधिसूचित करती है। यह नीति 1 सितम्बर, 2004 से लागू होगी तथा 31 मार्च, 2009 तक प्रभावी रहेगी, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए।

संशोधन 1.3 केन्द्रीय सरकार, अधिनियम की धारा-5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जनहित में इस नीति में संशोधन का अधिकार रखती है। ऐसे संशोधन भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से किए जाएंगे।

अन्तर्वर्ती व्यवस्था 1.4 पूर्व निर्यात/आयात नीतियों के अंतर्गत जारी की गई कोई भी व्यवस्था अधिसूचना या सार्वजनिक सूचना या अन्य व्यवस्था जो इस नीति के प्रारम्भ होने से पूर्व लागू थी, वह जब तक इस नीति के प्रावधानों में असंगत न हों, लागू रहेगी तथा उन्हें इस नीति के तहत जारी किया माना जाएगा।

इस नीति से पूर्व जारी किए गए प्राधिकार पत्र/ पत्र/प्रमाण-पत्र/अनुमत पत्र उस उद्देश्य और अवधि के लिए जिसके लिए ये प्राधिकार पत्र प्रमाण-पत्र और अनुमत पत्र जारी किए गए हैं मान्य रहेंगे जब तक अन्यथा अधिसूचित न किया गया हो।

1.5 यदि इस नीति के तहत मुक्त रूप से किए जा सकने वाले किसी निर्यात या आयात पर बाद में कोई प्रतिबंध लगाया जाता है या उसे विनियमित किया जाता है तो ऐसे प्रतिबंध या विनियमन के बावजूद सामान्यतः ऐसे निर्यात या आयात की अनुमति प्रदान की जाएगी, जब तक कि अन्यथा निर्धारित न किया गया हो, बशर्ते कि ऐसे प्रतिबंध से पूर्व स्थापित अपरिवर्तनीय साख-पत्र के प्रति ऐसे निर्यात या आयात का पोत लदान ऐसे प्रतिबंध से लागू होने की मूल वैधता अवधि के भीतर हो जाए।

अध्याय-एक (ख)**विशेष ध्यान देने योग्य पहल**

विशेष ध्यान देने योग्य पहल 1ख. 1 विश्व व्यापार में 5 वर्ष के अन्दर अपनी भागीदारी का प्रतिशत दुगना करने तथा विशेष रूप से अर्द्ध शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, हथकरघा, हस्तशिल्प, रत्न और आभूषण तथा चमड़े से बने सामान के क्षेत्रों में रोजगार का अवसर बढ़ाने कुछ विशेष ध्यान देने योग्य पहल पहचान लिए गए हैं।

भारत सरकार इन क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ाने के लिए संगठित प्रयास करेगी जिनके लिए क्षेत्र विशेष रणनीति तय करेगी जिसको समय-समय में अधिसूचित किया जाएगा।

नए क्षेत्रों में पहल की घोषणा : समय-समय पर अन्य क्षेत्रों में भी क्षेत्रीय पहलों की घोषणा की जाएगी।

अभी इन विशेष क्षेत्रों को निम्नलिखित सुविधाएं दी जाएंगी :—

(1) कृषि :

- (क) फलों, सब्जियों, फूलों, तुच्छ बन उत्पादों, दूध, मुर्गीपालन तथा उनके मूल्य वृद्धि उत्पादों के लिए विशेष कृषि उपज योजना नामक एक नई योजना बनायी गयी। (पैरा 3.8)
- (ख) कृषि निर्यात क्षेत्र (ए.ई. जैड) के विकास के लिए ए एस आई डी ई के अन्तर्गत धन दिया जाएगा।
- (ग) हटा दिया गया है।
- (घ) हटा दिया गया है।
- (ङ) ई पी सी जी के अन्तर्गत आयातित माल ए ई जैड में किसी भी स्थान में लगाने की अनुमति होगी।
- (च) प्रतिबंधित मदों जैसे कि पैन्ल, के आयात की विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के तहत अनुमति होगी।
- (छ) कृषि निर्यात के लिए अग्रिम प्राधिकारण पत्र के तहत कीटनाशक जैसे इनपुट के आयातों की अनुमति होगी।
- (ज) रु० 250 करोड़ के न्यूनतम सीमा के साथ निर्यात वृद्धि के नये कस्बों को अधिसूचित किया जाएगा।

(2) हथकरघा

- (क) हथकरघा निर्यात को बढ़ाने के लिए एम.ए. आई./एम डी ए योजना के तहत विशिष्ट निधि निर्धारित की जाएगी।
- (ख) विशिष्ट कटाई छटाई के शुल्क मुक्त आयात हकदारी पिछले वित्तीय वर्ष के निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5 प्रतिशत होगी।
- (ग) हाथ से बनाई हुई चटाई के नमूनों पर शुल्क मुक्त आयात की हकदारी पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 1 प्रतिशत होगा।
- (घ) हाथ से बनाई हुई चटाई के पुराने टुकड़ों की खेप का शुल्क मुक्त आयात का पुनः निर्यात मरम्मत के बाद अनुमत होगा।
- (ङ) रु० 250 करोड़ के न्यूनतम सीमा के साथ निर्यात वृद्धि के नये कस्बों को अधिसूचित किया जाएगा।

(च) सरकार ने निर्णय लिया है कि 'पूलमार्क' एवं 'सिल्कमार्क' की तर्ज पर एक ट्रेडमार्क विकसित किया जाएगा इससे हथकरघा उत्पादों को विशिष्ट पहचान के साथ बाजार विकसित करने में सुविधा होगी।

(3) हस्तशिल्प

- (क) नये हस्तशिल्प विशेष आर्थिक परिक्षेत्र स्थापित किए जायेंगे जो निर्यात के लिए कंटेनर क्षेत्र से खरीदे गए उत्पाद को तैयार करेंगे।
- (ख) कटाई और छटाई की शुल्क मुक्त आयात हकदारी पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की 5 प्रतिशत होगी। हकदारी ब्रांड बैडेड है जिसकी सुविधा सहायक विनिर्माताओं के साथ जुड़े व्यापारी निर्यातकों को भी दी जायेगी।
- (ग) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिपद उन निर्यातकों की तरफ से जो परोक्ष रूप से निर्यात करने में सुदृढ़ नहीं हैं के कटे हुए छटे हुए और उपभोग्यों को आयात करने के लिए प्राधिकृत होगी।
- (घ) हस्तशिल्प के प्रोत्साहन हेतु लिए एमएआई/एमडीए योजना के अधीन विशेष कोष निर्धारित किए जायेंगे।
- (ङ) शुल्क मुक्त आयात पर ट्रिमिंग इन्वेलिशमेन्ट और उपभोग्यों पर सीबीडी की छूट होगी।
- (च) रु० 250 करोड़ के न्यूनतम सीमा के साथ निर्यात वृद्धि के नये कस्बों को अधिसूचित किया जाएगा।

(4) रत्न और आभूषण :

- (क) 8 कैरेट और अधिक के सोने का आयात प्रतिभूति योजना के अधीन अनुमेय होगा बशर्ते आयात के साथ शुद्धता, भार और धातु मात्रा दर्शाता हुआ एक ऐसा प्रमाण-पत्र भी हो।
- (ख) सोना प्लेटिनम के अलावा धातुओं के लिए उपभोग्यों की शुल्क मुक्त आयात हकदारी पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 2 प्रतिशत तक होगी।
- (ग) व्यापारिक नमूनों की शुल्क मुक्त निर्यात हकदारी 300,000 रुपए होगी।
- (घ) नकार दिए आभूषणों के लिए शुल्क मुक्त पुनः आयात हकदारी निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की 2 प्रतिशत होगी।
- (ङ) कटे एवं पोलिश किए हुए रत्न और आभूषणों को आयकर अधिनियम के खण्ड-10क के अधीन छूट के उद्देश्य के लिए तैयार माल की तरह माना जाएगा।

(5) चमड़ा और जूते

- (क) विनिर्दिष्ट मदों की शुल्क मुक्त आयात हकदारी चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 5 प्रतिशत होगी।
- (ख) जूतों (चमड़ा सिंथेटिक दोनों) दस्ताने, यात्रा बैग और हैंड बैग के लिए ट्रिमिंग, इन्वेलिशमेन्ट और जूते उपांगों के आयात के लिए शुल्क मुक्त हकदारी पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 2 प्रतिशत होगी।

पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की 3 प्रतिशत होगी। हकदारी पैकिंग सामग्री, जैसे छपे हुए और बिना छपे हुए जूतों के डिब्बे, लकड़ी के छोटे कार्टन, जूतों की पैकिंग के लिए टिन या प्लास्टिक सामग्री पर भी लागू होगी।

- (ग) प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों को सीमा शुल्क से छूट होगी।
- (घ) अनुपयुक्त आयातित सामग्री जैसे की खाले एवं चमड़ा और नम नीला चमड़ा का पुनर्निर्यात अनुमेय है।
- (ङ) लीनिंग और इन्टरलीनिंग सामग्री सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 21/2002 दिनांक 1-3-2003 की क्रम सं. 168 पर अधिसूचित सीवीडी की छूट होगी।
- (च) आई डी सी (एचएस) के अध्याय 43 के अधीन आने वाले कच्चा, टैन्ड और ड्रेस रोम और चमड़े पर सी डी डी की छूट होगी।

समुद्री क्षेत्र के लिए पैकेज

- (क) विनिर्दिष्ट खास निविष्टियों रसायनों और सुगंधित तेलों आदि का शुल्क मुक्त आयात पिछले वर्ष के निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 1 प्रतिशत के बराबर अनुमत होगा।
- (ख) टूना फिशिंग के लिए मोनोफिलामेंट लॉग लाइन तंत्र के आयात को शुल्क की रियायती दरों पर अनुमत करना।
- (ग) विनिर्दिष्ट अपशिष्ट मानदण्डों को शर्तों के साथ समुद्री खाद्य अपशिष्ट की निकासी हेतु स्व-नकार प्रक्रिया लागू करना।

प्रगति मैदान के लिए इष्टतम विकास कार्यक्रम

1.ग.2 हमारी औद्योगिक और व्यापारिक उपलब्धियों का अधिकतम लाभ उठाने और मौजूदा सुविधाओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से जगह और सेवाओं में वृद्धि के लिए प्रगति मैदान को एक विश्वस्तर का काम्प्लेक्स बनाया जाएगा जो आगन्तुकों के अंतःप्रवेश और बहिर्गमन के अनुकूल होगा। काम्प्लेक्स की उपलब्ध सुविधाओं में सुधार किया जाएगा, इन्हें बढ़ाया जाएगा और इन्हें वैविध्य प्रदान किया जाएगा। वहां एक अत्यंत आधुनिक, 'स्टेट ऑफ द आर्ट' पर्यावरण नियंत्रित, वातानुकूलित प्रदर्शनी क्षेत्र और स्थाई प्रदर्शनी मार्ग्स होंगे। इसके अलावा, दस हजार शिष्टमंडलों के लिए एक बड़ा सम्मेलन केन्द्र विकसित किया जाएगा जिसमें बहुउद्देशीय और परिवर्तनीय हाल, जिनमें उच्च तकनीकी उपकरण लगे होंगे। पूरे वर्ष चलने वाले खाद्य एवं पेय रेस्त्राओं को विकसित किया जाएगा जिसमें विभिन्न किस्म और सस्ते-महंगे सभी प्रकार के पकवानों को बेचने के लिए बहुत सी दुकानें होंगी। प्रगति मैदान के अंदरूनी में नौ हजार से अधिक वाहनों को पार्क करने के लिए एक बहुस्तरीय पार्किंग स्थल होगा।

अध्याय-एक(ग)

व्यापार बोर्ड

व्यापार उद्योग बोर्ड

1.ग.1 विदेश व्यापार नीति से संबंधित मामलों में सरकार के सलाह देने के लिए व्यापार बोर्ड का पुनर्गठन किया जाएगा तथा इसे स्पष्ट और सक्रिय भूमिका दी जाएगी बांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने व भारत का निर्यात बढ़ाने के लिए व्यापार बोर्ड तथा सरकार के बीच लगातार पारस्परिक क्रिया होगी।

विचारणीय विषय

1.ग.2 व्यापार बोर्ड के निम्नलिखित विचारणीय विषय होंगे :—

- (1) बदलते हुए राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य में निर्यात को बढ़ाने के लिए अल्पकालीन व दीर्घकालीन योजना बनाने तथा इसे क्रियान्वित करने में सरकार को सलाह देना।
- (2) विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात निष्पादन की समीक्षा, नियंत्रण को पहचान तथा निर्यात अग्रिम को सर्वोत्तम करने के लिए औद्योगिक सुस्पष्ट उपाय सुझाना।
- (3) आयात व निर्यात के वर्तमान संस्थागत फ्रेमवर्क की जांच करना तथा बांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के सरल और कारगर व्यावहारिक उपाय सुझाना।
- (4) आयात निर्यात के नीति दस्तावेजों तथा प्रक्रियाओं की जांच करना तथा ऐसी योजनाओं में एकरूपता तथा चैनलाइज करने के लिए उपाय सुझाना।
- (5) भारत के विदेश व्यापार के संवर्धन से संबंधित मामलों की जांच करना तथा देश के सामान व सेवाओं के अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में मजबूत करना।
- (6) उपर्युक्त लक्ष्यों को बढ़ाने के लिए अध्ययन करना।

संयोजन

1.ग.3 सरकार व्यापार नीति में विशेषज्ञ अथवा प्रसिद्ध व्यक्ति को व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करेगी। सरकार अन्य 25 व्यक्तियों को भी नामित करेगी जिनमें 10 व्यक्ति व्यापार नीति में विशेषज्ञता प्राप्त होंगे। इसके अलावा मान्यताप्राप्त निर्यात संवर्धन परिपद् का चेयरमैन तथा पदेन सदस्यों को राष्ट्रीय चैम्बर्स ऑफ कामर्स का अध्यक्ष अथवा महासचिव नियुक्त करेगी।

बैठकें

1.ग.4 बोर्ड की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार आयोजित की जाएगी तथा रखे गए मुद्दों की मर्दों के सन्दर्भ में बोर्ड सरकार को सिफारिश को भेजेगा।

उप समिति

1.ग. 5 व्यापार बोर्ड को सह-समिति बनाने का अधिकार होगा और विशेष क्षेत्रों तथा उद्देश्यों पर सिफारिशों को बनाने के लिए विशेषज्ञों को कार्यरत करने का अधिकार होगा।

सचिवालय और बजट शीर्ष

1.ग.6 व्यापार बोर्ड का एक सचिवालय और बजट शीर्ष होगा तथा इसकी सेवाएं वाणिज्य विभाग के अन्तर्गत आएंगी।

अध्याय दो

निर्यात एवं आयात से संबंधित सामान्य प्रावधान

आयात और निर्यात मुक्त जब तक कि विनियमित न हो

2.1 निर्यात और आयात उन मामलों को छोड़कर जहां वे इस नीति के प्रावधानों अथवा तत्समय लागू अन्य कानूनों द्वारा विनियमित होते हैं, मुक्त होंगे। मदबाद निर्यात और आयात नीति, समय-समय पर

यथा संशोधित विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा प्रकाशित और अधिसूचित 'आई टी सी (एच एस)' में विनिर्दिष्ट के अनुसार होगी।

कानून का अनुपालन

2.2 प्रत्येक निर्यातक या आयातक को, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों, इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों और आदेशों, इस नीति के प्रावधानों तथा उसको दिए गए लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति की शर्तों और उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा। सभी आयातित माल भी देशी उत्पादित माल पर यथा लागू स्वदेशी कानूनों, नियमों, विनियमों, तकनीकी विनिर्देशनों, पर्यावरण और सुरक्षा मानदण्डों के अधीन होंगे। रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के तहत आवश्यक किम्बरलै प्रोसेस (केपी) प्रमाणपत्र जब तक पोतलदान पार्सल के साथ संलग्न न हो, अनगढ़े हीरों को आयात अथवा निर्यात अनुमत नहीं होगा।

नीति की व्याख्या

2.3 आई टी सी (एच एस) अथवा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1), अथवा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-2) अथवा डी ई पी बी दर की अनुसूची में किसी मद के वर्गीकरण, के संबंध में या इस नीति में दिए गए किसी भी प्रावधान के स्पष्टीकरण के बारे में यदि किसी भी प्रकार का प्रश्न अथवा शंका उत्पन्न होती है तो ऐसे प्रश्न अथवा शंका को महानिदेशक, विदेश व्यापार को भेजा जाएगा तथा उनका निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।

किसी लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति पत्र की नीति अनुसार जारी होने के विषय में कोई शंका या प्रश्न उठने पर अथवा ऐसे दस्तावेजों की आवश्यकता और अंश पर किसी प्रश्न अथवा शंका के उठने पर उन दस्तावेजों को महानिदेशक, विदेश व्यापार महानिदेशालय के पास भेजा जाएगा जिनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

प्रक्रिया

2.4 महानिदेशक, विदेश व्यापार किसी एक मामले में अथवा मामलों की श्रेणी में किसी भी आयातक अथवा निर्यातक या अन्य लाइसेंसिंग अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनाने हेतु इस अधिनियम के प्रावधानों, इसके अधीन बने आदेशों तथा इस नीति को लागू करने के उद्देश्य से कोई विशेष प्रक्रिया निर्धारित कर सकते हैं। ऐसी प्रक्रिया, प्रक्रिया पुस्तक (भाग-1), प्रक्रिया पुस्तक (भाग-2), डी ई पी बी दर की अनुसूची और आईटीसी (एच एस) में सम्मिलित होगी तथा सार्वजनिक सूचना के माध्यम से प्रकाशित होगी। ऐसी प्रक्रियाओं को, इसी प्रकार, समय-समय पर संशोधित किया जाएगा।

प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) विदेश व्यापार नीति की अनुपूरक है तथा इसमें समबद्ध प्रक्रियाओं और अन्य व्यौरों का उल्लेख है। नीति की विभिन्न स्कीमों के तहत उपलब्ध लाभों को प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में दिया गया है।

नीति/प्रक्रिया से छूट

2.5 इस नीति अथवा किसी प्रक्रिया के प्रावधानों में ढील प्राप्त करने के लिए इस आधार पर किया गया अनुरोध कि आवेदक को वास्तव में कठिनाई है अथवा नीति या प्रक्रिया को कड़ाई से लागू करने

पर व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो तो उसे आवश्यक छूट के लिए महानिदेशक, विदेश व्यापार के पास भेजा जा सकता है। उस पर महानिदेशक ऐसा आदेश या ऐसी छूट या राहत जैसा भी उचित या समुचित हो, दे सकते हैं।

महानिदेशक, विदेश व्यापार लोकहित में किसी भी व्यक्ति या वर्ग या व्यक्तियों की श्रेणी को इस नीति के किसी प्रावधान से या किसी प्रक्रिया से छूट दे सकते हैं या ऐसी छूट देते समय वह ऐसी शर्तें लगा सकते हैं जैसा कि वह उचित समझे। यदि वह अनुरोध नीति/प्रक्रिया के अध्याय-4 (रत्न और आभूषण क्षेत्र से संबंधित किसी प्रावधान को छोड़कर) के प्रावधानों के बारे में हो तो ऐसे अनुरोधों पर केवल अग्रिम लाइसेंसिंग समिति से सलाह लेकर यदि अनुरोध नीति/प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय-5 के प्रावधान के सम्बन्ध में है तो ई पी सी जी समिति से सलाह लेकर ही विचार किया जाए। तथापि अध्याय-4, अध्याय-5 और रत्न और आभूषण क्षेत्र से भिन्न प्रावधानों के संबंधों में ऐसे किसी अनुरोध पर केवल नीति छूट समिति की सलाह लेने के बाद ही विचार किया जाएगा।

प्रतिबंध के सिद्धान्त

2.6 विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निम्नलिखित हेतु कोई भी आवश्यक उपाय अपनाया और लागू किया जा सकता :-

- (1) सार्वजनिक आचरण का संरक्षण।
- (2) मानव, जानवर अथवा पादप जीवन अथवा स्वास्थ्य का संरक्षण।
- (3) पेटेंट, ट्रेडमार्क और कापीराइट का संरक्षण और भ्रामक कृत्यों की रोकथाम।
- (4) कारागार श्रमिकों के प्रयोग की रोकथाम।
- (5) कला, इतिहास अथवा पुरातत्व मूल्य की राष्ट्रीय धरोहर का संरक्षण।
- (6) क्षयशील प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण।
- (7) विखण्डनीय सामग्री अथवा जिससे वह प्राप्त की गई है, के व्यापार का संरक्षण, और
- (8) हथियारों, गोला-बारूद और युद्ध के साज-सामान के व्यापार की रोकथाम।

प्रतिबंधित माल

2.7 कोई भी माल जिसका आई टी सी (एच एस) के अधीन निर्यात अथवा आयात प्रतिबंधित किया गया है, उसका इस संबंध में जारी किए गए लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति या इस सम्बन्ध में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार ही निर्यात अथवा आयात किया जा सकेगा।

लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति की शर्तें

2.8 प्रत्येक लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति/प्राधिकार पत्र विनिर्दिष्ट वैधता अवधि के लिए वैध होगा तथा लाइसेंस/प्रमाणपत्र में दी गई शर्तें, लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट होगी तथा इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :-

1. माल की मात्रा, विवरण एवं मूल्य,
2. वास्तविक प्रयोक्ता शर्त,

3. निर्यात दायित्व,
4. प्राप्त किया जाने वाला मूल्य संवर्धन,
5. न्यूनतम निर्यात मूल्य।

लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति अधिकार नहीं

2.9 कोई भी व्यक्ति लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति को अधिकार से नहीं ले सकता है तथा महानिदेशक, विदेश व्यापार या लाइसेंसिंग प्राधिकारी को, अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति पत्र/प्राधिकार पत्र देने से इंकार करने या नवीकरण नहीं करने का अधिकार होगा।

जुमाना

2.10 यदि लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति धारक लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति/प्राधिकार पत्र की किसी शर्त का उल्लंघन करता है या निर्यात दायित्व को परा नहीं कर पाता है, तो उसे इस नीति के तहत बनाए गए अधिनियम, नियमों और आदेशों तथा उस समय लागू किसी अन्य नियम के अनुसार दंडित किया जा सकता है।

राज्य व्यापार

2.11 कोई माल, जिसके आयात अथवा निर्यात के लिए राज्य व्यापार उद्यमों को विशेषाधिकार दिया गया हो अथवा जिनके माध्यम से विशेष रूप से विनियमित किया गया हो, राज्य व्यापार उद्यम (उद्यमों) द्वारा आई टी सी (एच एस) नामक पुस्तक में यथा-विनिर्दिष्ट अनुसार उस माल का आयात या निर्यात किया जा सकता है बशर्ते कि वह उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन हो। तथापि विदेश व्यापार महानिदेशक, इनमें से किसी माल के आयात या निर्यात के लिए किसी अन्य व्यक्ति को लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति/प्राधिकार पत्र दे सकता है।

ऐसे माल के सम्बन्ध में, जिसके लिए राज्य व्यापार उद्यमों को विशेषाधिकार मंजूर किया गया हो, अथवा विशेष रूप से विनियमित किया गया हो, राज्य व्यापार उद्यम वाणिज्यिक दृष्टिकोण के अनुसार जिसमें कौमत्, गुणवत्ता, उपलब्धता, विपणनता, परिवहन तथा क्रय विक्रय की अन्य शर्तें शामिल हैं, ऐसी कोई अन्य खरीद या विक्रय कर सकता है जिसमें आयात और निर्यात शामिल हैं। ये उद्यम किसी भेदभाव के बिना कार्य करेंगे और ऐसी खरीद और विक्रय में भाग लेने हेतु सक्षम होने के लिए प्रचलित व्यापार प्रथा के अनुसार प्राप्त सुविधाओं वाले देशों के उद्यमों के साथ ताल-मेल बिठाएंगे।

आयातक-निर्यातक कोड संख्या

2.12 जब तक विशेष छूट नहीं दी जाती किसी भी व्यक्ति द्वारा आयातक निर्यातक कोड नम्बर (आई ई सी) के बिना किसी माल का निर्यात या आयात नहीं किया जाएगा। आयातक-निर्यातक कोड नम्बर प्रक्रिया पुस्तक (भाग-1) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन के आधार पर मंजूर किया जाएगा।

पड़ोसी देशों के साथ व्यापार

2.13 महानिदेशक विदेश व्यापार समय-समय पर आवश्यकता पड़ने पर ऐसे अनुदेश जारी कर सकते हैं अथवा ऐसी योजनाएं बना सकते हैं जो पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने और आर्थिक संबंध मजबूत करने के लिए अपेक्षित हों।

माल लाने ले-जाने की सुविधा

2.14 भारत के पड़ोसी देशों को माल भेजने या वहां से लाने की सुविधा भारत और इन देशों के बीच हुई द्विपक्षीय अधियों के अनुसार विनियमित होगी तथा अन्तर्गम्य समझौतों के अनुसार विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिबंधों के अधीन होगी।

ऋण की पुनः अदायगी करार के तहत रुकने वाला माल

2.15 ऋण की पुनः अदायगी करार के तहत रुकने वाला माल व्यापार के मामले में, महानिदेशक, विदेश व्यापार समय-समय पर आवश्यकता अनुसार ऐसे अनुदेश जारी कर सकते हैं अथवा स्कीम बना सकते हैं जो अपेक्षित हों तथा इस नीति में दिया गया कुछ भी उन अनुदेशों अथवा स्कीमों के अनुरूप नहीं है, लागू नहीं होगा।

वास्तविक प्रयोक्ता शर्त

2.16 पूंजीगत माल, कच्चा माल, मध्यम, प्रशोधित, उपभोग्य पदार्थ, अतिरिक्त पुर्जे, हिस्से पुर्जे उपसाधित्र यंत्र और अन्य सामान जिनके आयात पर प्रतिबंध नहीं है उनका आयात किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है।

तथापि, यदि इनके आयात के लिए लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति पत्र की जरूरत हों, तो केवल वास्तविक प्रयोक्ता ही ऐसे माल का आयात कर सकता है बशर्ते कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा यह शर्त समाप्त न कर दी गई हो।

पुरानी वस्तुएं

2.17 सभी पुरानी वस्तुएं आयात हेतु प्रतिबंधित होंगी तथा उन्हें इस नीति के प्रावधानों, आई टी सी (एच एस), प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड 1), सार्वजनिक सूचना या इस संबंध में जारी लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति पत्र/प्राधिकार पत्र के अनुसार उनका आयात किया जा सकता है।

पुनः फरबिसड/पुनः प्रशोधित पुर्जे सहित पुराने पूंजीगत माल का आयात मुक्त रूप से होगा तथापि पुराने व्यक्तिगत कम्प्यूटर/लैपटॉप, फोटोकॉपी मशीन, प्रशोधित, डीजल जनरेटिंग सैट का आयात लाइसेंस के मद्दे किया जाएगा।

पुरानी वस्तुएं जिसमें रिफरबिशड/रिकंडीशंड स्पेयरस भी शामिल हैं, के मुक्त रूप से आयात की अनुमति है।

नमूनों का आयात

2.18 नमूनों का आयात प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाएगा।

उपहारों का आयात

2.19 इस नीति के अधीन जहां ऐसा माल अन्यथा मुक्त रूप से आयात किया जा सकता हो, उपहारों के आयात की अनुमति होगी। अन्य मामलों में सीमाशुल्क निकासी (सीसीपी) की अनुमति महानिदेशक, विदेश व्यापार से प्राप्त करनी होगी।

यात्री असबाब

2.20 वस्तुतः घरेलू वस्तुओं और निजी प्रयोग की वस्तुओं को यात्री के निजी सामान की सीमा के अनुसार वाणिज्य मंत्रालय द्वारा

अधिसूचित असबाब नियमों में उनकी शर्तों के अनुसार आयात किया जा सकता है।

ऐसी मदों के नमूने जो अन्यथा इस नीति के अधीन मुक्त रूप से आयात योग्य हैं, का भी लाइसेंस/प्रमाण-पत्र/अनुमति पत्र/प्राधिकार पत्र के बिना वैयक्तिक असबाब के रूप में आयात किया जा सकता है।

विदेश से आने वाले निर्यातकों को भी, लाइसेंस/प्रमाण-पत्र/अनुमति पत्र/प्राधिकार के बिना, अपने वैयक्तिक असबाब के रूप में, उनके पास आए विशिष्ट निर्यात आर्डरों के लिए अपेक्षित ड्राइंग, पैटर्न्स, लैबल्स, प्राइस टैग्स, बटन्स, बैल्ड्स, ट्रिमिंग और एम्बेलिशमेंट्स का आयात करने की अनुमति है।

निर्यात आधार पर आयात

2.21 नया अथवा पुराना पूंजीगत माल, उपकरण, संघटक, हिस्से एवं उपकरणों, कंटेनर जो निर्यात हेतु माल के पैकिंग के लिए हों उनका सीमाशुल्क प्राधिकारियों के साथ विधिक बचनबद्धता/बैंक गारंटी के निष्पादन पर किसी लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति/प्राधिकार पत्र के बिना निर्यात के लिए आयात किया जा सकता है। बशर्ते कि मद को बिना किसी शर्त/लाइसेंस/अनुमति की आवश्यकता के मुक्त रूप से निर्यात किया जा सकता हो जैसा कि आई टीसी (एचएस) अनुसूची-2 के अन्तर्गत अपेक्षित है।

विदेश में मरम्मत की गई वस्तुओं का पुनः आयात

2.22 आई टी सी (एच एस) के तहत प्रतिबंधित को छोड़कर पूंजीगत माल, उपकरण संघटक अतिरिक्त पुर्जों, अनुसंगी चाहे आयातित हो या स्वदेशी, उनकी मरम्मत, परीक्षण गुणवत्ता सुधार या टेक्नोलॉजी में सुधार अथवा मानकीकरण के लिए किसी लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति/प्राधिकार पत्र के बिना विदेश भेजा जा सकता है और उनका पुनः आयात किया जा सकता है।

विदेश में परियोजनाओं में प्रयुक्त सामान का आयात

2.23 विदेश में परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बाद परियोजना ठेकेदार पूंजीगत माल सहित प्रयुक्त माल का किसी लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति के बिना आयात कर सकता है, बशर्ते कि इनका कम से कम एक वर्ष तक इस्तेमाल किया गया हो।

खुले समुद्र में बिक्री

2.24 भारत में आयात हेतु समुद्र में वस्तुओं की बिक्री इस नीति अथवा उस समय प्रभावी किसी अन्य नियम के तहत की जा सकती है।

पट्टा वित्त प्रबन्ध के अधीन आयात

2.25 पट्टा वित्त प्रबन्ध के अधीन नई पूंजीगत वस्तुओं के आयात हेतु लाइसेंसिंग प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक नहीं है।

सीमाशुल्क से माल की निकासी

2.26 वह माल जो पहले ही आयातित/पोतलदान/पहुँच गया हो लेकिन सीमाशुल्क से उसकी निकासी न हुई हो उस माल को बाद में जारी लाइसेंस/प्रमाण-पत्र/अनुमति के प्रति निकासी की जा सकती है।

बैंक गारंटी/विधिक बचनबद्धता का निष्पादन

2.27 जहां कहीं शुल्क मुक्त आयात की अनुमति है या जहां कहीं अन्यथा विनिर्दिष्ट किया गया है, वहां आयातक को सीमाशुल्क प्राधिकारी के साथ वस्तुओं की निकासी से पूर्व सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास यथानिर्धारित तरीके से एक विधिक बचनबद्धता/बैंक गारंटी का निष्पादन करना होगा। स्वदेशी प्राप्ति पत्र/अनुमति धारक को स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं/नामजद अधिकरणों से माल प्राप्त करने से पूर्व लाइसेंस प्राधिकारी के पास बैंक गारंटी/विधिक बचनबद्धता को प्रस्तुत करना होगा।

बैंक गारंटी से छूट

2.27.1 इस नीति के तहत उन सभी निर्यातकों, जिनका कारोबार चालू वित्तीय वर्ष तथा उससे पहले लाइसेंसिंग वर्ष में न्यूनतम 5 करोड़ का रहा तथा जिसके निर्यातों का तीन वर्षों का रिकार्ड अच्छा हो, को बैंक गारंटी के निष्पादन से मुक्त किया गया है तथा वे उस नीति की किसी भी योजना के तहत बैंक गारंटी के बदले विधिक बचनबद्धता प्रस्तुत कर सकते हैं।

आयात के लिए निजी/सार्वजनिक बांडेड गोदाम

2.28 राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना की शर्तों के अनुसार, घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निजी/सार्वजनिक बांडेड गोदाम बनाए जा सकते हैं।

कोई भी व्यक्ति निषिद्ध मदों, हथियार और गोला-बारूद या खतरनाक अपशिष्टों और रसायनों को छोड़कर किसी भी वस्तु का आयात कर सकता है तथा उन्हें ऐसे निजी/सार्वजनिक बांडेड गोदामों में रख सकता है।

ऐसी वस्तुओं की इस नीति के प्रावधानों के अनुसार और जहां कहीं जरूरी हो, लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति-पत्र के प्रति घरेलू खपत के लिए निकासी की जा सकती है।

ऐसे माल पर निकासी के साथ यथा लागू सीमाशुल्क का भुगतान किया जाएगा।

एक वर्ष की अवधि अथवा बढ़ाई गई अवधि में, जिसकी अनुमति सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा दी जाती है, यदि घरेलू खपत के लिए ऐसी वस्तुओं की निकासी नहीं की जाती तो इनका आयातक इन वस्तुओं का पुनः निर्यात कर सकता है।

मुक्त निर्यात

2.29 आयात और निर्यात की आई.टी.सी. (एच एस) या इस नीति के किसी अन्य प्रावधान या तत्समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा विनियमित न होते हों तो सभी निर्यात बिना किसी प्रतिबंध के किया जा सकेगा।

तथापि, महानिदेशक विदेश व्यापार एक सार्वजनिक सूचना के जरिए उन शर्तों को निर्धारित कर सकते हैं जिनके अनुसार आं टी सी (एच एस) में शामिल न की गई किसी वस्तु का लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति के बिना निर्यात किया जा सकता है।

नमूनों का निर्यात

2.30 नमूनों और निःशुल्क वस्तुओं का निर्यात प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में उल्लिखित प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

यात्री असबाब का निर्यात

2.31 बाहर जाने वाले भारतीय यात्रियों के वस्तुतः निजों सामान को या तो यात्रियों के साथ ही अथवा यदि साथ न ले जाना हो तो भारत से यात्री के प्रस्थान के पहले या बाद में एक वर्ष के अन्दर ले जाने की अनुमति है। तथापि, आई टी सी (एच एस) में प्रतिबंधित तौर पर उल्लिखित मदों के लिए लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति प्राधिकार पत्र लेना जरूरी होगा।

उपहारों का निर्यात

2.32 किसी एक लाइसेंसिंग वर्ष में खाद्य मदों सहित 5,00,000/- रुपये तक के मूल्य की वस्तुओं का निर्यात उपहार स्वरूप किया जा सकता है।

तथापि, निर्यात की आई टी सी (एच एस) में निषेधात्मक सूची की मदों को उपहार के तौर पर बिना लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति के निर्यात नहीं किया जा सकता।

अतिरिक्त पुर्जों का निर्यात

2.33 आई टी सी (एच एस) के तहत प्रतिबंधित मदों के अलावा संयंत्र, उपस्कर, मशीनरी, आटोमोबाइल अथवा किसी अन्य माल के स्वदेशी अथवा आयातित वारण्टी अतिरिक्त पुर्जों का निर्यात ऐसे माल की वारण्टी अवधि के भीतर मुख्य उपस्कर के साथ या बाद में, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के मद्दे निर्यात किया जा सकता है।

तीसरा पक्ष निर्यात

2.34 नीति के अध्याय 9 में यथापरिभाषित अनुसार तीसरे पक्ष द्वारा निर्यात की अनुमति होगी।

आयातित वस्तुओं का निर्यात

2.35 इस नीति के अनुसार आयातित माल का बिना किसी लाइसेंस/प्रमाण-पत्र/अनुमति/प्राधिकार पत्र के उसी रूप में या वास्तव में उसी रूप में निर्यात किया जा सकता है बशर्ते आयात या निर्यात की जाने वाली मद विशेष आयात लाइसेंस या निर्यात की निषेधात्मक सूची के अन्तर्गत आयातित मदों को छोड़कर आई टी सी (एच एस) में आयात की प्रतिबंधात्मक सूची या निर्यात की प्रतिबंधात्मक सूची में शामिल न हो।

मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान के प्रति आयातित ऐसी वस्तुओं के निर्यात मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान के प्रति अनुमत होंगे।

2.36 आई टी सी (एच एस) में निर्यात अथवा आयात की प्रतिबंधित मदों के तौर पर उल्लिखित मदों (निषिद्ध मदों को छोड़कर) का आयात सीमाशुल्क बॉण्ड के तहत मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में लाइसेंस प्रमाणपत्र/अनुमति के बिना किया जा सकता है बशर्ते कि मद

को बिना किसी शर्त/लाइसेंस/अनुमति की आवश्यकता के मुक्त रूप से निर्यात किया जा सकता हो जैसा कि आई टी सी (एच एस) अनुसूची 2 के अन्तर्गत अपेक्षित है।

प्रतिस्थापन माल का निर्यात

2.37 निर्यात करते समय यदि कोई माल या उसके हिस्से दोषपूर्ण/टूटे-फूटे अथवा अन्यथा प्रयोग के अयोग्य पाये जाएं तो उनका प्रतिस्थापन निर्यातक द्वारा निःशुल्क किया जाएगा और इस प्रकार के माल की सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निकासी निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा सकेगी, बशर्ते कि प्रतिस्थापन माल आई टी सी (एच एस) में निर्यात हेतु प्रतिबंधित मदों के तौर पर उल्लिखित न हो।

मरम्मत किए गए सामान का निर्यात

2.38 निर्यात करते समय आई टी सी (एच एस) के तहत प्रतिबंधित को छोड़कर कोई माल या उसके हिस्से दोषपूर्ण, टूटे-फूटे या अन्यथा उपयोग के लिए अयोग्य पाये जायें तो मरम्मत के लिए उनका आयात किया जा सकता है और बाद में पुनः निर्यात किया जा सकता है। ऐसे सामान को लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति के बिना और समय-समय पर इस संबंध में जारी सीमाशुल्क अधिसूचना के अनुसार निकासी की अनुमति होगी।

निर्यात के लिए निजी बाण्डेड गोदाम

2.39 राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं की शर्तों के अनुसार विशेषतया निर्यात के लिए डी टी ए में निजी बाण्डेड गोदाम की स्थापना की जाए।

ऐसे गोदाम सीमाशुल्क का भुगतान किए बिना स्वदेशी विनिर्माताओं से माल खरीदने के पात्र होंगे। अधिसूचित गोदामों को स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा की गई आपूर्ति को वास्तविक निर्यात माना जाएगा बशर्ते की उसका भुगतान मुक्त विदेशी मुद्रा में किया गया हो।

निर्यात संविदाओं का कोटिकरण

2.40 सभी निर्यात संविदाओं और बीजकों को मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा के वर्ग में रखा जाएगा परन्तु निर्यात प्राप्तियां मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में वसूल की जाएंगी।

तथापि विशेष निर्यातों के प्रति निर्यात प्राप्तियां रुपयों में भी वसूल की जा सकती है बशर्ते कि यह ए सी यू के सदस्य देश या नेपाल या भूटान को छोड़कर किसी भी देश में स्थित अप्रवासी बैंक के मुक्त रूप से परिवर्तनीय बोस्ट्रो खाते के जरिए हों। इसके साथ बोस्ट्रो खाते के जरिए रुपये का भुगतान क्रेता द्वारा उसके अप्रवासी बैंक खाते में मुक्त विदेशी मुद्रा में भुगतान के प्रति हो। इस कारोबार के सम्बन्ध में क्रेता द्वारा उसके अप्रवासी बैंक (बैंक सेवा प्रभार को घटाने के बाद) दी गई मुक्त विदेशी मुद्रा इस नीति की निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत निर्यात वसूली के रूप में मानी जाएगी।

जिन संविदाओं के लिए भुगतान एशियन क्लयरिंग यूनियन (ए सी यू) के जरिए किए जाएंगे उन्हें ए सी यू डालर के वर्ग में रखा जाएगा। केन्द्रीय सरकार उपयुक्त मामलों में इस पैराग्राफ के प्रावधानों से छूट दे सकती है। एक्जिम बैंक/भारत सरकार लाइन ऑफ क्रेडिट के प्रति निर्यात ठेके और बीजक भारतीय रुपयों में किए जा सकते हैं।

निर्यात प्राप्तियों की वसूली

2.41 यदि कोई निर्यातक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर निर्यात आय वसूल नहीं कर सकता है तो ऐसी स्थिति में, उस समय लागू किसी कानून के अन्तर्गत किसी दायित्व या दण्ड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसके विरुद्ध अधिनियम, नियमों और उसके अंतर्गत जारी किए गए आदेशों और नीति के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

निर्यात वस्तुओं की मुक्त आवाजाही

2.42 किसी भी केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के अधिकरण द्वारा निर्यात हेतु अनुमत मर्दों की खेप को किसी भी कारण से रोका/विलम्बित नहीं किया जाएगा। किसी भी संदेह कि स्थिति में संबंधित प्राधिकारी, निर्यातक से वचनबद्धता की मांग कर सकता है।

स्टॉक को जब्त न करना

2.42.1 किसी भी अधिकरण द्वारा स्टॉक को जब्त नहीं किया जाएगा ताकि विनिर्माण संबंधी कार्यकलापों और निर्यात वस्तुओं की सुपुर्दगी की तारीख में बाधा न डाली जा सके। कुछ खास मामलों में, संबंधित अधिकरण प्रथम दृष्टया प्रमाण के आधार पर स्टॉक को जब्त कर सकती है। तथापि, इस प्रकार जब्त किए गए माल को 7 दिन के भीतर छोड़ना होगा।

निर्यात संवर्धन परिषद

2.43 निर्यात संवर्धन परिषदों का मूल उद्देश्य देश के निर्यात को बढ़ावा देना और उसमें वृद्धि करना है। प्रत्येक परिषद विशेष वर्ग के उत्पाद परियोजनाओं और सेवाओं के संवर्धन के लिए जिम्मेदार है। निर्यात संवर्धन परिषदों की सूची तथा उनका मुख्य कार्य प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में दिया गया है।

पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाणपत्र

2.44 कोई भी व्यक्ति जो आयात निर्यात के लिए (1) लाइसेंस/प्रमाण-पत्र/अनुमति पत्र [आई टी सी(एच एस) में सूचीबद्ध/प्रतिबंधित मर्दों के अतिरिक्त] (2) किसी अन्य लाभ या इस नीति के अन्तर्गत किसी अन्य छूट के लिए आवेदन करता है तो उसको प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण सह-सदस्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा बशर्ते कि इस सम्बन्ध में विशेष रूप से उसे छूट न दी गई हो।

2.45 हटा दिया गया है।

ई डी आई पहल के जरिये व्यापार सुविधा

2.45.1 विदेश व्यापार महानिदेशालय की कोशिश अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों को अमल में लाने हुए व्यापार दस्तावेजों के अधिकतम सरलीकरण, मानकीकरण और सामंजस्य प्राप्त करने के लिए काम करना है। इस दिशा में विदेश व्यापार महानिदेशालय दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज करने, उन्हें पुनः प्राप्त करने और दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की और कदम बढ़ा रहा है जो सीमाशुल्क और बैंकों सहित अन्य समुदाय के साथ संदेश के आदान-प्रदान और सहमत प्रोटोकाल पर आधारित है।

डी जी सी आई और एस वाणिज्यिक व्यापार डाटा

2.45.2 प्रयोक्ताओं को पेशेवर ढंग से वाणिज्यिक निर्णय लेने के योग्य बनाने हेतु, डी जी सी आई और एस व्यापार डाटा को व्यवसायिक दृष्टिकोण से संरचना के प्रारूप पर आधारित न्यूनतम समय अन्तराल वाले अनुयोग उपलब्ध किए जाएंगे।

ई डी आई पहल अनुकूलन के उन्नयन हेतु वित्तीय प्रोत्साहन

2.45.3 सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहन के दृष्टिकोण से, विदेश व्यापार महानिदेशालय प्रयोक्ता समुदाय को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगा। ब्यौरा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में वर्णित है।

निपटान आयोग के जरिए निर्यात दायित्व चूक का विनियमीकरण और सीमाशुल्क और ब्याज का निपटान

2.46 ऐसी फर्मों को सहायता प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए जिन्होंने ऐसे कारणों को कि उनके नियंत्रण में नहीं थे, के लिए विदेश व्यापार नीति के तहत भुगतान नहीं किए हैं और कमजोर इकाइयों के विलयन, अर्जन और पुनर्वास को सरल बनाने के लिए 01-04-2005 से ऐसे मामलों का निर्णय लेने के लिए उत्पाद एवं सीमाशुल्क केन्द्रीय बोर्ड में निपटान आयोग बनाने को सशक्त बनाने का निर्णय लिया गया है।

दस्तावेज अपेक्षाओं का सरलीकरण

2.47 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एकल सामान्य दस्तावेज को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया लंबित होने के कारण निर्यात-आयात से झूल करने वाले सरकारी विभाग जहाजरानी बिल, बैंक प्राप्ति प्रमाण-पत्र, पैकिंग सूची, लदान बिल आदि जैसे निर्यात दस्तावेजों की जांच के आधार पर अन्य सरकारी विभागों द्वारा जारी अनुमति/लाइसेंस/प्रमाण-पत्र को स्वीकार करेंगे और इन दस्तावेजों को नए सिरे से प्रस्तुत करने के लिए जोर नहीं देंगे।

डी टी ए में सेवा कर की वापसी

2.48.1 सभी माल और सेवाओं पर, जो घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र की यूनिटों से तथा ई ओ ए/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटों से निर्यात की गयी है, लगाए गए सेवा कर से छूट की अनुमति दी जाएगी।

एस ई जेड में सेवा कर से छूट

2.48.2 एस ई जेड में यूनिटों को सेवा कर से छूट दी जाएगी।

शिकायत निवारण

निर्यात/आयात के सुविधा प्रदान कर्ता के रूप में विदेश व्यापार महानिदेशालय

2.49 विदेश व्यापार महानिदेशालय निर्यातों और आयातों के सुविधाकारक के रूप में कार्य करने को वचनबद्ध है। हमारा केन्द्र बिन्दु सही संचालन पर है जो कि स्पष्ट, पारदर्शी और उत्तरदायी निकासी प्रणालियों पर निर्भर करता है।

सिटिजन चार्टर

2.49.1 विदेश व्यापार महानिदेशालय का एक सिटीजन चार्टर है जिसमें कि आयातकों और निर्यातकों के प्रति इसकी वचनबद्धता दर्शाई

गई है। इसमें ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए समय सूची भी दी गई है और विभिन्न स्तरों पर शिकायत समितियों के विवरण दिए गए हैं।

शिकायत निवारण प्रणाली

2.49.2 नीति और प्रक्रिया से संबंधित व्यापार और उद्योग की शिकायतों के तीव्र सुधार को आसान बनाने के लिए सरकारी संकल्प द्वारा एक शिकायत निवारण प्रणाली गठित की गई है।

सरकार देरी को माफ करने के वास्तविक मामलों में निर्यातकों द्वारा उल्लंघन को विनियमित करने, हकदारी पर उठे विवाद को सुलझाने, लाइसेंसों के प्रयोग हेतु विस्तार की स्वीकृति आदि के लिए 27-10-2004 को स्थापित शिकायत निवारण समिति के माध्यम से पिछली नीति से सम्बन्धित सभी शेष समस्याओं और विवादों को समाधान करने के लिए वचनबद्ध है।

2.49.3 हटा दिया गया है।

अध्याय—तीन

संवर्धनात्मक उपाय

निर्यातों के मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु राज्यों को सहायता (ए एस आई डी ई)

3.1 राज्य सरकारों को अपने राज्यों हेतु निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस उद्देश्य हेतु वाणिज्य विभाग ने एक योजना बनाई है जिसको ए.एस.आई.डी.ई. कहा जाता है।

राज्यों को राशि आबंटित करने के लिए वाणिज्य विभाग ने वार्षिक योजना में सकल निर्यात तथा निर्यात में बढ़ोत्तरी के दर के दोहरे मानक के आधार पर उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं।

राज्य इस राशि को मूलभूत ढांचे के विकास हेतु उपयोग करेगा जैसे कि उत्पादन केन्द्रों को पत्तों के साथ जोड़ने के लिए सड़क बनाना, इनलैण्ड कन्टेनर डिपो और कन्टेनर फ्रेट स्टेशन्स को स्थापित करना, नए राज्य स्तर के निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों/जोनों की संरचना और मौजूदा जोनों में सामान्य सुविधाओं को बढ़ाना, मूलभूत ढांचे की परियोजनाओं में इक्विटी भागीदारी, लघु पत्तों और घाटों का विकास, सामान्य बहिष्काव संशोधन सुविधाओं की स्थापना में सहायता करना, ऊर्जा आपूर्ति का स्थायीकरण करना तथा वाणिज्य विभाग द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित किन्हीं अन्य गतिविधियों में भाग लेना।

बाजार पहुंच की पहल (एमएआई)

3.2 बाजार पहुंच की पहल (एमएआई) योजना मध्यम स्तर के निर्यात संवर्धन प्रयत्नों के लिए है जिसमें देशों तथा उत्पाद पर खास बल दिया जाएगा।

वित्तीय सहायता निर्यात संवर्धन परिपदों, उद्योग और व्यापार एसोसिएशनों, राज्य सरकार की एजेंसियों, विदेशों में भारतीय वाणिज्यिक मिशनों तथा अन्य पात्र हस्तियों, जिनको समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा, के लिए उपलब्ध है।

एम.ए.आई. योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यकलापों को वित्तीय सहायता दी जा सकती है। जिसमें बाजार का अध्ययन, शोरूम/गोदाम

सुविधाएं स्थापित करना, बिक्री संवर्धन मुहिम, अन्तर्राष्ट्रीय डिपार्टमेंटल स्टोर, प्रचार मुहिम, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में हिस्सा लेना, ब्राण्ड प्रमोशन, भेषजीय उत्पादन पंजीकरण प्रभार तथा इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए परीक्षण प्रभार भी शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक निर्यात संवर्धन गतिविधियों के लिए सरकार से उनकी कुल लागत के 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है जो उनकी गतिविधियों और कार्यान्वयन एजेंसी पर निर्भर करेगा जैसा कि विस्तृत दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है। मार्गदर्शन को पूरा विवरण <http://commerce.nic.in> में देखा जा सकता है।

विपणन विकास सहायता (एम डी ए)

3.2.1 प्रत्येक वर्ष नियमित आधार पर निर्यात संवर्धन परिपदों, उद्योग और व्यापार एसोसिएशनों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न निर्यात संवर्धन गतिविधियों को वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए विपणन विकास सहायता (एमडीए) योजना बनाई गई है।

संशोधित एमडीए दिशानिर्देशों के अनुसार उन निर्यातकों को एमडीए सहायता उपलब्ध है जिनका वार्षिक कारोबार 10 करोड़ रु. है।

इसमें व्यापार मेलों, विदेशों या भारत में क्रेताओं और विक्रेताओं के सम्मेलन में भागीदारी, व्यापार संवर्धन सेमिनार भी शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त उन निर्यातकों को जो कि चार केन्द्र बिन्दु क्षेत्र जैसे कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, सीआईएस क्षेत्र, एएसईएन देशों, आस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में से किसी एक में यात्रा करते हैं, उनको यात्रा अनुदान तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी के लिए सहायता उपलब्ध है।

अन्य क्षेत्रों में व्यापार मेलों इत्यादि में शामिल होने के लिए बिना यात्रा अनुदान के वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

व्यापार संबंधित मामलों हेतु विधिक खर्चों को चुकाना

3.2.1.1 निर्यात संवर्धन परिपदों की अनुशंसा पर योग्य निर्यातकों को व्यापार संबंधित मामले में मुकदमे पर खर्च को चुकाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।

उत्कृष्ट निर्यात वाले नगर

3.3 कुछ विशिष्ट भौगोलिक स्थलों में अनेक नगर अच्छे खासे औद्योगिक स्थापना स्थलों के रूप में उभरे हैं जो भारत के निर्यात में पर्याप्त योगदान देते हैं। इन औद्योगिक क्लस्टर मदों को मान्यता देना आवश्यक हो गया है ताकि उनकी क्षमता को अधिकतम किया जा सके और उच्च मूल्य बाजार में जाने के लिए उनका दर्जा बढ़ाने में सहायता की जा सके।

1000 करोड़ या उससे अधिक निर्यात करने वाले कुछ चुने हुए शहरों को उनकी निर्यात क्षमता के आधार पर उत्कृष्ट निर्यात के शहर के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। तथापि हथकरघा, हस्तशिल्प, कृषि व मत्स्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट निर्यात के शहर के लिए यह सीमा 250 करोड़ रुपये होगी।

इन क्षेत्रों में साधारण सेवा प्रदायक ईपीसीजी योजना की सुविधा के हकदार होंगे।

यूनिटों की मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों, केन्द्रित तकनीकी सेवाओं के सृजन हेतु बाजार पहुँच पहल योजना के अन्तर्गत धनराशि प्राप्त कर सकेंगे।

इसके अतिरिक्त ऐसे क्षेत्र एएसआईडी योजना से अभिन्न महत्वपूर्ण मूलभूत संरचना के अन्तराल को पहचानने हेतु प्राथमिकता के आधार पर सहायता प्राप्त करेंगे। उत्कृष्ट निर्यात के अधिसूचित कस्बे परिशिष्ट 7 में दिए गए हैं।

ब्रांड संवर्धन तथा गुणवत्ता

3.4.1 केन्द्र सरकार की नीति यह है कि वह विनिर्माताओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित करे कि वे अपने-अपने उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत गुणवत्ता के मानदण्डों को प्राप्त करेंगे। केन्द्रीय सरकार गुणवत्ता जागरूकता पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाने और कुल गुणवत्ता प्रबंध के विचार को बढ़ावा देने के लिए उद्योग और व्यापार संस्थाओं को समर्थन और सहायता प्रदान करेगी।

परीक्षण गृह

3.4.2 केन्द्रीय सरकार परीक्षण गृहों और प्रयोगशालाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर के स्तर का बनाने के लिए उनके आधुनिकीकरण और उन्नयन में सहायता करेगी।

गुणवत्ता संबंधी शिकायतें/विवाद

3.4.3 विदेशी क्रेताओं से प्राप्त हुई गुणवत्ता संबंधी शिकायतों की जांच विदेश व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में गठित गुणवत्ता शिकायतों की क्षेत्रीय उप-समिति (आर एस सी यू सी) द्वारा की जाएगी। विशेषतः गुणवत्ता संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु और सामान्यतः ऐसी अन्य शिकायतों के संबंध में, दिशा-निर्देश प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट-16 में दिए गए हैं।

व्यापार संबंधों को प्रभावित करने वाले व्यापारिक विवाद

3.4.4 यदि विदेश व्यापार महानिदेशक की जानकारी में यह बात आती है अथवा उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि कोई निर्यात अथवा आयात इस तरीके से किया गया है, जो :

- (i) किसी अन्य देश के साथ भारत के व्यापार संबंधों के लिए हानिकारक हो, और/अथवा
- (ii) निर्यात अथवा आयात में कार्यरत अन्य व्यक्तियों के हितों के प्रति हानिकार हो; और/अथवा
- (iii) जिससे देश की बदनामी हुई हो,

ऐसी स्थिति में विदेश व्यापार महानिदेशक संबंधित निर्यातक अथवा आयातक के विरुद्ध अधिनियम, इसके अधीन बने नियमों तथा आदेशों और इस नीति के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही कर सकते हैं।

3.5 स्टार निर्यात सदन

स्टार निर्यात सदन

3.5.1 व्यापारी और विनिर्माता निर्यातक, सेवा प्रदायक, निर्यातानुखी, एकक (ई ओ यू)/विशेष आर्थिक ज़ोन (एस ई जेड),

कृषि निर्यात ज़ोन (ए ई जेड) में स्थित यूनिटें, इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर तकनॉलॉजी पार्क (ई एच टी पी), साफ्टवेयर तकनॉलॉजी पार्क (एस टी पी) और जैव तकनॉलॉजी पार्क (बी टी पी) स्टार निर्यात सदन स्तर के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।

स्तर श्रेणी

3.5.2 आवेदक की श्रेणी का निर्धारण चालू तथा पिछले तीन वर्षों के कुल जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य (रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य मान्य निर्यातों के लिए) निर्यात निष्पादन पर निर्भर करेगा।

श्रेणी	निष्पादन (रुपयों करोड़ में)
एक स्टार निर्यात सदन	15
दो स्टार निर्यात सदन	100
तीन स्टार निर्यात सदन	500
चार स्टार निर्यात सदन	2000
पाँच स्टार निर्यात सदन	5000

टिप्पणी :—

1. लघु उद्योग/अति लघु क्षेत्र/कुटीर क्षेत्र, के पी आई सी/के बी आई पी के साथ पंजीकृत यूनिट, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम और जम्मू एवं कश्मीर में स्थित यूनिट, हस्तकरधा, हस्त शिल्प, हाथ से बुना कालीन, रेशम के कालीन निर्यात करने वाले यूनिट तथा परिशिष्ट-9 में यथा सूचीबद्ध लेटिन अमेरिका/सी आई एस/उप सहारन अफ्रीका को निर्यात करने वाले निर्यातक, आई एस ओ 9000 (शृंखला) वाले यूनिट/आईएसओ 14000 (शृंखला) स्तर वाले/डब्ल्यूएचओजीएमपी/एचएसी सीपी/एसईआईसीएमएम स्तर-2 तथा उच्च स्तर प्राप्त एजेंसियां जो परिशिष्ट 6क में सूचीबद्ध की गई हैं। सेवा और कृषि उत्पादों के निर्यात, स्टार निर्यात सदन स्तर की स्वीकृति हेतु, निर्यात के दोहरे वरीयता के पात्र होंगे। यह लाभ विनिर्माता तथा व्यापारी निर्यातकों को ही उपलब्ध होगा। तथापि, एक पोत-लदान उपर्युक्त श्रेणियों में से किसी भी एक को केवल एक पोत-लदान के लिए दोहरी वरीयता दी जाएगी।

- 1(क) निर्यात कारोबार एक से दूसरे को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। अतः निर्यात उत्पादन की गणना के लिए डिस्कलेमर पद्धति की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. पुनः निर्यात आधार पर किए गए निर्यात की गणना मान्यता प्रदान करने के लिए नहीं की जाएगी।
3. मान्यता के प्रयोजन के लिए किसी लिमिटेड कम्पनी की सहायक कम्पनी द्वारा किए गये निर्यात को लिमिटेड कम्पनी के निर्यात उत्पादन में गिना जाएगा। इस प्रयोजन के लिए कम्पनी के सहायक कम्पनी में अधिकतर शेयर होने चाहिए।
4. एक स्टार निर्यात सदन की मान्यता के लिए केवल तभी विचार किया जाएगा जब निर्यातक ने किन्हीं दो चालू वर्षों तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान न्यूनतम निर्यात निष्पादन 15 करोड़ रुपये या इसके अधिक किया हो।

विशेषाधिकार

3.5.2.1 एक स्टार निर्यात सदन निम्नलिखित सुविधाओं के हकदार होंगे :—

- (i) स्व-घोषणा आधार पर आयात और निर्यात दोनों के लिए लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति और सीमाशुल्क निकासी।
- (ii) तरजीह पर निवेश-उत्पादन मानदण्डों का निर्धारण 60 दिन के भीतर।
- (iii) बैंकों के माध्यम से दस्तावेजों के अनिवार्य लेन-देन से छूट, तथापि बैंकिंग चैनलों से रुपया भेजना जारी रहेगा।
- (iv) ई ई एफ सी खाते में विदेशी मुद्रा का 100 प्रतिशत रखना होगा,
- (v) सामान्य प्रत्यावर्तन अवधि को 180 दिन से 360 दिन तक करना।
- (vi) हटा दिया गया है।
- (vii) इस नीति के अधीन योजनाओं में बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की छूट होगी।
- (viii) दो स्टार तथा उससे अधिक स्टार वाले निर्यात सदनों को राजस्व विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्यात वेयरहाउस (गोदाम) बनाने की अनुमति होगी।

वैधता अवधि

3.5.3 1-9-2002 को या उससे बाद जारी अथवा नवीकृत सभी स्टार प्रमाण-पत्र लाइसेंसिंग वर्ष के 1 अप्रैल से वैध होंगे। इस अवधि के दौरान आवेदक जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, 31-3-2009 तक ऐसी मान्यता की मंजूरी के लिए आवेदन कर सकता है।

स्टार-धारक प्रमाण-पत्र की समाप्ति पर प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 में बंथा-निर्धारित अवधि के भीतर स्टार प्रमाण-पत्र की मंजूरी जैसा कि उपर्युक्त उक्त मान्यता के लिए कोई नया आवेदन हो, के लिए आवेदन देना आवश्यक होगा। उक्त संक्रमणकालीन अवधि के दौरान स्टार-धारक आम सुविधाओं और लाभों के लिए पैरा 3.5.2.1 दावा करने का हकदार होगा। बशर्ते कि आवेदक ऐसी सुविधाओं और लाभों का दावा करते समय एक शपथ-पत्र दाखिल करें कि नीति के अनुसार वह सतत मान्यता का हकदार है।

3.6 सेवाओं का निर्यात**सेवा निर्यात**

3.6.1 सेवाओं के व्यापार संबंधी सामान्य समझौते के तहत आने वाली सभी 161 व्यापार योग्य सेवाएं शामिल हैं। यहाँ ऐसी सेवाओं के लिए भुगतान को मुक्त विदेशी मुद्रा या भारतीय रुपये में जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्यथा मुक्त विदेशी मुद्रा द्वारा भुगतान किया गया मान लिया गया है, में लिया जाएगा। सेवाओं की सूची प्रक्रिया पुस्तक के परिशिष्ट-10 में दी गई है। नीति के सभी प्रावधान जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हों, आवश्यक परिवर्तनों के साथ सेवाओं के निर्यात के लिए भी लागू होंगे जो वस्तुओं के लिए लागू हैं।

सेवाओं के लिए निर्यात संवर्धन परिषद

3.6.2 सेवा निर्यातकों को फियो के पास पंजीकरण कराना होगा। तथापि, सॉफ्टवेयर निर्यातकों को इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद के पास पंजीकरण कराना होगा।

सेवाओं के लिए नई निर्यात संवर्धन परिषद

सेवा क्षेत्र को दिशा मार्गदर्शन और बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेवाओं के लिए एक विशेष निर्यात संवर्धन परिषद बनाई जायेगी।

सेवा निर्यात संवर्धन परिषद निम्न कार्य करेगी :

- (i) मुख्य सेवाओं के लिए मुख्य बाजारों की तलाश करेगी और मैट्रिक्स के प्रत्येक भाग के लिए कार्यक्रम के माध्यमों से बाजार का विकास करेगी।
- (ii) ब्राण्ड स्थापित करने और लक्ष्य बाजारों में मार्केटिंग कार्यक्रम तैयार करने में क्षेत्रीय सेवा प्रदायक के साथ सहयोग करेगी।
- (iii) नीति, प्रक्रिया और द्विपक्षीय/बहुपक्षीय मुद्दों के संबंध में सेवा उद्योग की मान्य नोडल बोडी के साथ समन्वय स्थापित करने में आवश्यक हस्तक्षेप करेगी।

आम सुविधा केन्द्र

3.6.3 सरकार क्षेत्र विशेष में गृह आधार पर सेवा प्रदायकों जैसे इंजीनियरिंग तथा वास्तुविद डिजाइन, मल्टी-मीडिया कार्यक्रमों, सॉफ्टवेयर का विकास करने वालों आदि उपयोग हेतु आम सुविधा केन्द्रों की स्थापना और विकास करेगी तथा राज्य स्तर और जिला स्तर के कस्बों से सेवा निर्यात नजरिये में गृह आधारित व्यावसायिकों को भारी संख्या में बुलाया जायेगा।

3.6.4 भारत से सेवित स्कीम**उद्देश्य**

3.6.4.1 सेवाओं के निर्यात में वृद्धि को बढ़ावा देना उद्देश्य है ताकि सशक्त और विशिष्ट 'भारत से सेवित' ब्रांड को तुरंत समस्त विश्व में मान्यता और आदर प्राप्त हो जाए।

पात्रता

3.6.4.2 प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट-10 में सूचीबद्ध सेवाओं के सभी सेवा प्रदायक जिन्होंने विगत वित्तीय वर्ष में कम से कम 10 लाख रुपये का कुल विदेशी मुद्रा अर्जन या भारतीय रुपये जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्य मुक्त विदेशी मुद्रा द्वारा भुगतान किया गया मान लिया गया है, वे शुल्क क्रेडिट हकदारी हेतु पात्रता के स्क्रिप होंगे।

उन व्यक्तियों जो कि प्रक्रिया पुस्तक (भाग-1) के परिशिष्ट-10 में सूचीबद्ध सेवाओं के सभी सेवा प्रदायक जिनका विदेशी मुद्रा अर्जन या भारतीय रुपये जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्यथा मुक्त विदेशी मुद्रा द्वारा भुगतान किया गया मान लिया गया है, के लिए विगत वित्तीय वर्ष में 5 लाख का मानदण्ड रखा गया है।

हकदारी

3.6.4.3 सभी सेवा प्रदायक जिसमें हैल्थकेयर और शैक्षणिक सेवा प्रदायक तथा इंजीनियरिंग बिजनेस आऊटसोर्सिंग (ई पी ओ) और

नॉलेज बिजनेस आऊटसोर्सिंग (के पी ओ) सेवा प्रदायक जो कि प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट-10 में सूचीबद्ध सूची सेवा प्रदायक (उन सेवा प्रदायकों के अतिरिक्त जो कि पैरा 3.6.4.4 के अन्तर्गत आते हैं) विगत वित्तीय वर्ष में 10 प्रतिशत विदेशी मुद्रा अर्जन के बराबर शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के पात्र होंगे। तथापि वह सेवा या सेवा प्रदायक जो कि प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैरा 3.18.1 में सूचीबद्ध हैं, इस योजना के अन्तर्गत आने वाले लाभों के हकदार नहीं होंगे।

प्रेषण

3.6.4.3 सेवा प्रदायकों द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए आर बी आई द्वारा अनुमत अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड और अन्य जरिए से अर्जित विदेशी मुद्रा को, स्कीम के तहत शुल्क क्रेडिट हकदारी के आकलन के ध्यान में रखा जाएगा।

होटल और रेस्टोरेंट

3.6.4.4 पर्यटन विभाग, द्वारा अनुमोदित एक सितारा और उससे अधिक सितारा होटल (मैनेज्ड होटल और हैरिटेज होटल शामिल हैं) और पर्यटन विभाग के पास पंजीकृत पर्यटन क्षेत्र के अन्य सेवा प्रदायक विगत वित्तीय वर्ष में उनके द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा के 5 प्रतिशत के बराबर शुल्क क्रेडिट के हकदार होंगे।

विशिष्ट रेस्टोरेंट विगत वित्तीय वर्ष में उनके द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा के 10 प्रतिशत के बराबर शुल्क क्रेडिट के हकदार होंगे।

अनुमत आयात

3.6.4.5 शुल्क क्रेडिट स्क्रिप को स्पेयर्स, कार्यालय उपकरण और पेशेवर उपकरण, कार्यालय फर्नीचर और उपभोग्यों सहित किसी पूंजीगत माल के आयात के लिए प्रयोग किया जा सकता है जो कि अन्यथा निर्यात और आयात मर्दों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण के तहत मुक्त रूप से आयात की जा सकती है अथवा इस संबंध में जारी एक सार्वजनिक सूचना के तहत किसी विशिष्ट श्रेणी के लिए अन्यथा मुक्त रूप से आयात की जा सकती है।

स्कीम के तहत अर्जित शुल्क क्रेडिट के इस्तेमाल की अनुमति वाहनों के आयात के मामले में शुल्क की अदायगी के लिए नहीं दी जाएगी, चाहे आई टी सी (एच एस) के तहत ऐसे वाहन मुक्त रूप से आयात योग्य हैं।

होटलों, गोल्फ रिजार्ट, क्लबों और विशिष्ट रेस्टोरेंटों के मामले में, जहाँ कैटरिंग सुविधा हो, शुल्क क्रेडिट हकदारी के खाद्य वस्तुओं और अल्कोहल युक्त पेयों हेतु भी प्रयोग किया जा सकता है।

गैर-हस्तांतरणीयता

3.6.4.6 हकदारी और आयातित माल गैर-हस्तांतरणीय होगा।

तथापि इस योजना के तहत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप आयातित माल का हस्तांतरण अध्याय 9 में उल्लिखित समूह कम्पनियों प्रदायकों के सेवा और वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त प्रबंधित होटलों के अन्तर्गत अनुमत होगा।

हेल्थ केयर और शिक्षा

3.6.4.7 हटा दिया गया है।

विशेष प्रावधान

3.6.4.8 सरकार के पास जनहित में अधिकार सुरक्षित होगा कि वह समय-समय पर सेवा निर्यातों की श्रेणी अथवा किस्म निर्धारित करेगी जो पात्रता अथवा हकदारी की गणना हेतु पात्र नहीं होंगे।

इसी प्रकार सरकार समय-समय पर उस माल को भी अधिसूचित करेगी, जो स्कीम के तहत जारी शुल्क मुक्त हकदारी प्रमाणपत्र के तहत आयात हेतु अनुमत नहीं होंगे।

पट्टा वित्तीयन के तहत आयात

3.6.4.9 इस नीति के पैरा 2.25 के प्रावधानों के अनुसार पट्टे के वित्तीयन के तहत पूंजीगत माल के आयात के मामले में शुल्क के भुगतान के लिए स्कीम के तहत अर्जित शुल्क मुक्त क्रेडिट हकदारी के इस्तेमाल की अनुमति होगी।

3.7 हटा दिया गया है।

3.8 विशेष कृषि और ग्रामीण उद्योग उपज योजना

(विशेष कृषि और ग्रामीण उद्योग उपज योजना)

उद्देश्य

3.8.1 विशेष कृषि और ग्रामीण उद्योग योजना (पूर्व विशेष कृषि उपज योजना) का उद्देश्य है फलों, सब्जियों, फूलों, लघु वन्य उत्पाद, दुग्ध, मुर्गीपालन और उनके मूल्यवर्द्धित उत्पादों तथा ऐसे उत्पादों के निर्यातकों को प्रोत्साहित कर ग्रामीण उद्योग उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है।

हकदारी

3.8.2 प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट 37क में दी गई सूची के अनुसार फलों, सब्जियों, फूलों और लघु वन्य उपज और उनके मूल्यवर्द्धित उत्पादों के तहत आने वाले उत्पादों के निर्यातक निर्यातों के 5 प्रतिशत पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के बराबर शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के हकदार होंगे। इन कृषि उत्पादों की सूची और निर्यातों की अवधि जिनके लिए हकदारी दी जा रही है के ब्यौरे प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट 37क में दिए गए हैं।

तथापि, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट 37क में दी गई सूची के अनुसार दुग्ध, मुर्गीपालन और उनके मूल्यवर्द्धित उत्पाद, 1 अप्रैल 2005 से अथवा उसके बाद किए गए निर्यातों के संबंध में लाभों के पात्र होंगे। तथापि प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट 37क में दी गई सूची के अनुसार ग्रामीण उद्योग उत्पाद, 1 अप्रैल, 2006 से अथवा उसके बाद किए गए निर्यातों के संबंध में लाभों के पात्र होंगे।

तथापि ऐसे मामले में जहाँ कृषि निवेशों (उत्प्रेरक, उपभोग्य और पैकिंग सामग्री को छोड़कर) के आयात के लिए इस नीति के अध्याय-4 के तहत निर्यातकों ने लाभ उठाए, शुल्क क्रेडिट स्क्रिप, निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 3.5 प्रतिशत की घटी दर पर अनुमत होगी। इसके मुद्दे आयातित स्क्रिप व मर्दें मुक्त रूप से हस्तांतरणीय होंगी।

3.8.2.1 स्कीम के अन्तर्गत, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट-37क में दी गई सभी मर्दों का निर्यात उपरोक्त पैरा 3.8.2. के

अनुसार निर्यात लाभों के योग्य होगा। जो मर्दे, निर्यात व आयात मर्दों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण में निर्यात नीति की अनुसूची 2 के तहत निर्यात के लिए प्रतिबन्धित अथवा निषिद्ध हैं, पैरा 3.8.2 के अन्तर्गत किन्हीं लाभों की पात्र नहीं होगी।

3.8.2.2 स्कीम के तहत निम्नलिखित निर्यात पर शुल्क क्रेडिट हकदारी के लिए विचार नहीं किया जाएगा :

- (क) विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.35 के अन्तर्गत आने वाले आयातित माल का निर्यात या ट्रांसशिपमेंट के द्वारा किया गया निर्यात;
- (ख) मान्य निर्यात;
- (ग) एस ई जेड और ई ओ यू इकाइयों से किया गया निर्यात।

अनुमत आयात

3.8.3 शुल्क क्रेडिट का प्रयोग पूंजीगत वस्तुओं सहित निविष्टियों या वस्तुओं के आयात हेतु किया जा सकता है जो कि अन्यथा आई टी सी (एचएस) के तहत इनका मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है।

निर्यात के पत्तन के अलावा अन्य किसी पत्तन से आयात की अनुमति राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना की शर्तों के अनुसार टी आर ए सुविधा के तहत दी जा सकती है।

3.8.3.1 प्रक्रिया पुस्तक (भाग-1) के परिशिष्ट 37 (ख) में उल्लिखित मर्दे इस योजना के अन्तर्गत आयात के लिए अनुमत नहीं की जाएंगी।

सेन्वैट/शुल्क-वापसी

3.8.4 विशेष कृषि और ग्रामीण उद्योग योजना के तहत नकद या डेबिट के जरिये किए गये अतिरिक्त सीमा-शुल्क/उत्पाद शुल्क के भुगतान को राजस्व विभाग द्वारा बनाये गए नियमों के अनुसार सेन्वैट क्रेडिट/शुल्क वापसी के रूप में समयोजित किया जायेगा।

विशेष प्रावधान

3.8.5 सरकार को जन हित में यह अधिकारी रहेगा कि वे समय-समय पर उन निर्यात उत्पादों के वर्ग को निर्दिष्ट करे जो हकदारी के परिकलन हेतु पात्र नहीं होंगे।

3.9 बाजार केन्द्रित स्कीम

उद्देश्य

3.9.1 इस स्कीम का उद्देश्य इन देशों को हमारी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के दृष्टिकोण से चुने हुए अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों से ऊँचे वहन-शुल्क की कीमत तथा अन्य असमर्थताओं की क्षतिपूर्ति करना है।

पात्रता

3.9.2 अधिसूचित देशों को सभी उत्पादों का निर्यात 1 अप्रैल, 2006 से शुरू होने वाले प्रत्येक लाइसेंसिंग वर्ष के लिए निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 2.5 प्रतिशत के समतुल्य शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का हकदार होगा। इसके मद्दे आयातित स्क्रिप और मर्दे मुक्त रूप से हस्तान्तरणीय होंगी।

3.9.2.1 जो मर्दे, निर्यात आयात मर्दों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण में निर्यात नीति की अनुसूची 2 के तहत निर्यात के लिए प्रतिबन्धित अथवा निषिद्ध हैं, पैरा 3.9.2 के अन्तर्गत किन्हीं लाभों की पात्र नहीं होगी। स्कीम के अन्तर्गत, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड 1) के परिशिष्ट-37 ग में यथा उल्लिखित सभी देशों को निर्यात उपर्युक्त 3.9.2 के अनुसार निर्यात लाभों का पात्र होगा।

3.9.2.2 स्कीम के तहत निम्नलिखित निर्यातों पर निर्यात निष्पादन के आकलन के लिए अथवा हकदारी की शर्तों के लिए विचार नहीं किया जाएगा;

- (क) विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.35 के अन्तर्गत आने वाले आयातित माल के निर्यात या ट्रांसशिपमेंट के द्वारा किया गया निर्यात।
- (ख) एस ई जेड/ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी आई/बी टी पी स्कीमों के तहत संचालित एककों का निर्यात कारोबार अथवा इन एककों को की गये आयातों अथवा उनके द्वारा निर्मित उत्पाद और डी टी ए इकाइयों के जरिये निर्यातित उत्पाद।
- (ग) मान्य निर्यात (चाहे भुगतान मुक्त विदेशी विनियम में प्राप्त किया जाना हो और भुगतान ई ई एफ सी खाते से होनी हो)
- (घ) सेवा निर्यात
- (ङ) हीरे और अन्य कीमती, अर्द्ध कीमती पत्थर
- (च) स्वर्ण, चाँदी, प्लेटिनम और सादे और जड़ित आभूषण सहित किसी भी रूप में अन्य कीमती पत्थर।
- (छ) सभी रूप में और सभी प्रकार के अयस्क और सांद्रण।
- (ज) सभी प्रकार के अनाज
- (झ) सभी प्रकार के और सभी रूपों में चीनी,
- (ञ) सभी प्रकार के और सभी रूपों में कच्चे/पेट्रोलियम तेल और कच्चे/पेट्रोलियम आधारित उत्पाद जो आई टी सी (एच एस) कोड 2709 से 2715 में शामिल किए गए हैं।

3.9.2.3 निर्यातकों के पास उन्हीं निर्यातित उत्पाद/उत्पादों के सम्बन्ध में या तो बाजार केन्द्रीय स्कीम अथवा कृषि उपज योजना और ग्रामीण उद्योग योजना के अन्तर्गत लाभ के आवेदन का विकल्प होगा।

अनुमत आयात

3.9.3 शुल्क क्रेडिट का प्रयोग निविष्टियों या पूंजीगत वस्तुओं सहित माल के आयात हेतु किया जा सकता है बशर्ते आई टी सी (एच एस) के तहत इनका मुक्त रूप से आयात किया जा सके।

राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के निबन्धन और शर्तों के अनुसार टी आर ए सुविधा के अन्तर्गत निर्यात के पत्तन के अलावा अन्य पत्तन से आयात की अनुमति दी जाएगी।

सेन्वैट/वापसी

3.9.4 विशेष कृषि उपज योजना के तहत नकद या डेबिट के जरिये किए गये अतिरिक्त सीमा-शुल्क/उत्पाद शुल्क के भुगतान को राजस्व विभाग द्वारा बनाये गए नियमों के अनुसार सेन्वैट क्रेडिट/शुल्क वापसी के रूप में समयोजित किया जायेगा।

विशेष प्रावधान

3.9.5 सरकार को जन हित में यह अधिकार रहेगा कि वे समय-समय पर उन निर्यातों और निर्यात उत्पादों को विनिर्दिष्ट करे जो हकदारी के आकलन हेतु पात्र नहीं होंगे।

3.10. उत्पाद केन्द्रित स्कीम**उद्देश्य**

3.10.1 स्कीम का उद्देश्य उन उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देना है जिनकी ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में उच्च रोजगार प्रगाढ़ता है जिससे मूलभूत सुविधाओं में कमी तथा इन उत्पादों के विपणन में आयी अन्य सहबद्ध कीमतों की क्षतिपूर्ति की जा सके।

पात्रता

3.10.2 अधिसूचित देशों को सभी उत्पादों का निर्यात 1 अप्रैल, 2006 से शुरू होने वाले प्रत्येक लाइसेंसिंग वर्ष के लिए निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 2.5 प्रतिशत के समतुल्य शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का हकदार होगा। तथापि, स्कीम के तहत ऐसे उत्पादों के निर्यात कारोबार का केवल 50 प्रतिशत का ही लाभों हेतु आकलन किया जाएगा। स्क्रिप और इसके मद्दे आयातित मर्दे मुक्त रूप से हस्तान्तरणीय होंगी।

3.10.2.1 स्कीम के तहत, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट-37 'ध' में यथा उल्लिखित ऐसे उत्पादों का निर्यात उपर्युक्त पैरा 3.10.2 के अनुसार निर्यात लाभों का पात्र होगा।

3.10.2.2 स्कीम के तहत निर्यात निष्पादन के आकलन अथवा हकदारी की गणना के लिए निम्नलिखित निर्यातों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

- (क) विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.35 के अन्तर्गत आने वाले आयातित माल के निर्यात या ट्रांसशिपमेंट के द्वारा किया गया निर्यात।
- (ख) एस ई जेड/ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी आई/बी टी पी स्कीमों के तहत संचालित एककों का निर्यात कारोबार अथवा इन एककों को की गयी आपूर्तियाँ अथवा उनके द्वारा विनिर्मित उत्पाद और डी टी ए इकाइयों के जरिये निर्यातित उत्पाद।
- (ग) भान्य निर्यात

3.10.2.3 निर्यातक के पास उसी निर्यातित उत्पाद/उत्पादों के संबंध में फोकस बाजार योजना के तहत अथवा फोकस उत्पाद भोजन के तहत अथवा विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन करने का विकल्प होगा।

अनुमत आयात

3.10.3 शुल्क क्रेडिट का प्रयोग निविष्टियों या पूंजीगत वस्तुओं सहित माल के आयात हेतु किया जा सकता है बशर्ते आई टी सी (एच एस) के तहत इनका मुक्त रूप से आयात किया जा सके। राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के निबंधन और शर्तों के अनुसार टी आर ए सुविधा के अन्तर्गत निर्यात के पत्तन के अलावा अन्य पत्तन से आयात की अनुमति दी जाएगी।

सेंवेट/शुल्क वापसी

3.10.4 विशेष कृषि उपज योजना के तहत नकद या डेबिट के जरिये किए गये अतिरिक्त सीमा-शुल्क/उत्पाद शुल्क के भुगतान को

राजस्व विभाग द्वारा बनावे गए नियमों के अनुसार सेंवेट क्रेडिट/शुल्क वापसी के रूप में समयोजित किया जायेगा।

विशेष प्रावधान

3.10.5 सरकार को जन हित में यह अधिकार रहेगा कि वे समय-समय पर उन निर्यातों और निर्यात उत्पादों को विनिर्दिष्ट करे जो हकदारी के आकलन हेतु पात्र नहीं होंगे।

अध्याय-चार**शुल्क मुक्त और शुल्क वापसी स्कीम**

4.1 शुल्क मुक्त स्कीम के अन्तर्गत निर्यात उत्पाद के लिए आवश्यक निविष्टियों का शुल्क मुक्त आयात किया जाता है। शुल्क मुक्त स्कीम के अन्तर्गत अग्रिम प्राधिकार पत्र अथवा एक शुल्क मुक्त आयात हकदारी (डी एफ आई ई) प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। शुल्क वापसी स्कीम के अन्तर्गत निर्यात उत्पाद में प्रयुक्त निविष्टियों पर लगे शुल्क के निर्यात पश्चात् प्रतिपूर्ति/वापसी की जाती है। शुल्क वापसी स्कीम में (क) डी एफ आर सी (शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाणपत्र) (ख) डी ई पी बी (शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम) और (ग) डी बी के (शुल्क वापसी स्कीम) हैं।

डी एफ आर सी निर्यात उत्पाद में प्रयुक्त निवेशों के शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति (रिप्लैनिशमेंट) अनुमत करता है। डी ई पी बी स्कीम में निर्यात उत्पाद में प्रयुक्त निविष्टियों पर आयात प्रभारों की वापसी की अनुमति है।

शुल्क मुक्त/वापसी स्कीम के अन्तर्गत निर्यात की गई वस्तुओं का पुनः आयात

4.1.1 अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी एफ आई ई प्रमाणपत्र/डी एफ आर सी/डी ई पी बी के अन्तर्गत निर्यात की गई वस्तुओं का पुनः आयात उसी रूप या आंशिक रूप से उसी रूप में पुनः आयात किया जा सकता है बशर्ते कि वे समय-समय पर जारी राजस्व विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हों।

मूल्य संवर्धन

4.1.2 इस अध्याय के मामले में (रत्न और आभूषण छोड़कर) मूल्य संवर्धन इस प्रकार होगा :—

ए-बी

वी.ए. = ——— × 100, जहाँ

बी

वी.ए. मूल्य संवर्धन

ए किए गए वास्तविक निर्यात का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य/प्राप्त आपूर्ति के मार्ग पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के लिए

बी प्राधिकार पत्र के तहत आने वाले आयातित निवेशों का लागत बीमा भाड़ा मूल्य तथा कोई अन्य प्रयुक्त आयातित माल जिस पर शुल्क वापसी का लाभ का दावा किया जा रहा है।

अग्रिम प्राधिकार पत्र प्रमाण-पत्र (पूर्ववर्ती अग्रिम लाइसेंसिंग स्कीम) अग्रिम प्राधिकार पत्र

4.1.3 निर्यात उत्पाद में (अपशिष्ट के लिए सामान्य अनुमति देते हुए) वास्तव में शामिल की जाने वाली निविष्टियों के शुल्क मुक्त

आयात की अनुमति देने के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, स्कीम के अधीन ईंधन, तेल, ऊर्जा, कैटालिस्ट आदि जिनकी खपत/प्रयोग निर्यात उत्पाद के लिए उपयोग की जाती है, को अनुमत किया जा सकता है। तथापि, विदेश व्यापार मामविदेशक, सार्वजनिक सूचना के माध्यम से, जनहित में अग्रिम प्राधिकार पत्र को सीमा से किसी उत्पाद (उत्पादों) को हटा सकता है।

अग्रिम प्राधिकार पत्र के अधीन प्राधिकार पत्र के तहत बीमा भाड़ा मूल्य के 10 प्रतिशत तक ऐसे अनिवार्य कलपुर्जों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति है जिनका परिणामी उत्पाद के साथ निर्यात/आपूर्ति आवश्यक है। शिपान (एस आई ओ एन) के अधीन निवेशों और निर्यात मर्दों के आधार पर अग्रिम प्राधिकार पत्र जारी किया जाता है। तथापि, वे प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैरा 4.7 के अनुसार स्वतः घोषित भानदण्डों या तदर्थ मानदण्डों के आधार पर भी जारी किए जा सकते हैं। अग्रिम प्राधिकार पत्र विनिर्माता, निर्यातक अथवा सहायक विनिर्माता के साथ जुड़े व्यापारी निर्यातक को निम्नलिखित हेतु जारी किया जा सकता है :—

- i. वास्तविक निर्यात (एस ई जैड को किए निर्यात समेत) और, या
- ii. अन्तर्वती आपूर्तियाँ, और/या
- iii. नीति के पैरा

8.2 (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ) और (ञ) में उल्लिखित श्रेणियों को माल की आपूर्ति हेतु मुख्य ठेकेदार को।

- iv. विदेश जाने वाले जहाज/वायुयान पर सामान की आपूर्ति इस शर्त के मद्दे होगी कि आपूरित मर्दों के संबंध में विशिष्ट शिपान है। माल के विनिर्माण में आवश्यक निविष्टियों के आयात के लिए।

इसके अलावा, नीति के पैरा 8.2 (घ) (ङ) (च) और (छ) में उल्लिखित विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के माल की आपूर्ति के बारे में, ऐसी परियोजना के मुख्य ठेकेदार के उप-ठेकेदार द्वारा भी अग्रिम प्राधिकार पत्र का लाभ उठाया जा सकता है बशर्ते कि उप-ठेकेदार का नाम मुख्य ठेके में उल्लिखित हो।

ऐसा प्राधिकार पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ को की गयी आपूर्तियों अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता कार्यक्रम अथवा अन्य बहुपक्षीय एजेंसियों के अन्तर्गत हेतु भी जारी किया जा सकता है और जिसका भुगतान मुक्त विदेशी मुद्रा में किया जाएगा।

4.1.4 वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के मद्दे पैरा 4.1.3 में परिभाषित निवेशों के शुल्क मुक्त आयात हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र जारी किया जाता है। ऐसे प्राधिकार पत्र मूल सीमाशुल्क, अतिरिक्त सीमाशुल्क, शिक्षा उपकर एंटीडम्पिंग शुल्क, और सुरक्षा शुल्क, यदि कोई हो, के भुगतान से छूट प्राप्त होंगे। तथापि, पैरा 8.2 (झ) और (त्र) के तहत शामिल आपूर्तियों हेतु आयात, लागू एंटी डम्पिंग और सुरक्षा शुल्क, यदि कोई हो, के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं होगा।

4.1.5 अग्रिम प्राधिकार पत्र और/अथवा उनके तहत आयातित माल निर्यात दायित्व की पूर्ति के बाद भी हस्तान्तरणीय नहीं होंगे। तथापि, प्राधिकार पत्र धारक को निर्यात दायित्व की पूर्ति करने के बाद शुल्क मुक्त निवेशों में से विनिर्दिष्ट उत्पाद को बेचने का विकल्प प्राप्त होगा।

4.1.6 अग्रिम प्राधिकार पत्र सकारात्मक मूल्य संवर्धन के साथ जारी किया जा सकता है।

तथापि, ऐसा वास्तविक निर्यात जिसका भुगतान मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्त नहीं होता है, वह प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1), के परिशिष्ट 32 में यथाविनिर्दिष्ट मूल्य संवर्धन के अधीन होगा। एस ई जैड इकाइयों को आपूर्ति के मामले में, मुद्रा के प्रापण पर ध्यान न देते हुए, अग्रिम प्राधिकार पत्र सकारात्मक मूल्य संवर्धन के साथ जारी कर दिया जाएगा।

चाय के मामले में अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत न्यूनतम मूल्य संवर्धन 100 प्रतिशत होगा।

मसालों के मामले में [निर्यात और आयात मर्दों के आई टी सी (एच एस) मर्दों के वर्गीकरण, 2004-09 के अध्याय-9 में शामिल], अग्रिम लाइसेंस के तहत न्यूनतम मूल्य संवर्धन 15 प्रतिशत होगा।

4.1.7 अग्रिम प्राधिकार पत्र जारी करने की तारीख को प्रभावी प्रक्रिया और नीति के अनुसार जारी किया जाएगा।

आयात हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र की वैधता अर्वाधि प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में विनिर्दिष्ट के अनुसार होगी।

4.1.8 अग्रिम प्राधिकार पत्र की सुविधा वहाँ भी उपलब्ध होगी जहाँ निर्यातक को कुछ अथवा सभी निवेशों की निश्चित आपूर्ति की जाती है।

ऐसे मामलों में, मूल्य संवर्धन की गणना हेतु, निःशुल्क निवेशों के नोशनल मूल्य के साथ अन्य शुल्क मुक्त निवेशों को भी ध्यान में रखा जाएगा। तथापि, यदि सभी निविष्टियों की बिना लागत आपूर्ति की जाती है तो निर्यातक के पास नीति के पैराग्राफ 4.2.7 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों का पालन करने का भी विकल्प होगा।

निर्यात दायित्व

4.1.9 अग्रिम प्राधिकार पत्र के अधीन निर्यात दायित्व को पूरा करने की अवधि प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में उल्लिखित अनुसार होगी।

बी आई एफ आर यूनिटों हेतु प्रावधान

4.1.9क बी आई एफ आर के पास पंजीकृत किसी फर्म/कम्पनी अथवा यूनिट अधिग्रहण कराने वाली किसी फर्म/कम्पनी, जो बी आई एफ आर के अन्तर्गत हो, संचालन एजेंसी द्वारा तैयार किए पुनर्वास पैकेज के अनुसार निर्यात निष्पादन अर्वाधि विस्तार की अनुमति होगी बशर्ते कि बी आई एफ आर का वाद में अनुमोदन प्राप्त हो जाए।

तथापि, उन मामलों में जहाँ पुनर्वास पैकेज में निर्यात दायित्व अर्वाधि विस्तार का उल्लेख न हो, निर्यात दायित्व पूर्ति हेतु मामले के गुण-दोष के आधार पर प्राधिकार पत्र के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि हेतु अनुमति प्रदान की जाएगी।

इसी प्रकार, संबंधित राज्य सरकार का पुनर्वास स्कीम के अनुसार ऐसी सुविधा हेतु एस एस आई यूनिट भी पात्र होगी। तथापि, उन मामलों

में जहाँ राज्य पुनर्वास स्कीम में निर्यात दायित्व विस्तार अवधि का उल्लेख ना हो, निर्यात दायित्व की पूर्ति हेतु मामले के गुण-दोष के आधार पर प्राधिकार पत्र जारी करने की तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक अनुमति दी जाएगी।

निर्यात दायित्व अवधि विस्तार, जैसा ऊपर दिया गया है, उन मामलों में संयोजन शुल्क के भुगतान के बिना होगा जहाँ पुनर्वास पैकेज घोषित/अनुमोदित कर दिया गया है।

वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र

4.1.10 अग्रिम प्राधिकार पत्र वार्षिक निर्यातों, अन्तर्वर्ती आपूर्तियों और/या मान्य निर्यातों के लिए वार्षिक अपेक्षाओं के आधार पर भी जारी किए जा सकते हैं।

एक से पाँच सितारा निर्यात सदन, वार्षिक अपेक्षा के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र के लिए पात्र होंगे। निर्यातकों की अन्य सभी श्रेणियाँ जिनका विगत निर्यात निष्पादन पिछले दो वर्षों का हो वे भी वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र हेतु पात्र होंगे।

इसके अलावा, व्यापारी निर्यातक को उनकी वार्षिक अपेक्षा के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र दिया जा सकेगा बशर्ते कि वे संगत प्राधिकार पत्र में सह विनिर्माता (विनिर्माताओं) के नाम (नामों) के पृष्ठांकन के लिए सहमत हों।

विगत लाइसेंसिंग वर्ष में इस स्कीम के अन्तर्गत आयात के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के अनुसार हकदारी वास्तविक और/या मान्य निर्यात के मूल्य के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 300 प्रतिशत अथवा एक करोड़ रुपये, जो भी अधिक हो, तक होगी। ऐसे प्राधिकार पत्र में विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.1.6 में विनिर्दिष्ट मूल्य संवर्धन शामिल होगा।

अग्रिम रिलीज आदेश

4.1.11 अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक, वार्षिक अपेक्षा के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक, हीरा अग्रदाय प्राधिकार पत्र का धारक, डी एफ आई ई प्रमाणपत्र का धारक और डी एफ आर सी धारक जो सीधे आयात के बदले स्वदेशी/स्त्रोतों राज्य व्यापार अधिकरणों/ई ओ यू/एस ई जेड/ई एच टी पी/एस.टी.पी. यूनिटों/बी टी पी से निविष्टियाँ प्राप्त करना चाहता है तो उसे उन निविष्टियों को अग्रिम रिलीज आदेशों के प्रति मुक्त विदेशी मुद्रा/भारतीय रुपए में प्राप्त करने का विकल्प होगा।

डी एफ आई ई प्रमाणपत्र अथवा डी एफ आर सी के हस्तांतरणकर्ता भी ए.आर.ओ सुविधा के लिए पात्र होगा। तथापि, ई.ओ.यू./ई.एच.टी.पी./बी.टी.पी./एस.टी.पी./एस ई जेड यूनिटों से ए.आर.ओ. को परिवर्तन किए बिना प्राधिकार पत्र के प्रति आपूर्तियाँ प्राप्त की जा सकती हैं।

ए.आर.ओ की वैधता अवधि प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में यथानिर्धारित के अनुसार होगी।

बैंक टू बैंक अन्तर्देशीय साख पत्र

4.1.12 अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक, वार्षिक अपेक्षाओं के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक, डी एफ आई ई प्रमाण-पत्र धारक, हीरा

अग्रदाय प्राधिकार पत्र धारक और डी एफ आर सी धारक, अग्रिम रिलीज आदेश के लिए आवेदन करने के बजाय, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बैंक टू बैंक अन्तर्देशीय साख पत्र का लाभ उठा सकता है।

निषिद्ध मर्दे

4.1.13 अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी एफ आई ई प्रमाण-पत्र/डी एफ आर सी के तहत आई टी सी (एच एस) में उल्लिखित आयातों का निषिद्ध मर्दों का आयात नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, राज्य व्यापार उद्यमों द्वारा आयात हेतु आरक्षित मर्दों को अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी एफ आई ई प्रमाणपत्र/डी एफ आर सी के मर्दे आयात नहीं किया जा सकता। तथापि, ये मर्दे अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी एफ आई ई प्रमाणपत्र/डी एफ आर सी/डी एफ आई ए धारक को जारी ए आर ओ अथवा अवैधीकरण पत्र के मर्दे राज्य व्यापार उद्यमों से खरीदी जा सकती हैं।

अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी एफ आई ई प्रमाणपत्र/डी एफ आर सी धारक को समुद्र में बिक्री के आधार पर माल की बिक्री की अनुमति राज्य उद्यमों को भी प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, राज्य व्यापार उद्यमों को अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी एफ आई ई प्रमाणपत्र/डी एफ आर सी धारक द्वारा आयात के लिए यदि ऐसा वे चाहें तो 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' जारी करने की अनुमति प्रदान की जाती है। तथापि, प्राधिकार पत्र धारक को उन 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' के मर्दे किए गए आयातों की तिमाही विवरणी संबंधित राज्य उद्यमों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है और राज्य व्यापार उद्यम, इसके बाद ऐसे आयातों की अर्द्धवार्षिक आयात आँकड़े, निगरानी हेतु वाणिज्य विभाग को एक पृष्ठांकित प्रति सहित संबंधित प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत करेगी।

इसी प्रकार आई टी सी (एच एस) में उल्लिखित निर्यातों की निषिद्ध मर्दों का इस अग्रिम प्राधिकार पत्र प्रमाणपत्र स्कीम के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र/प्रमाणपत्र के तहत निर्यात नहीं किया जा सकता। इसके अलावा प्रतिबंधित मर्दों का निर्यात, निर्यात प्राधिकार पत्र अथवा अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता अथवा सभी शर्तों के मर्दे आई टी सी (एच एस) की अनुसूची-2 के तहत होगा।

शुल्क वापसी की स्वीकार्यता

4.1.14 अग्रिम प्राधिकार पत्र के मामले में, निर्यातित माल में प्रयुक्त शुल्क भुगतान किए गए माल पर शुल्क वापसी उपलब्ध होगी, चाहे आयातित या स्वदेशी हो, वित्त मंत्रालय (शुल्क वापसी निदेशालय) द्वारा निर्धारित शुल्क वापसी दर के अनुसार शुल्क वापसी उपलब्ध होगी। तथापि, आवेदन पत्र में यथा उल्लिखित शुल्क प्रदत्त सामग्रियों को ही शुल्क वापसी दी जाएगी।

शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाणपत्र

शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाणपत्र (डी एफ आर सी)

4.2 वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयुक्त निविष्टियों के आयात के लिए व्यापारी निर्यातक अथवा विनिर्माता-निर्यातक को मूल सीमाशुल्क, शुल्क का भुगतान किए बिना शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।

तथापि, ऐसी निविष्टियाँ आयात के समय उत्पाद शुल्क के बराबर अतिरिक्त सीमाशुल्क के भुगतान के शर्तों के अधीन होंगी।

4.2.1 डी एफ आर सी, रत्न और आभूषण क्षेत्र की ऐसी मदों जिनके लिए प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैराग्राफ 4 क. 2.1 में मूल्य संबंधन दिया गया है और, अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के तहत उच्च मूल्य संबंधन के लिए विनिर्दिष्ट मदों को छोड़कर 25 प्रतिशत के न्यूनतम मूल्य संबंधन पर जारी किए जाएंगे।

4.2.2 शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है उस वास्तविक निर्यात के लिए जिसके लिए मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा उन वास्तविक निर्यातों के लिए भी शुल्क मुक्त प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है जो एस ई जेड के लिए भुगतान अपरिवर्तनीय मुद्रा/आपूर्तियों के लिए भी जारी की जा सकती है जो नीति के पैराग्राफ 8.2 के अधीन प्रभावी है।

[डी एफ आर सी धारकों की आपूर्तियों को छोड़कर डी एफ आर सी उन वास्तविक निर्यातों के लिए भी (एस ई जेड की आपूर्तियों को छोड़कर) जारी की जा सकती है जिनके लिए भुगतान अपरिवर्तनीय मुद्रा किया जा सकता है। तथापि, ऐसा निर्यात प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1)] के परिशिष्ट-11 में यथानिर्दिष्ट मूल्य संबंधन व शर्तों के अधीन होगा।

4.2.3 विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा यथाअधिसूचित सिओस के अन्तर्गत शामिल केवल निर्यात उत्पादों के संबंध में शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे।

तथापि सिआन्स जो 'वास्तविक प्रयोक्ता' की शर्त के अधीन है या जहाँ निर्यात आय प्राप्त न हुई हो आवेदन पत्र को भरते समय या सामान्य मानदण्डों के तहत ईंधन के आयात के लिए हो, इन सब निवेशों के लिए डी एफ आर सी वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त सहित जारी किया जाएगा।

तथापि, ईंधन, के लिए आयात पात्रता उसी कम्पनी को हस्तांतरित की जा सकती है जो बाजार में ईंधन के विपणन के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से प्राधिकृत हो।

ऐसे मामले जिनमें मानक निवेश उत्पाद मानदण्ड एसिटिक एनहाइडाइड, एपीडाइन तथा सिओडो एपीडाइन के आयात को अनुमत करते हैं, इनके लिए डी एफ आर सी जारी किया जाएगा बशर्ते इन मदों को आयात मदों की सूची से विशेष रूप से हटा दिया गया हो।

सिओन (एस आई ओ एन) जोकि निवेशों के लिए पूर्व आयात की शर्त निर्धारित करता हो, के मामले में डी आफ आर सी जारी नहीं किया जाएगा।

विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.1.13 के प्रावधान डी एफ आर सी धारक के लिए लागू होंगे।

4.2.4 शिपिंग बिल में यथा उल्लिखित सिओन के अनुसार निविष्टियों के आयात के लिए शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे। ऐसे प्राधिकारों की वैधान प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के प्रावधानों के अनुसार लागू होगी। डी. एफ. आर. सी. और/या इसके मद्दे आयातित वस्तु (वस्तुएँ) मुक्त रूप से हस्तांतरणीय होगी। तथापि, वास्तविक

प्रयोक्ता की सशर्त डी एफ आर सी या उसके मद्दे में आयातित वस्तु (वस्तुएँ) अहस्तांतरणीय होंगी।

4.2.5 निर्यात उत्पाद, जो संशोधित चैट के लिए पात्र हैं, सेनवेट क्रेडिट/सेवा कर क्रेडिट के लिए पात्र होंगे।

तथापि, स्कीम के अन्तर्गत गैर-उत्पाद शुल्क योग्य, गैर-शुल्क योग्य या केन्द्रीय चैट योग्य उत्पाद, स्कीम के तहत आयात के समय प्रदत्त अतिरिक्त सीमाशुल्क के बदले में निर्यात के समय शुल्क वापसी के पात्र होंगे।

4.2.6 शुल्क वापसी निदेशालय (वित्त मंत्रालय) द्वारा निर्धारित शुल्क वापसी दर के अनुसार निर्यात उत्पाद में प्रयुक्त किसी भी सामग्री जिसपर शुल्क अदा किया गया हो चाहे आयातित हो अथवा स्वदेशी, के संबंध में निर्यातक शुल्क वापसी लाभों के लिए पात्र होंगे।

तथापि, शुल्क वापसी शुल्क भुगतान की गई वस्तुओं तक प्रतिबंधित हो जो सिओन के अन्तर्गत न आती हों।

पुनः निर्यात के लिए जाबिंग मरम्मत आदि

4.2.7 राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की गयी अधिसूचना के अनुसार जो माल आई टी सी (एच एस) में प्रतिबंधित रूप में उल्लिखित निःशुल्क आपूर्ति की शर्तों पर निषिद्ध मद नहीं है जाबिंग प्रयोजन के लिए उसका प्राधिकार/प्रमाणपत्र/अनुमति के बिना आयात के अनुमति दी जा सकती है।

सीमाशुल्क अधिसूचना की शर्तों के अनुसार, मरम्मत, रिफिनिंग, रिइंजीनियरिंग, टेस्टिंग आदि करने के लिए इसी प्रकार के माल के आयात की अनुमति होगी चाहे वह माल निर्यात आयात नीति/आयात और निर्यात पुस्तक के आई.टी.सी (एच.एस.) वर्गीकरण के अधीन आयात के लिए प्रतिबंधित हों।

तथापि, उपरोक्त प्रावधान सभी शर्तों के अधीन या प्राधिकार अथवा/अनुमति की आवश्यकता के अनुसार लागू होंगे जो आई टी सी (एच एस) की अनुसूची-2 के तहत अपेक्षित हैं।

स्कीम की समाप्ति

4.2.8 डी. एफ. आर.सी.स्कीम, 30-4-2006 तक किए गए निर्यातों के लिए लागू होगी।

शुल्क हकदारी पास बुक स्कीम (डी ई पी बी)

4.3 शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम का उद्देश्य है निर्यात उत्पाद के आयात अंश पर लागू सीमाशुल्क को अप्रभावी करना है। निष्प्रभावीकरण निर्यात उत्पाद के मद्दे शुल्क क्रेडिट की मंजूरी से किया जाएगा।

डी ई पी बी योजना तब तक लागू रहेगी जब तक निर्यातकों के साथ परामर्श करके कोई अन्य नई योजना नहीं बनाई जाती।

4.3.1 डी टी ए द्वारा एस ई जेड यूनिट को आपूर्ति के मामले में एस ई जेड यूनिट के विदेशी मुद्रा लेखा से डी ई पी बी के अधीन निर्यातक, मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में किए गए निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की विनिर्दिष्ट प्रतिशतता के रूप में क्रेडिट के लिए आवेदन कर सकता है।

कच्चे माल, अन्तरवर्तियों, संघटकों, कलपुर्जों, पैकेजिंग सामग्री आदि के आयात हेतु क्रेडिट, ऐसे निर्यात उत्पादों और ऐसी दरों के मद्दे उपलब्ध होगा जो विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा इस संबंध में जारी सार्वजनिक सूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हों। क्रेडिट का इस्तेमाल किसी मद पर सीमाशुल्क के भुगतान हेतु किया जा सकता है जो मुक्त रूप से आयात किए जा सकें।

4.3.2 डी ई पी बी धारक के पास अतिरिक्त सीमाशुल्क का भुगतान यदि कोई हो नगद भी करने का विकल्प होगा।

वैधता

4.3.3 आयात के लिए डी ई पी बी की वैधता की अवधि प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में यथा निर्धारित के अनुसार होगी।

हस्तांतरणीयता

4.3.4 डी ई पी बी और/अथवा इसके प्रति आयातित मदे मुक्त रूप से हस्तांतरणीय हैं। तथापि, डी ई पी बी का हस्तांतरण डी ई पी बी में आयात के लिए विनिर्दिष्ट उस पत्तन पर होगा जहाँ से निर्यात किया गया है।

निर्यात के पत्तन से अलग पत्तन से आयातों को राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना की शर्तों के अनुसार टी आर ए सुविधा के तहत अनुमति दी जाएगी।

शुल्क वापसी की उपयुक्तता

4.3.5 सामान्य रूप से डी. ई. पी. बी. स्कीम के अधीन किए गए निर्यात शुल्क वापसी के हकदार नहीं होंगे। तथापि, डी ई पी बी के अधीन निविष्टियों पर नकद अदा किया गया अतिरिक्त सीमाशुल्क/उत्पाद शुल्क को राजस्व विभाग द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार सेनेटैट क्रेडिट या शुल्क वापसी के रूप में समायोजित किया जाएगा।

शुल्क मुक्त निवेश हकदारी प्रमाणपत्र

स्कीम

4.4.1 निविष्टियों, ईंधन, ऊर्जा स्रोत, उत्प्रेरक आदि के शुल्क मुक्त आयात की मंजूरी के लिए एक शुल्क मुक्त निविष्टि हकदारी प्रमाण पत्र जारी किया जाता है जो निर्यात उत्पाद के उत्पादन के लिए अपेक्षित हैं। तथापि, महानिदेशक, विदेश व्यापार जनहित में सार्वजनिक सूचना के माध्यम से इस स्कीम की सीमा से किसी उत्पाद (उत्पादों) को बाहर कर सकते हैं। यह स्कीम 01 मई, 2006 से प्रभावी होगी।

हकदारी

4.4.2 ये प्रमाण पत्र निविष्टि और निर्यात मर्दों के आधार पर मानक निविष्टि और उत्पादन मानदण्डों (सिओन) के तहत जारी किए जाएंगे। आयात हकदारी सिओन में उल्लिखित मात्रा तक सीमित होगी।

प्रमाणपत्र के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के 10 प्रतिशत तक अनिवार्य कलपुर्जों का शुल्क मुक्त आयात जिनके परिणामी उत्पाद के साथ निर्यात/आपूर्ति किया जाना अपेक्षित है, स्कीम के अन्तर्गत भी किया जा सकता है। ऐसे प्रमाण पत्र या तो विनिर्माता निर्यातक अथवा सह विनिर्माता

(विनिर्माताओं) से संबद्ध व्यापारी निर्यातक को जारी किए जा सकते हैं—

(i) वास्तविक निर्यातों के लिए (एस ई जेड को निर्यातों सहित), और/अथवा

(ii) मध्यवर्ती आपूर्तियों के लिए, और/अथवा

नीति के पैराग्राफ 8.2 (ख) (ग) (घ) (ङ) (च) (छ) (झ) और (ञ) में उल्लिखित श्रेणियों के माल की आपूर्ति हेतु मुख्य ठेकेदार को, माल के विनिर्माण में अपेक्षित निविष्टि के आयात के लिए।

इसके अलावा, नीति के पैराग्राफ 8.2 (घ) (ङ) (च) (छ) और (ञ) में उल्लिखित विनिर्दिष्ट परियोजनाओं को माल के आपूर्ति के संबंध में, ऐसी परियोजना के मुख्य ठेकेदार के उप ठेकेदार द्वारा एक डी एफ आई ई प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है बशर्ते कि मुख्य ठेके में, उप-ठेकेदार का नाम आता है।

ऐसे प्रमाण पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ या संयुक्त राज्य के सहायता कार्यक्रम के तहत या अन्य बहुपक्षीय एजेन्सियों को की गई आपूर्तियों और मुक्त विदेशी मुद्रा में किए गए भुगतान हेतु भी जारी किए जा सकते हैं।

एक विनिर्माता निर्यातक अथवा सह विनिर्माता के साथ सम्बद्ध एक व्यापारी निर्यातक इस स्कीम के तहत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है। स्कीम के तहत किए गए निर्यात से पूर्व, आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

ऐसे प्रमाण पत्र शुरू में वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन जारी किए जाएंगे तथा मूल सीमाशुल्क, अतिरिक्त सीमाशुल्क, शिक्षा उपकर, एण्टी डम्पिंग शुल्क और सुरक्षात्मक शुल्क, यदि कोई हो, के भुगतान से छूट दी जाएगी।

आयात मर्दे

4.4.3 आई.टी.सी. (एच.एस.) में उल्लिखित आयातों की निपिद्ध मर्दे स्कीम के तहत जारी प्रमाण पत्र के अन्तर्गत आयात नहीं की जाएगी।

घरेलू बाजार से शुल्क मुक्त प्राप्ति ए आर ओ/अवैधता पत्र/बैंक टू बैंक अन्तरदेशीय साख पत्र आदि के मद्दे अग्रिम प्राधिकार स्कीम के मामले जैसा उपलब्ध होगा।

डी एफ आई ई प्रमाण पत्र धारक हेतु विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.1.13 के प्रावधान लागू होंगे।

मूल्य संवर्धन

4.4.4 रत्न और आभूषण क्षेत्र के मर्दों को छोड़कर ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने के लिए न्यूनतम 20 प्रतिशत मूल्य संवर्धन अपेक्षित होगा, जिनके लिए प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैराग्राफ 4 क 2.1 में यथा उल्लिखित मूल्य संवर्धन और अग्रिम प्राधिकार स्कीम के अन्तर्गत

जिन मदों के लिए अधिक मूल्य संवर्धन निर्धारित किया गया है, लागू होंगे।

निर्यात दायित्व

4.4.5 स्कीम के अधीन निर्यात दायित्व को पूरा करने से संबंधित प्रक्रिया और इसे पूरा करने के लिए अनुमत समयावधि प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 के अध्याय 4 में दी गई है।

हस्तान्तरणीयता

4.4.6 निर्यात दायित्व पूर्ण हो जाने के बाद प्रमाणपत्र के हस्तान्तरणीयता अथवा इसके मुद्दे आयातित निविष्टियों के लिए आवेदन क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी के समक्ष किया जा सकता है। हस्तान्तरणीयता पृष्ठांकित होने के बाद, प्रमाणपत्र धारक इस प्रयोजन के लिए डी जी एक टी, द्वारा अधिसूचित किसी अन्य मद (मदों) तथा ईंधन के अलावा शुल्क मुक्त निविष्टियों के हस्तांतरण के लिए स्वतंत्र होगा।

तथापि, मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों के संबंध में जो 'वास्तविक प्रयोक्ता' शर्तों के अधीन है अथवा सामान्य मानदण्डों के तहत ईंधन के आयात के लिए अथवा जहाँ, एसिटिक एन हाइड्राइड इफेड्राइन और स्प्रूडो इफेड्राइन का आयात मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्ड/मानदण्डों के तहत अनुमत है, इन निविष्टियों के लिए वास्तविक प्रयोक्ता शर्तों के अधीन डी जी एक आई ई प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा तथा निर्यात दायित्व पूरा होने के बाद भी इन निविष्टियों हेतु कोई हस्तान्तरणीयता अर्जन नहीं की जाएगी।

तथापि, ईंधन के लिए, आयात हकदारी केवल उन कम्पनियों को हस्तान्तरित की जाएगी जिन्हें तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ईंधन के विपणन का प्राधिकार मंजूर किया गया है।

सेनबेट सुविधा

4.4.7 प्रमाणपत्र के मुद्दे आयातित या घरेलू स्रोतों से प्राप्त निविष्टियों हेतु कोई सेनबेट क्रेडिट सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

शुल्क वापसी सुविधा

4.4.8 वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शुल्क वापसी दर के अनुसार निर्यातित वस्तुओं में इस्तेमाल चाहे आयातित हो या घरेलू स्रोतों से प्राप्त हो, किसी भी शुल्क का भुगतान किए गए माल के संबंध में शुल्क वापसी उपलब्ध होगी। तथापि शुल्क वापसी, आवेदन पत्र में उल्लिखित शुल्क का भुगतान किए गए माल तक प्रतिबंधित होगी।

रत्न और आभूषण

रत्न और आभूषण के लिए स्कीम

4क. रत्न और आभूषण निर्यातक, रत्न और आभूषण के विनिर्माण के लिए आवश्यक शुल्क मुक्त निविष्टियों का आयात प्राप्त कर सकते हैं।

प्रतिपूर्ति प्राधिकार

4क.1 रत्न और आभूषण निर्यातक प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में इस संबंध में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार लाइसेंसिंग प्राधिकारी से प्रतिपूर्ति प्राधिकार (आर ई पी) प्राप्त करके अपने निवेशों का शुल्क मुक्त आयात करने के पात्र होंगे।

4क.1.1 प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट 12क में सूचीबद्ध रत्न और आभूषण उत्पादों के निर्यातक, अपने निवेशों के आयात और उनका प्रतिपूर्ति के लिए उक्त परिशिष्ट में उल्लिखित दर पर और उसमें दी गई मदी के लिए, प्रतिपूर्ति प्राधिकार के पात्र होंगे।

प्रतिपूर्ति प्राधिकार, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैराग्राफ 4क.28 में उल्लिखित धिवरण के अनुसार उपभोग्यों के आयात के लिए भी जारी किया जा सकता है।

प्रमाणन/ग्रेडिंग के लिए कटे हुए और पॉलिश किए हीरों का निर्यात

4क.2 रत्न और आभूषण निर्यातक 0.25 कैरेट भार या उससे अधिक के कटे और पॉलिश किए हीरों को भारतीय हीरा संस्थान, सूरत, गुजरात को प्रमाणन/ग्रेडिंग हेतु भेजने की अनुमति दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, कम से कम तीन वर्षों का निर्यात अनुभव रखने वाले और पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक के वार्षिक औसत कारोबार करने वाले रत्न और आभूषण निर्यातक अथवा जिमोलोजिकल इंस्टिट्यूट आफ अमेरिका (जी आई ए), दि रोबर्ट मोडवाइ कैम्पस, इंटरनेशनल जिमोलोजिकल इंस्टिट्यूट (आई जी आई) और यू एस ए में यूरोपियन जिमोलोजिकल लेबोरेटरी (ईजीएल), हॉग रोड बुर डायमण्ड, एन्टवर्प (एच आर डी) वर्ल्ड डायमण्ड सेन्टर आफ डायमण्ड हाई काउंसिल, एन्टवर्प, बेल्जियम, सेन्ट्रल जेम लेबोरेटरी, मिआगी विल्डिंग 5-15-14 यूएनो टायतो क्यू, टोक्यो, जापान, अमेरिकन जेम मोसायटी कैबोरेटरीज (एजीएम लैबोरेटरीज) 8917 वेस्ट महारा एवेन्यू, लान वेगास, नेवादा 89117 और डायमण्ड ट्रेडिंग कम्पनी, मेडेनहीड, यू.के. के भारत में स्थित प्राधिकृत कार्यालय/एजेंसियों को उक्त प्रयोगशालाओं/एजेंसियों द्वारा निर्धारित प्रमाणन/ग्रेडिंग प्रयोजन के लिए, कटे हुए और पॉलिश किए हुए हीरों, प्रत्येक वजन 0.25 कैरेट और उससे अधिक के निर्यात की अनुमति दी जाएगी बशर्ते इनके द्वारा जारी प्रमाणपत्र/ग्रेडिंग रिपोर्ट के साथ बिना किसी आयात शुल्क के इनका पुनः आयात किया गया हो।

4क.2.1 प्रमाणन/ग्रेडिंग के लिये कटे हुए और पॉलिश किये हीरों के निर्यात के समय निर्यातक को सीमाशुल्क प्राधिकारी को यह वचनबद्धता देनी होगी कि कटे हुये और पॉलिश किये हीरों का प्रमाणन/ग्रेडिंग के लिए निर्यात के तीन माह के भीतर पुनः आयात किया जायेगा।

निर्यात बाजार में प्रमाणन/ग्रेडिंग के लिए निर्यात किए जाने वाले प्रत्येक हीरे के अनुमानित मूल्य, ऊंचाई, परिधि, भार का स्पष्ट उल्लेख किया जाये ताकि उनके आयात के समय उनकी पहचान के लिए उक्त विनिर्देशन के साथ मूल की तुलना की जा सके। बाद में, इन कटे और पॉलिश किए हीरों का नीति के प्रावधानों के अनुसार निर्यात किया जा सके।

स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम के आभूषणों के लिए स्कीम

4क.3 स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम के आभूषणों और उनकी वस्तुओं के निर्यातक इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार

स्वर्ण, प्लेटिनम, चांदी, मार्बेटिंग्स, फाइंडिंग्स, अपरिष्कृत रत्न, कीमती और अर्द्ध-कीमती पत्थर सिन्थेटिक पत्थर और असंसाधित मोती आदि जैसी अपनी अनिवार्य निविदियों का आयात कर सकते हैं।

नामित एजेंसियां

4क.4 स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम आभूषणों और उनकी वस्तुओं की स्कीमों का लाभ उठाने वाले निर्यातक (ई ओ यू/एस ई जेड स्कीम के तहत संचालित इकाइयों को छोड़कर) नामित एजेंसियों से स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम प्राप्त कर सकते हैं। नामित एजेंसियां ये हैं—एमएमटीसी लिमिटेड, हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम (एच एच ई सी), राज्य व्यापार निगम (एस टी सी), भारतीय परियोजन और उपकरण निगम लिमिटेड (पी ई सी) पांच सितारा निर्यात सदन नीति के पैराग्राफ 3.5.2 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य एजेंसी।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत बैंक मानक स्वर्ण छड़ों के रूप में शोधन और आयात हेतु स्वर्ण छीजन का आयात कर सकता है। सोने के आयात के विषय में विस्तृत प्रक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पृथक रूप से अधिसूचित मार्ग निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

निर्यात की मंदा

4क.5 निम्नलिखित मदों का, यदि निर्यात किया जाता है, तो वे इन स्कीमों के अन्तर्गत रत्न और आभूषण क्षेत्र हेतु पैरा-4क के तहत स्कीमों की सुविधाओं के लिए पात्र होंगी :

(क) 8 कैरेट या अधिक सोना वाले सोने के जेवरात चाहे सादे हों अथवा जड़ित जिनमें आंशिक रूप से संसाधित आभूषणों तथा ऐसी अन्य वस्तुएं जिनमें तमगे एवं सिक्के शामिल हैं (इनमें कानूनी निविदा किस्म के सिक्के शामिल नहीं हैं)

(ख) भार के रूप में 50 प्रतिशत से अधिक चांदी वाले आंशिक रूप से संसाधित आभूषण सहित चांदी के जेवरात, चांदी के बर्तन, चांदी के स्ट्रिप्स और वस्तुएं इसमें मैडल और सिक्के शामिल हैं (इनमें वेध टेंडर वाले सिक्के और कोई इंजीनियरी माल शामिल नहीं हैं)।

(ग) भार के रूप में 50 प्रतिशत से अधिक भार प्लेटिनम वाले जेवरात जिनमें आंशिक रूप से संसाधित आभूषण तथा ऐसी अन्य वस्तुएं जिनमें तमगे एवं सिक्के शामिल हैं (इनमें कानूनी निविदा किस्म के सिक्के व इंजीनियरिंग माल शामिल नहीं हैं)।

मूल्य परिवर्धन

4क.6 रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए मूल्य परिवर्धन प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैरा 4क.2.1 में दिए अनुसार होगी।

ए-बी

बी.ए. = ----- × 100, जहाँ

बी

बी.ए. मूल्य परिवर्धन

ए. प्राप्त निर्यात का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य/प्राप्त आपूर्ति का रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य

बी. लागत बीमा भाड़ा मूल्य अर्थात् रत्न आदि जैसे अन्य मदों के मूल्य सहित अनुमत अवशिष्ट के साथ निर्यात उत्पाद में स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम अंश का मूल्य/जहाँ कहीं भी सोने को ऋण आधार पर दिया गया है, विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा मुक्त विदेशी मुद्रा में ब्याज के भुगतान को भी लागत बीमा भाड़ा मूल्य में शामिल किया जाएगा।

छीजन मानदंड

4क.7 सोने/चांदी/प्लेटिनम जेवरात के लिए स्कीमों के तहत, विनिर्माण अपशेष अथवा छीजन प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैरा 4क.2 में विनिर्दिष्ट के अनुसार अनुमत होगी।

विदेशी क्रेता द्वारा आपूर्ति के प्रति निर्यात

4क.8 जहाँ निर्यात आदेश, तीन वर्ष के अनुभव वाले नामित एजेंसी/स्तर/धारियों/निर्यातकों जिन्होंने पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान 5 करोड़ का कारोबार किया है, को दिया जाता है वहां विदेशी क्रेता विनिर्माण और निर्यात के लिए स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम, एलॉय, चांदी/स्वर्ण/प्लेटिनम की फाइंडिंग्स और मार्बेटिंग का अग्रिम और प्रभार मुक्त रूप में नामित एजेंसियों/स्तर धारकों/निर्यातकों को आपूर्ति कर सकता है।

नामित अधिकरणों द्वारा सीधे या उनकी सहयोगी कम्पनियों या स्तरधारियों/निर्यातकों जैसी भी स्थिति हो, के माध्यम से निर्यात किया जा सकता है। फाइंडिंग्स का आयात और निर्यात नेट टू नेट आधार पर किया जाएगा। विदेश क्रेता, नामित एजेंसियों/स्तरधारियों/निर्यातकों को सादे, अर्ध परिष्कृत सोना/चांदी/प्लेटिनम आभूषण जिनमें मरम्मत/पुनःनिर्माण और निर्यात के लिए फाइंडिंग/माउंटिंग/कम्पोजेन्ट्स शामिल हैं, की भी आपूर्ति (अग्रिम और प्रभार मुक्त रूप से) कर सकता है बशर्ते कि न्यूनतम मूल्य संवर्धन 10 प्रतिशत हो। तथापि, यदि इस प्रकार के आयातित अर्ध परिष्कृत सोना/चांदी/प्लेटिनम आभूषणों का जड़ित आभूषण के रूप में निर्यात किया जा सकता है। उनका मूल्य संवर्धन 15 प्रतिशत प्राप्त किया जायेगा। निर्यात के ऐसे मामलों में 2 प्रतिशत के छीजन की अनुमति होती है।

इस संबंध में प्रक्रिया, प्रक्रिया-पुस्तक (खण्ड-1) में दिए अनुसार होगी।

नामित एजेंसियों द्वारा आपूर्ति के प्रति निर्यात

4क.9 निर्यातक, इस संबंध में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार निर्यात उत्पादों के लिए सोने/चांदी/प्लेटिनम को निवेश के रूप में अग्रिम अथवा निर्यात के बाद प्रतिपूर्ति के तौर पर नामित एजेंसियों से प्राप्त कर सकता है।

अग्रिम प्राधिकार पत्र के प्रति निर्यात

4क.10 निम्नलिखित हेतु शुल्क मुक्त आयात के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र दिया जा सकता है:—

(क) कम से कम 0.995 शुद्धता का सोना, और 8 कैरेट

और अधिक के माउन्टिंग्स, साकेट्स, फ्रेम्स एवं फाइंडिंग्स।

(ख) कम से कम 0.995 शुद्धता की चांदी माउन्टिंग्स, साकेट्स, फ्रेम्स एवं फाइंडिंग्स जिनमें भार में 50 प्रतिशत से अधिक चांदी हो।

(ग) कम से कम 0.900 शुद्धता का प्लेटिनम, माउन्टिंग्स, साकेट्स, फ्रेम्स एवं फाइंडिंग्स जिनमें भार में 50 प्रतिशत से अधिक प्लेटिनम हो।

4क.11 ऐसे प्राधिकार पत्र निर्यात दायित्व की शर्त रहेगी जिसे इस संबंध में प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4क में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार पूरा करना अपेक्षित होगा।

अग्रिम प्राधिकार पत्र इस बारे में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार सीधे आयात के बदले नाभित एजेंसियों से सोना/चांदी/प्लेटिनम प्राप्त कर सकते हैं।

रत्न प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र

4क.12 नीति के पैरा 4क.8, 4क.9 और 4क.10 में दिए गए स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम आभूषण और उनसे बनी वस्तुओं के निर्यात के लिए स्कीमों के तहत रत्न प्रतिपूर्ति (रत्न और आभूषण प्रतिपूर्ति) प्राधिकार पत्र जारी किया जा सकता है। सादा स्वर्ण/प्लेटिनम/चांदी जेवरात और उनकी वस्तुओं के मामले में, ऐसे प्राधिकार पत्र का मूल्य, निर्धारित न्यूनतम मूल्य परिवर्धन से अधिक की वसूली के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा।

जड़ित स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम जेवरात और उनकी वस्तुओं के मामले में, अनुमेय वेस्टेज समेत स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम/चांदी पर मूल्य परिवर्धन का हिसाब लगाने के बाद, निर्यातित मर्चों में उपयुक्त जड़ितों के मूल्य को ध्यान में रखकर रत्न प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र का मूल्य निर्धारित किया जाएगा।

ऐसे रत्न प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र मुक्त रूप से हस्तान्तरणीय होंगे।

रत्न प्रतिपूर्ति दर और मद

4क.13 प्रतिपूर्ति का पैमाना और आयात की मद, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट 12ख के अनुसार निर्धारित होगी।

हीरा अग्रदाय प्राधिकार पत्र

4क.14 कटे और पालिश किये हीरों, आधे कटे हीरे, किसी भी रूप में कटे हुए सहित मिश्रण के लिए यदि अपेक्षित हो, कटे और पालिश किए हुए हीरों, के आयात और कटे और पालिश किये हीरों के निर्यात के लिए हीरा अग्रदाय प्राधिकार पत्र जारी किया जा सकता है।

ऐसे प्राधिकार पत्रों के तहत निर्यात दायित्व की पूर्ति, इस बारे में जारी प्रक्रिया के अनुसार करनी होगी।

पात्रता

4क.14.1 कटे और पालिश किए हीरों के निर्यातक जो स्तरधारी हो, को कटे और पालिश किए हीरों के पिछले वर्ष के निर्यात निष्पादन के 5 प्रतिशत तक कटे और पालिश किए हीरों के आयात के लिए प्राधिकार पत्र जारी किया जा सकता है।

निर्यात दायित्व

4क.14.2 स्कीम के तहत निर्यात दायित्व प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के अध्याय 4 के पैराग्राफ 4क के प्राधान्यों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

निर्यात संवर्धन दौरे/ब्राण्डेड आभूषणों का निर्यात

4क.15 वाणिज्य विभाग की अनुमति से नामित एजेंसियों और उनके सहयोगी तथा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिपद की अनुमति से अन्य, विदेशों में प्रदर्शनी आयोजित करने/भाग लेने के लिए स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम आभूषण और उनसे बनी वस्तुओं का निर्यात कर सकते हैं।

स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम आभूषण कीमतों, अर्द्ध कीमती पत्थरों, मधियों और वस्तुओं तथा ब्राण्डेड आभूषण को व्यक्तिगत तौर पर ले जाने की अनुमति है। ये निर्यात प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में दी गई शर्तों के अधीन होंगे।

निर्यात/आयात पार्सलों को व्यक्तिगत तौर पर लाना-ले जाना

4क.16 विदेश जाने वाले यात्रियों द्वारा रत्न और आभूषण के निर्यात पार्सलों तथा किसी भारतीय आयातक/विदेशी द्वारा रत्न और आभूषण को व्यक्तिगत तौर पर प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार लाने-ले जाने की अनुमति होगी।

डाक द्वारा निर्यात

4क.17 विदेशी डाकघर के माध्यम से निर्यात के मामले में जिसमें विदेशी डाकघर के माध्यम से स्पीड पोस्ट के द्वारा भी निर्यात शामिल है, आभूषण के पार्सल का मूल्य 50,000 अमरीकी डालर तथा भार में 20 कि.ग्रा. से ज्यादा नहीं होगा। विस्तृत प्रक्रिया, पुस्तक (खण्ड-1) के अध्याय-4 में दिया गया है।

निजी/सार्वजनिक ब्रांडेड गोदाम

4क.18 कटे और पालिश किए गए हीरों, कटे और पालिश किए गए रंगीन रत्नों, अनकटे और सेट न किए हुए बहुमूल्य और अर्ध-बहुमूल्य पत्थरों के आयात और पुनः निर्यात के लिए एस ई जैड/डी टी ए में निजी एवं सार्वजनिक ब्रांडेड गोदाम स्थापित किए जा सकते हैं। कटे और पालिश किए गए हीरों और कटे और पालिश किए गए रंगदार रत्नों का आयात और पुनः निर्यात 5 प्रतिशत के न्यूनतम मूल्य संवर्धन की प्राप्ति के अधीन होगा।

हीरा और जवाहरात डॉलर खाते

4क.19 अपरिष्कृत या कटे और पालिश किए हीरों/रत्नों के सादे आभूषण, मीनाकारी और/या हीरे से जड़ित/अजड़ित और/या अन्य

पत्थर की खरीद/बिक्री करने वाली फर्मों तथा कम्पनियों जिनका हीरों के आयात या निर्यात में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव है और पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान 5 करोड़ या इससे अधिक का वार्षिक औसत कारोबार है, के नामजद हीरा डॉलर खातों के जरिये अपना व्यापार जारी रख सकती है।

हीरा डॉलर लेखा स्कीम इस अध्याय के चालू लाइसेंसिंग स्कीम के अन्तर्गत चलाई जाएगी। यह स्कीम वैकल्पिक होगी तथा जो आयातक/निर्यातक जो रुपये खाते को चालू रखना चाहते हैं, मौजूदा नीतियों के अन्तर्गत उन्हें इसकी अनुमति दी जाएगी।

ऐसे खातों में डॉलर, बैंक बिल और/या निर्यात आय से उपलब्ध होगा और इनका प्रयोग केवल

- (1) विदेशी/स्थानीय स्रोतों से अपरिष्कृत हीरों की आयात/खरीद,
- (2) स्थानीय स्रोतों से कटे और पालिश हीरों, रंगीन रत्न और सादे स्वर्ण आभूषणों की खरीद,
- (3) विदेशी/नामित एजेन्सियों से स्वर्ण का आयात/खरीद तथा बैंक से डॉलर में पुनः का भुगतान, और
- (4) निर्यातकों को रुपये लेखा में हस्तांतरण। इस हीरा डॉलर खाता योजना (डी डी ए एस) के ब्यौरे प्रक्रिया पुस्तक (खंड-1) में दिये गये हैं। प्रक्रिया पुस्तक (खंड-1) में उल्लिखित प्रक्रिया हीरा जड़ित आभूषणों पर भी लागू होगी। प्रक्रिया पुस्तक (खंड-1) में रंखांकित प्रक्रिया हीरा जड़ित आभूषणों पर लागू होगी।

एक गैर डी डी ए धारक को भी कटे हुए एवं पालिश किए हुए हीरों की प्रतिपूर्ति करने की अनुमति है, भुगतान डालर में मिलेगा तथा इसे 7 दिन के भीतर रुपयों में बदलना होगा। कटे हुए एवं पालिश किए हुए हीरों की गैर डी डी ए धारक द्वारा की गई प्रतिपूर्ति को भी उसके निर्यात दायित्व को पूरा किया गया ही माना जाएगा और/या इसे प्रतिपूर्ति लाइसेंस का हक प्राप्त हो जाएगा।

परिशोधन एवं पुनः आयात के लिए कटे एवं पालिश किए हुए बहुमूल्य और अर्ध-बहुमूल्य पत्थरों का निर्यात

4क. 20.1 रत्न एवं आभूषण निर्यातकों को परिशोधन तथा पुनः आयात के लिए कटे एवं पालिश किए हुए बहुमूल्य और अर्ध-बहुमूल्य पत्थरों का निर्यात सीमाशुल्क नियमावली एवं विनियमों के अनुसार घोषणा करेगा :

आभूषणों को गलाने और पुनः निर्यात करने के लिए बहुमूल्य मेटल स्क्रेप/उपयोग किए गए आभूषणों का आयात

4क. 21 प्रक्रिया पुस्तक खंड-1 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार गलाने, परिमार्जन और आभूषण के पुनः निर्यात के लिए बहुमूल्य मेटल स्क्रेप उपयोग किए गए आभूषणों के आयात की अनुमति होगी। तथापि हैण्ड बैगेज के जरिये आयात की अनुमति नहीं होगी।

अस्वीकृत आभूषण का पुनः आयात

4क. 22 रत्न एवं आभूषण निर्यातकों को प्रक्रिया-पुस्तक, खंड-1 के पैरा 4क. 32 के 4क. 32.1 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अस्वीकृत बहुमूल्य धातु आभूषण के पुनः आयात की अनुमति होगी।

खेप आधार पर आभूषण का निर्यात

4क. 23 रत्न एवं आभूषण निर्यातकों को प्रक्रिया-पुस्तक, खंड-1 के अध्याय 4 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार और इस संबंध में सीमाशुल्क नियमावली और विनियमों के अनुसार खेप आधार पर आभूषण के निर्यात की अनुमति होगी।

अध्याय-5

निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल स्कीम

ईपीसीजी स्कीम

5.1 पूर्व उत्पादन, उत्पादन और पश्च उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं (कम्प्यूटर साफ्टवेयर सिस्टम के साथ उनके एस के डी/सी के डी समेत) का 5 प्रतिशत सीमाशुल्क के आधार पर इस योजना के तहत आयात किया जा सकता है बशर्ते कि लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 8 वर्षों तक ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के तहत आयातित पूंजीगत माल पर बचाए गए शुल्क के 8 गुणा के बराबर निर्यात दायित्व की पूर्ति की जाए।

कृषि यूनियों के मामले में, 5 प्रतिशत सीमाशुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं का आयात अनुमत होगा बशर्ते कि लाइसेंस जारी होने की तिथि से 12 वर्षों तक बचाए गए शुल्क (स्कीम के तहत आयातित पूंजीगत वस्तुओं पर) के 6 गुणा के बराबर निर्यात दायित्व की पूर्ति की गयी हो।

तथापि, लघु उद्योग एककों हेतु, लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 8 वर्षों तक, (स्कीम के तहत आयातित पूंजीगत माल पर) बचाए गए शुल्क के 6 गुणा के बराबर निर्यात दायित्व पूरा करने के अधीन, 5 प्रतिशत सीमाशुल्क पर पूंजीगत माल के आयात की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि स्कीम के तहत ऐसे आयातित पूंजीगत माल का पत्तन पर उतरते समय लागत बीमा भाड़ा मूल्य 25 लाख रुपये से ज्यादा न हो तथा ऐसे आयातों के पश्चात् प्लांट और मशीनरी में कुल निवेश उद्योग एककों के निवेश सीमा से अधिक न हो।

तथापि, 100 करोड़ या इससे अधिक के बचाए गए शुल्क वाले ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के संबंध में निर्यात दायित्व 12 वर्षों की अवधि में पूरा करना अपेक्षित होगा।

यदि ई पी सी जी स्कीम के तहत आयातों पर सी वी डी नकद रूप में अदा किया गया है तो, सी वी डी बचाए गए निवल शुल्क के लिए नहीं लिया जाएगा बशर्ते कि इसे सेन्वेट न किया गया हो।

पूंजीगत माल में स्पेयर्स, (नवीकृत स्पेयर्स सहित) औजार, जिंक्स, फिक्चर, डाइज और माउलडस शामिल होंगे। लाइसेंसधारक द्वारा पूंजीगत वस्तुओं के एसेम्बल या विनिर्माण हेतु ऐसी पूंजीगत वस्तुओं के हिस्से-पुर्जों के आयात के लिए ईपीसीजी लाइसेंस भी जारी किया जा सकता है।

ई पी सी जी स्कीम के अधीन पुराने माल का कालावधि पर बिना किसी प्रतिबंध के आयात किया जा सकता है।

तथापि मोटर कारों, खेल कूद के लिए उपयोगी वाहनों/बहुउद्देशीय वाहनों के आयात की अनुमति केवल होटलों, टूर एजेंटों, टूर प्रचालकों अथवा टूर परिवहन प्रचालकों और गोल्फ रिजर्वर्स या स्वामित्व रखने वाली/संचालन करने वाली कम्पनियों को होगी जिनका चालू और पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में कुल विदेशी मुद्रा अर्जन 1.5 करोड़ रुपये हो। मोटर कारों, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी वाहनों/सभी प्रयोजनों के वाहनों के आयात हेतु लाइसेंसिंग वर्ष में जारी सभी ईपीसीजी प्राधिकारों पर 'बढ़ाई शुल्क' राशि विगत तीन लाइसेंसिंग वर्षों में होटल, ट्रेवल और टूरिज़्म और गोल्फ टूरिज़्म क्षेत्रों से औसत विदेशी मुद्रा के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। तथापि मोटर कारों, खेल कूद के लिए उपयोगी वाहनों/बहुउद्देशीय वाहनों के पूर्णों जैसे कि चैसिस इत्यादि ईपीसीजी स्कीम के तहत आयात नहीं किए जा सकते।

आईटीसी (एच एस) के अन्तर्गत उल्लिखित प्रतिबंधित मालों के आयात की अनुमति आयात सुविधा समिति से अनुमोदन के बाद स्कीम के तहत दी जाएगी।

5.1क स्कीम के तहत मौजूदा प्लांट और मशीनरी के लिए आयातित/आयात किए जाने वाले स्पेयर्स (नवोद्भूत/रीफर्बिस्ट स्पेयर्स सहित), औजार, स्पेयर रिफैक्टरीज, उत्प्रेरक और उपभोग्यों की भी अनुमति दी जाएगी चर्चते कि प्राधिकार पत्र जारी होने की तिथि से 8 वर्षों तक की अवधि में निर्यात दायित्व बचाए गए शुल्क के 8 गुणा के बराबर हो।

परियोजनाओं के लिए ईपीसीजी

5.1ख स्कीम के तहत परियोजनाओं के आयात हेतु अधिसूचना सं. 21/2002 दिनांक 1-3-2002 के क्रम सं. 441 के तहत पूंजीगत माल के आयात के लिए ईपीसीजी लाइसेंस भी जारी किया जा सकता है जो कि सीमाशुल्क छूट प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित हैं जिसमें आयातों पर मूल सीमाशुल्क 10 प्रतिशत की सीवीडी के साथ 10 प्रतिशत है।

ऐसे ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों के लिए निर्यात दायित्व बचाए गए शुल्क का आठ गुणा होगा। बचाया गया शुल्क उपर्युक्त सीमाशुल्क अधिसूचना के तहत प्रभावी शुल्क और ईपीसीजी स्कीम के तहत रियायती शुल्क के बीच का अन्तर होगा।

खुदरा क्षेत्र हेतु ई पी सी जी

5.1ग खुदरा क्षेत्र में आधुनिक आधारभूत ढांचा तैयार करने हेतु खुदरा व्यापारी जिनके पास न्यूनतम आच्छादित क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर है, पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए ई पी सी जी स्कीम के तहत रियायती शुल्क का लाभ दिया जा सकता है। खुदरा व्यापारी को निर्यात दायित्व अर्थात् 8 वर्षों में बचाए गए शुल्क का 8 गुणा पूरा करना होगा।

धारा 5

5.2 इस स्कीम के अंतर्गत सहायक विनिर्माता(ओं) सहित प्रत्येक उनके बिना विनिर्माता निर्यातक/विक्रेता(ओं), सहायक

विनिर्माता(ओं) से जुड़े व्यापारी निर्यातक और सेवा प्रदायक पूंजीगत माल का आयात करने के पात्र हैं।

पूंजीगत माल के आयात की शर्तें

5.3 पूंजीगत माल का आयात, निर्यात दायित्व की पूर्ति तक वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन होगा।

निर्यात दायित्व

5.4 स्कीम के अंतर्गत निर्यात दायित्व पूरा करने के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी :-

(1) स्कीम के अन्तर्गत आयातित पूंजीगत वस्तुओं के प्रयोग द्वारा विनिर्मित या उत्पादित ऐसी वस्तुओं के निर्यात द्वारा निर्यात दायित्व पूरा किया जाएगा।

उन्हीं वस्तुओं के निर्यात द्वारा भी, जिसके लिए ई पी सी जी प्राधिकार पत्र प्राप्त किया गया है निर्यात दायित्व पूरा किया जा सकता है जिनमें लाइसेंसधारक/विनिर्दिष्ट सहायक विनिर्माता(ओं) की विभिन्न विनिर्माण यूनिटों से प्राप्त, विनिर्मित अथवा उत्पादित किया गया हो।

जब पूंजीगत माल पूर्व/पश्च उत्पादन के लिए आयात किए गए हों और लाइसेंस स्पेयर्स के आयात के लिए लिया गया है तो लाइसेंस धारक उस संयंत्र/परियोजना से विनिर्मित उत्पादों के निर्यात द्वारा निर्यात दायित्व पूरा करेगा कि जिससे पूर्व/पश्च उत्पादन पूंजीगत माल में समाविष्ट संबंधित है।

ई पी सी जी प्राधिकार पत्र धारक द्वारा निर्यात के लिए दी गई सेवाओं अथवा विनिर्मित उत्पादों के लिए भंडारण और वितरण सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए पूंजीगत माल के आयात की अनुमति ई पी सी जी प्राधिकार पत्र के तहत होगी।

इस योजना के अन्तर्गत निर्यात दायित्व विगत तीन लाइसेंसिंग वर्षों में बढ़ाई गयी अवधि यदि कोई हो, सहित कुल निर्यात दायित्व अवधि के अन्दर में उसके द्वारा प्राप्त किए गए उसी उत्पाद और सामान उत्पाद प्रक्रिया पुस्तक (खंड-1) में उल्लिखित श्रेणियों को छोड़कर, के निर्यातों के औसत स्तर से ज्यादा होगा।

वैकल्पिक रूप से, ई पी सी जी प्राधिकार पत्र धारक द्वारा उसी फर्म/कम्पनी अथवा समूह कम्पनी/प्रबंधित होटल जिनके पास ई पी सी जी लाइसेंस है, में विनिर्मित या प्राप्त अन्य मालों/सेवाओं के निर्यातों द्वारा भी निर्यात दायित्व पूरा किया जा सकेगा।

तथापि, ऐसे मामलों में, ई पी सी जी स्कीम के तहत लगाया गया अतिरिक्त निर्यात दायित्व मूल और स्थानापन्न उत्पाद(ों)/सेवा(ओं) दोनों हेतु पिछले तीन वर्षों में यूनिट/कम्पनी/समूह कम्पनी/प्रबंधित होटल द्वारा किए गए औसत निर्यातों से अधिक होगा, यहां तक कि उन मामलों में भी जहां प्रक्रिया पुस्तक (खंड-1) के पैरा 5.7.6 में दिए गए वैकल्पिक उत्पाद(ओं)/सेवा(ओं) के लिए औसत में छूट है।

शेष निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए प्राधिकार पत्र धारक द्वारा पूरे किए जाने वाले बढ़ रहे निर्यातों में निर्यातों का वास्तविक उत्पाद/सेवा और वैकल्पिक उत्पाद (ओं)/सेवा (ओं) का कोई भी

संयोजन हो सकता है। माल का निर्यातक सेवाओं के निर्यात अथवा विलोमतः निर्यात दायित्व पुनः नियत करने का विकल्प चुन सकता है।

लाइसेंसधारक स्कीम के तहत शेष निर्यात दायित्व के अनुपात में लागत बीमा भाड़ा मूल्य के लिए बचाई गई शुल्क राशि के 8 गुणा पर आधारित शेष निर्यात दायित्व को पुनः नियत करने के लिए विकल्प चुन सकता है। निर्यात दायित्व के पुनः निर्धारण के लिए दिशानिर्देश प्रक्रिया-पुस्तक (खण्ड-1) के पैरा 5.19 में दी गई है।

उपर्युक्त सुविधाएं केवल विनिर्माता निर्यातकों/सेवा प्रदायकों को सभी लाइसेंसों पर उपलब्ध होंगी जहां बचाई गई निर्यात दायित्व अवधि सहित निर्यात दायित्व अवधि आवेदन की तारीख पर वैध है। इस संबंध में वैकल्पिक मद और/या बचाई गई शुल्क राशि पर आधारित निर्यात दायित्व के पुनः निर्धारण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने पर अथवा उसके बाद किए गए निर्यातों को निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए माना जाएगा।

- (2) इस स्कीम के अधीन प्राप्त किए गए निर्यात दायित्व आयातक द्वारा अग्रिम लाइसेंस, डी एफ आर सी, डी ई पी बी या ड्रॉबैक योजना के अधीन समान उत्पाद के लिए प्राप्त किए गए निर्यात दायित्व के अतिरिक्त होगा।
- (3) निर्यात दायित्व डीटीए को आईटीए-1 की आपूर्ति द्वारा भी पूरा किया जा सकता है बशर्ते कि वसूली मुक्त विदेशी मुद्रा में हो।
- (4) निर्यात वास्तविक निर्यात होंगे। तथापि नीति के पैराग्राफ 8.2 (क), (ख), (घ), (च), (छ) और (ज) में यथाउल्लिखित मान्य निर्यात भी नीति के पैरा 8.3 के तहत उपलब्ध सामान्य लाभों के साथ निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए माने जाएंगे।

आर एण्ड डी सेवाओं के लिए प्राप्त मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा और विदेशी मुद्रा में प्राप्त रॉयल्टी भुगतान भी ईपीसीजी स्कीम के तहत वसूली के लिए माने जाएंगे। विदेश व्यापार नीति के अध्याय 9 के संबंध में, पतन निर्वहन सेवाओं के लिए रुपए के रूप में प्राप्त भुगतान भी, स्कीम के तहत निर्यात दायित्व पूर्ति के लिए माना जाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंकिंग चैनलों के माध्यम से मुक्त विदेशी मुद्रा में 'काउण्टर बिक्री' से प्राप्त भुगतान, निर्यात दायित्व की पूर्ति पैरा 5.1 ग के अनुसार गिनी जाएगी।

बीआईएफआर यूनिटों के लिए प्रावधान

5.5.1 बीआईएफआर के साथ पंजीकृत कोई फर्म/कम्पनी या यूनिट खरीदने वाली कोई फर्म/कम्पनी, जो कि बीआईएफआर के अधीन है, को संचालित करने वाली एजेन्सी द्वारा तैयार एवं बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित पुनः स्थापना पैकेज के अनुसार निर्यात दायित्व बढ़ाने की अनुमति होगी।

तथापि, ऐसे मामलों में, जहां पुनः स्थापना पैकेज में निर्यात दायित्व विस्तार की अवधि का उल्लेख न हो, वहां निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए मामले के गुणावगुण के आधार पर लाइसेंस जारी करने की तारीख से 12 वर्षों की समयवधि अनुमत होगी।

इसी प्रकार, लघु उद्योग इकाइयां भी संबंधित राज्य सरकार की पुनः स्थापना योजना के अनुसार ऐसी ही सुविधा के लिए हकदार होंगी। तथापि, ऐसे मामलों में जहां राज्य पुनः स्थापना योजना में निर्यात दायित्व विस्तार अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई वहां निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए मामले के गुण-दोष के आधार पर प्राधिकार पत्र जारी करने की तारीख से 12 वर्षों की समयवधि अनुमत होगी।

एग्री इकाइयों के लिए ई पी सी जी

5.5.2 कृषि निर्यात क्षेत्रों में कृषि इकाइयों को जारी ई पी सी जी प्राधिकार पत्र के मामले में, निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए प्राधिकार-पत्रों को जारी करने की तारीख से 12 वर्षों की समयवधि अनुमत होगी।

कृषि निर्यात क्षेत्रों में कृषि इकाइयों को कृषि निर्यात क्षेत्र के भीतर ई पी सी जी के तहत आयातित पूंजीगत माल (i) के स्थानान्तरण की सुविधा भी होगी।

विधिक वचनबद्धता/बांड पत्र या 15 प्रतिशत बैंक गारंटी (जैसा भी मामला हो) ई पी सी जी प्राधिकार पत्र के लिए दिया जा सकता है जो कि कृषि निर्यात क्षेत्रों में इकाइयों को दिया गया है। बशर्ते कि ई पी सी जी प्राधिकार पत्र परिशिष्ट 8 में अधिसूचित मुख्य कृषि उत्पाद (i) अथवा उनकी मूल्य संवर्धन वस्तुओं के निर्यात के लिए लिया गया है। स्वदेशी रूप से पूंजीगत माल को प्राप्त करना और घरेलू आपूर्तिकर्ता को लाभ

5.6 ई पी सी जी प्राधिकार पत्र धारक व्यक्ति वस्तुएं आयात करने के बजाए इन्हें घरेलू निर्माता से प्राप्त कर सकता है। ई पी सी जी प्राधिकार पत्रधारक को पूंजीगत वस्तुओं की आपूर्ति करने वाला घरेलू विनिर्माता नीति के पैरा 8.3 के तहत मान्य निर्यात लाभ पाने का पात्र होगा।

घरेलू आपूर्तिकर्ता को लाभ

ई पी सी जी प्राधिकार पत्र और घरेलू विनिर्माता के बीच ऐसे वस्तुओं की प्राप्ति के लिए हुए फर्म के करार के मामले में, घरेलू निर्माता उक्त पूंजीगत वस्तुओं के विनिर्माण हेतु आवश्यक संघटकों सहित निविष्टियों के आयात हेतु अग्रिम लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन कर सकता है।

घरेलू विनिर्माता ई पी सी जी प्राधिकार पत्र धारक को पूंजीगत माल की आपूर्ति के बाद संघटकों सहित निविष्टियों की प्रतिपूर्ति भी कर सकता है।

निर्यात दायित्व का निर्धारण

5.7क सीधे आयात के मामले में, ई पी सी जी प्राधिकार पत्र के संबंध में निर्यात दायित्व को वास्तव में आयातित पूंजीगत माल (इसमें स्वेयर्स, जिग्स, फिक्स्चर्स, डाइज और मोल्ड्स शामिल हैं) के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य पर बचाये गए शुल्क के अनुसार होगा। घरेलू प्राप्ति के मामले में ई पी सी जी प्राधिकार पत्र के संबंध में निर्यात दायित्व को पूंजीगत माल (इसमें स्वेयर्स, जिग्स, फिक्स्चर्स, डाइज और मोल्ड्स शामिल हैं) के रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य पर बचाए गए केन्द्रीय सीमा शुल्क के अनुसार होगा।

5.8 कृषि निर्यात जोन में सेवा प्रदायक को कृषि निर्यात जोन के भीतर पूंजीगत माल को हटाने या दूसरी जगह ले जाने की सुविधा होगी बशर्ते कि यह ऐसे कार्यकलापों का सही रिकार्ड रखे। तथापि, प्राधिकार पत्र धारक द्वारा ऐसे उपकरण बेचे या लीज पर नहीं दिए जाएंगे।

ईपीसीजी के तहत औसत निर्यातों का रखरखाव

5.9 पैरा 5.4 (इ) की शर्तों के अनुसार, ई पी सी जी प्राधिकार पत्र धारक को निर्यात दायित्व की सम्पूर्ण अवधि के दौरान प्रक्रिया-पुस्तक (खण्ड-1) में दी गई छूट प्राप्त श्रेणियों को छोड़ कर उसी अथवा समान उत्पादों के लिए पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में निर्यातों के औसत के बराबर निर्यातों के औसत स्तर को बनाए रखना होगा।

उपर्युक्त के बावजूद, लाइसेंसधारक किसी विशेष वर्ष(1) में औसत निर्यातों का स्तर बनाए रखेंगे बशर्ते कि यह अन्य वर्ष(1) में औसत पूरा करने के लिए अतिरिक्त निर्यातों द्वारा पूरा किया गया हो।

5.9.1 हटा दिया गया है।

मौजूदा ई पी सी जी मशीनरी का तकनीकी उन्नयन

5.10 ई पी सी जी लाइसेंसधारक ई पी सी जी लाइसेंस के तहत आयातित मौजूदा पूंजीगत माल के तकनीकी उन्नयन का चुनाव कर सकता है।

मौजूदा पूंजीगत माल के तकनीकी उन्नयन को संचालित करने की शर्त निम्नानुसार है :—

- (1) ई पी सी जी के तहत आयातित मौजूदा पूंजीगत माल के तकनीकी उन्नयन के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम समयावधि लाइसेंस जारी करने की तारीख से 5 वर्ष है।
- (2) पुराने पूंजीगत माल के तहत किए गए न्यूनतम निर्यात पहले ई पी सी जी लाइसेंस पर लगाए गए कुल निर्यात दायित्व का 40 प्रतिशत होना चाहिए।
- (3) निर्यात दायित्व को इस प्रकार पुनः निर्धारित किया जाएगा कि दोनों पूंजीगत माल के लिए निर्धारित कुल निर्यात दायित्व दोनों पूंजीगत माल पर बचाए गए शुल्क की कुल राशि का 6 गुणा होगा।
- (4) पूंजीगत माल की पुनः स्थापना संचालित करने की प्रक्रिया, प्रक्रिया-पुस्तक (खण्ड-1) के पैरा 5.20 में दी गई है।
- (5) तकनीकी उन्नयन के लिए सुविधा सिर्फ एक बार उपलब्ध होगी और किया जाने वाला न्यूनतम आयात आवेदक फर्म द्वारा प्लान्ट और मशीनरी में मौजूदा निवेश का कम से कम 10 प्रतिशत होगा।

फास्ट ट्रेक कम्पनियों के लिए प्रोत्साहन

5.11 स्कीम के तहत निर्यातों को गति प्रदान करने की दृष्टि से फास्ट ट्रेक कम्पनियों को प्रोत्साहित करने हेतु ऐसे मामलों में जहां

लाइसेंसधारक ने लाइसेंस में विनिर्दिष्ट मूल निर्यात दायित्व की अवधि के आधे या आधे से कम समय में स्कीम के तहत निर्यात दायित्व का 75 प्रतिशत अथवा अधिक पूरा कर लिया हो (निर्यातों के औसत स्तर सहित), बकाया निर्यात दायित्व को माफ कर दिया जाएगा और संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस को विमुक्त कर दिया जाएगा।

तथापि, ऐसे मामलों में प्रक्रिया-पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 5.12 के अन्तर्गत कोई लाभ नहीं उपलब्ध होगा।

अध्याय-छः

निर्यात अभिमुख यूनिटें (ई ओ यू) इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क (ई एच टी पी) साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क (एस टी पी) और बायो टेक्नोलोजी पार्क (बी टी पी)

पात्रता

6.1 अपने सारे उत्पादन और सेवाओं (डी टी ए में अनुमत बिक्री को छोड़कर) को निर्यात करने का दायित्व लेने वाली यूनिटें निर्यात अभिमुख यूनिट (ई. ओ. यू.) स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क (ई एच टी पी), योजना साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क (एस टी पी) योजना या बायो टेक्नोलोजी पार्क (बी टी पी) स्कीम के अन्तर्गत स्थापित की जा सकती हैं तथा ऐसी यूनिटें माल के निर्माण सहित मरम्मत, री-मेकिंग, री-कंडीशनिंग, री-इन्जीनियरिंग और सेवा प्रदान करने में लगी हो सकती हैं। तथापि इन योजनाओं के तहत व्यापारी यूनिट शामिल नहीं हैं।

माल का निर्यात तथा आयात

6.2 (क) ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात कर सकती है सिवाय उन मदों के जो आई टी सी (एच एस) में निषिद्ध हैं। विशेष रसायन, जैविक, उपकरण और तकनीकियों (एस सी ओ एम ई टी) का निर्यात किया जाएगा बशर्ते कि ये आई टी सी (एच एस) में उल्लिखित शर्तें पूरी होती हों।

निर्यात संवर्धन सामान जैसे कि ब्रोचर यथा साहित्य पैम्फलेट, होल्डिंग, कैटालोग, पोस्टर इत्यादि की खरीद और आपूर्ति पिछले वर्ष के निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क के 1.5 प्रतिशत के माल के निर्यात की भी अनुमति होगी।

(ख) एक निर्यात अभिमुख यूनिट/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट, डी टी ए अथवा डी टी ए में बाण्डेड गोदामों अथवा भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी उससे संबंधित गतिविधियों के लिए पूंजीगत माल सहित सभी प्रकार की वस्तुओं का बिना शुल्क दिए आयात कर सकती है बशर्ते कि ये आई टी सी (एच एस) में आयात की निषिद्ध मद न हो। कि अन्य कानून के तहत आयात के लिए अनुमति दी जाएगी। यूनिटों को, ग्राहकों से ऋण पर पूंजीगत वस्तुओं सहित, मुफ्त में या स्वीकृति कार्यकलापों के लिए अपेक्षित वस्तुओं के आयात की भी अनुमति होगी। पूंजीगत माल का आयात स्वप्रमाणन आधार पर होगा। एकक द्वारा मालका आयात निर्यात उत्पादन के प्रारंभिक उपयोग तथा वास्तविक उपयोक्ता शर्तों के अधीन होगा।

(ग) निर्यात अभिमुख विनिर्माण यूनिटों पर राज्य व्यापार व्यवस्था लागू नहीं होगी।

(घ) ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी में साफ्टवेयर एककों द्वारा प्रयोग के लिए केन्द्रीय सुविधा स्थापित करने हेतु कुछ विशिष्टीकृत वस्तुओं का शुल्क मुक्त रूप से आयात कर सकती है या डीटीए से प्राप्त कर सकती हैं। ये साफ्टवेयर एकक ई ओ यू/डी टी ए एकक हो सकते हैं, जो साफ्टवेयर के निर्यात की सुविधा का प्रयोग कर सकते हैं।

(ङ) कृषि, पशुपालन, जल कृषि, पुष्प उत्पादन, बागवानी, मत्स्य पालन, अंगुरोत्पादन, मूर्गीपालन अथवा रेशम उत्पादन में संलग्न निर्यात अभिमुख यूनिटों को बाण्डेड क्षेत्र के बाहर प्रयोग के लिए केवल विशिष्ट माल को ले जाने की अनुमति दी जा सकती है।

(च) रत्न और आभूषण ई ओ यू यूनिटें नामित एजेंसियों से भी सोना/चांदी/प्लेटिनम ऋण/सम्पूर्ण खरीद आधार पर प्राप्त कर सकती हैं। यूनिटें या तो सोना/चांदी/प्लेटिनम के आभूषणों का निर्यात रिलीज की तारीख से 90 दिन के अन्दर कर देंगी। हालाँकि यह नामित एजेंसियों से कीमती पत्थरों के एकमुश्त खरीद पर लागू नहीं होगा।

(छ) सेवा यूनिटों के अतिरिक्त ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट भारतीय रिजर्व बैंक की क्लियरेंस, यदि कोई हो, के अधीन राज्य ऋण के पुनः भुगतान/क्रेता के एस्को रुपया लेखा के प्रति भारतीय रुपयों में रूस संघ को निर्यात कर सकती है।

(ज) स्पेयर्स और उपभोग्यों की खरीद और आपूर्ति निर्यातों के 1.5 प्रतिशत जहाज पर्यन्त निःशुल्क के बराबर उन्हीं करारकर्ता/खरीददार निर्यात वस्तुओं के गारंटी अवधि में निर्यात की अनुमति होगी।

पुराना पूंजीगत माल

6.3 पुराना पूंजीगत माल का बिना किसी आयु सीमा के शुल्क मुक्त आयात भी किया जा सकता है।

पूँजीगत माल के पट्टे

6.4 पार्टियों के बीच में हुई पक्की संधिदा के आधार पर कोई निर्यात अभिमुख यूनिट/इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क/साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क/बी टी पी यूनिट घरेलू/विदेशी पट्टे वाली कंपनी से बिना सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क का भुगतान किए पूंजीगत माल उठा सकती है। ऐसे मामले में घरेलू/विदेशी पट्टे वाली कंपनी तथा निर्यात अभिमुख यूनिट/इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क/साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क/बी टी पी यूनिट शुल्क मुक्त पूंजीगत माल, आयात करने/खरीदने के लिए संयुक्त रूप से आयात दस्तावेज प्रस्तुत करेगी।

निवल विदेशी मुद्रा अर्जन (एन एफ ई)

6.5 ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटें प्रकिया प्रस्तक के परिशिष्ट 14-1-ग के विशेष प्रावधानों को छोड़कर जहां उच्च मूल्य संबंधन की जरूरत होगी, एक सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा

अर्जक होंगी। निवल विदेशी मुद्रा अर्जन (एन एफ ई) उत्पादन प्रारम्भ होने से पांच वर्षों की अवधि के लिए संघटित रूप से गिना जाएगा।

अनुज्ञा पत्र/आशय पत्र और विधिक वचनबद्धता

6.6 (क) अनुमोदन हो जाने पर, विकास आयुक्त/नामित अधिकारी द्वारा ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट को अनुमति पत्र (एल ओ पी)/आशय पत्र (एल ओ आई) जारी करेगा। एल ओ पी/एल ओ आई का आरम्भ में वैधता अवधि तीन वर्ष होगी जब से यूनिट ने उत्पादन आरम्भ किया होगा। इसकी वैधता अवधि को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक वैधता की अवधि से आगे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तथापि, छः वर्ष से अधिक के विस्तार के प्रस्ताव पर विशेष परिस्थितियों में अनुमोदन बोर्ड द्वारा मामला दर मामला आधार पर विचार किया जाएगा। एक बार यूनिट ने उत्पादन आरम्भ कर दिया, तो इसकी गतिविधियों के लिए जारी किए गए अनुमति पत्र/आशय पत्र 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध होंगे। इस अवधि को विकास आयुक्त द्वारा, एक बार में 5 वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

(ख) सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त पैरा 6.2 के प्रावधानों के संबंध में ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटों को जारी एल ओ पी/एल ओ आई को सभी प्रयोजन के लिए लाइसेंस माना जाएगा।

(ग) यूनिट संबंधित विकास आयुक्त को एक विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत करेगी। सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन की शर्त को अथवा एल ओ पी/एल ओ आई/आई एल/एल यू टी की शर्तों को न पूरा कर सकने पर वह विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 और किसी अन्य कानून के तहत नियम तथा आदेश जो बिना पूर्वाग्रह के बने हों, के अधीन दण्ड की भागी होगी और वह एल ओ पी/एल ओ आई/आई.एल रद्द अथवा मंसूख हो जाएगा।

निवेश मानदण्ड

(घ) जिन परियोजनाओं में संयंत्र और मशीनरी पर 1 करोड़ रुपया न्यूनतम निवेश न हो उन पर ई. ओ. यू. स्कीम के अन्तर्गत स्थापना के लिए विचार किया जाएगा। यह, हालाँकि, मौजूदा यूनिटें और ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी, हैण्डिक्राफ्ट/कृषि/पुष्पोत्पादन बागवानी/जल कृषि/पशुपालन/सूचना तकनीकी, सेवाएं ब्रास हार्डवेयर, हस्तनिर्मित आभूषण और बीओए द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य क्षेत्रों में लागू नहीं होगा।

आवेदन और अनुमोदन

6.7 ई ओ यू योजना के तहत यूनिटों की स्थापना के लिए आवेदनों पर (क) सेवा क्षेत्र (आर एण्ड डी, साफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी संबद्ध सेवाओं अथवा बी ओ ए द्वारा प्रत्यायोजित अन्य सेवा गतिविधियों को छोड़कर) की यूनिटों की स्थापना के लिए प्रस्तावों को छोड़कर, यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा 15 दिनों के भीतर मंजूरी/नामंजूरी दी जा सकती है जो प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करती हो।

(ख) अन्य मामलों में इस उद्देश्य के लिए गठित अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में निर्दिष्ट के अनुसार मंजूरी दी जाएगी।

(ग) औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता वाले ईओयू की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन, अनुमोदन बोर्ड और औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा प्रस्ताव के निपटान के बाद 45 दिन के अन्दर विकास आयुक्त द्वारा किया जा सकता है।

तैयार उत्पाद/अवशेष/स्क्रेप/शेष और उप-उत्पाद की घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डी टी ए) में बिक्री

6.8 निम्नलिखित अभिमुख यूनियों/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क/साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क/बी टी पी यूनियों का सारा उत्पादन निम्नलिखित के अधीन निर्यात किया जाएगा :—

(क) रत्न और आभूषण यूनियों का छोड़कर यूनियन निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 50 प्रतिशत तक माल का विक्रय कर सकता है बशर्ते कि रियायती शुल्क के भुगतान पर सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा की पूर्ति की गई है। डी टी ए बिक्री हकदारी के अन्दर इकाइयाँ अपने उत्पादों को डी टी ए में माल जैसे ही बेच सकती हैं। मोटर कार, अल्कोहल युक्त शराब, पुस्तकें और चाय (इन्स्टैंट को छोड़कर) और पुस्तकें या पैकेजिंग/लेबलिंग/सैग्रीगेशन/रेफ्रीजरेशन/यूनिट कम्पैक्टिंग/माइक्रोनाइजेशन/पल्वराइजेशन/ग्रेन्यूलेशन/मोनो-हाइड्रेट रूप के रसायन से एनहाइड्रस रूप में परिवर्तन अथवा विलोमन के मामले में रियायती शुल्क पर कोई डीटीए बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।

एस ई जेड में यूनियन को की गई बिक्री भी ई ओ यू द्वारा निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य को निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखी जाएगी। बशर्ते कि इन बिक्रियों हेतु किया गया भुगतान ई ई एफ सी एकाउण्ट से किया गया हो। डी टी ए को की गई बिक्री भी फार्मास्यूटिकल उत्पादों (थोक दवाइयों समेत) के पंजीकरण की अपरिहार्य आवश्यकता के मद्दे होगी।

(ख) सेवा के लिए, साफ्टवेयर यूनियों सहित, डी टी ए में किसी भी रूप में बिक्री, आनलाइन डाटा संचार सहित निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 50 प्रतिशत/अर्जित विदेशी मुद्रा के 50 प्रतिशत तक की भी अनुमति होगी, जहाँ ऐसी सेवाओं का भुगतान विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है।

(ग) रत्न और आभूषण यूनियन डी टी ए में पूर्व वर्ष के निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 10 प्रतिशत तक बेच सकती हैं बशर्ते कि नीति निवल विदेशी मुद्रा को पूरा कर लिया गया है। सादे आभूषण

की बिक्री के संबंध में, प्राप्तकर्ता नामित एजेंसियों से बिक्री पर यथा लागू शुल्क की रियायती दरों का भुगतान करेगा। रत्न जड़ित आभूषण के संबंध में, यथा लागू शुल्क का भुगतान करना होगा।

(घ) जब तक एल ओ पी में विशेष रूप से निश्चित न हुआ तो, सीमाशुल्क प्राधिकारियों की पूर्व अनुमति से पैराग्राफ 6.8 (क) के तहत यथा लागू शुल्कों के भुगतान पर, डी टी ए में रिजेक्ट्स की कुल सीमा के 50 प्रतिशत तक बिक्री की जा सकती है। ऐसी बिक्री डी टी ए बिक्री हकदारी के मद्दे गिनी जाएगी। निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5 प्रतिशत तक रिजेक्ट्स की बिक्री पर एन एफ ई प्राप्त करने की शर्त नहीं होगी।

(ङ) उत्पादन प्रक्रिया या तत्सम्बंधी प्रक्रिया से निकलने वाले स्क्रेप/अवशिष्ट/अवशेष का यथा लागू रियायती शुल्क का भुगतान करने पर डी टी ए में बिक्री अथवा निर्यात शुल्क मुक्त स्कीम के तहत अधिसूचित मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्ड के अनुसार किया जा सकता है जो निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 50 प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर होगा। लेकिन ऐसी बिक्री न्यूनतम निवल विदेशी मुद्रा अर्जन की प्राप्ति के अधीन नहीं होगी। उन मदों के संबंध में जो मानदण्ड में शामिल नहीं हैं, विकास आयुक्त आंकड़ों के आधार पर छः माह की अवधि और छः माह के भीतर की अवधि के लिए तदर्थ मानदण्ड निर्धारित कर सकता है, उसे अनुमोदन बोर्ड द्वारा मानदण्ड निर्धारित करवाने होंगे। यूनियों द्वारा जिन वेस्ट/स्क्रेप/अवशेष की बिक्री डी टी ए बिक्री की पात्रता या डी टी ए बिक्री पात्रता से बाहर बिक्री की अनुमति नहीं है उन पर शुल्क का पूर्ण भुगतान करना होगा। स्क्रेप/अवशिष्ट/अवशेष का भी निर्यात किया जा सकता है।

(च) यदि ऐसे स्क्रेप/अवशिष्ट/अवशेषों को सीमाशुल्क प्राधिकारियों की अनुमति से नष्ट किया जाता है तो उन पर कोई शुल्क/कर नहीं लगेगा।

(छ) अनुमति पत्र में शामिल उपोत्पाद की डी टी ए में भी बेचा जा सकता है बशर्ते की नीति के पैरा 6.8 (क) की समग्र हकदारी के भीतर लागू शुल्कों के भुगतान और अर्जित निवल विदेशी मुद्रा को पूरा कर लिया हो। पैरा 6.8 (क) की हकदारी के बाहर उपोत्पाद की बिक्री सम्पूर्ण शुल्कों के भुगतान पर भी अनुमत होगी।

(ट) ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनियन तैयार उत्पादों को बेच सकते हैं जो पूर्ण शुल्क का भुगतान करके विकास आयुक्त को सूचित करके घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में नीति के तहत मुक्त रूप से आयात योग्य हैं बशर्ते यूनियन ने सकारात्मक एन एफ ई प्राप्त कर लिया हो।

(ठ) इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर निर्माण करने वाली यूनिटों के मामले में, निवल विदेशी मुद्रा और डी टी ए बिक्री हकदारी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए अलग से निर्धारित की जाएगी।

(ड) ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी द्वारा विनिर्मित वस्तुओं की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में बिक्री के मामले में जहाँ मूलशुल्क और सी वी डी शून्य है; ऐसी वस्तुओं को शुल्क के भुगतान के प्रयोजन के लिए उत्पाद कर रहित माना जाएगा।

(ण) नये ई ओ यू के मामले में अग्रिम घरेलू प्रशुल्क बिक्री की अनुमति होगी जो भेषज यूनिटों के अलावा जहाँ यह प्रथम दो वर्षों के लिए अनुमानित निर्यातों पर आधारित होगी के अतिरिक्त पहले वर्ष के लिए अनुमानित निर्यातों का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

घरेलू टैरिफ क्षेत्र में अन्य आपूर्तियाँ

6.9 अर्जित निवल विदेशी मुद्रा पूरा करने के लिए घरेलू टैरिफ क्षेत्र में ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटों से निम्नलिखित आपूर्तियों की गणना की जाएगी:—

- (क) वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम लाइसेंस/शुल्क छूट के तहत डी एफ आर सी/विमुक्ति योजना/ई पी सी जी स्कीम के धारकों के संबंध में डी टी ए में की गई आपूर्तियाँ;
- (ख) हटा दिया गया है।
- (ग) अन्य निर्यातोन्मुख इकाई/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलाजी पार्क/सॉफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क/बायोटेक्नोलाजी पार्क/एस ई जेड इकाई को आपूर्ति इन यूनिटों द्वारा ऐसे माल की खरीद के लिए अनुमति नीति के पैराग्राफ 6.2 के अन्तर्गत की जायेगी।
- (घ) नीति के और/या सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 65 के तहत स्थापित बांडेड गोदाम विशेष आर्थिक क्षेत्र की यूनिटों में की गई आपूर्तियाँ, जहाँ भुगतान विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है।
- (ङ) माल और सेवाओं की आपूर्ति ऐसे संगठनों जो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य छूट अधिसूचना के अनुसार शुल्क मुक्त आयात के हकदार हैं।
- (च) निर्यात से संबंधित सेवाओं की आपूर्ति (सेवा यूनिटों द्वारा) मुक्त विदेशी मुद्रा के लिए अथवा ऐसी सेवाओं के लिए जिनका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुक्त विदेशी मुद्रा के बदले भारतीय रुपये में किया गया हो।
- (छ) सूचना तकनीकी समझौता (आईटीए-1) मदों और अधिसूचित शून्य शुल्क टेलिकाम/इलेक्ट्रॉनिक मदों की आपूर्ति।

अन्यों के माध्यम से निर्यात

6.10 एक ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट, अपने द्वारा विकसित विनिर्मित माल/सॉफ्टवेयर का निर्यात प्रक्रिया पुस्तक के पैरा-6.19 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार दूसरे निर्यातक अथवा किसी अन्य ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/एस ई जेड यूनिट के माध्यम से कर सकती है।

डी. टी. ए. से आपूर्तियों हेतु हकदारी

6.11 (क) निर्यातोन्मुख/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलाजी पार्क/सॉफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क/बी टी पी की यूनिटों को घरेलू हकदारी टैरिफ क्षेत्र से की गई आपूर्तियों को 'मान्य निर्यात' समझा जाएगा और डी टी ए आपूर्तिकर्ता निर्यात दायित्व, यदि कोई हो, के अलावा नीति के अध्याय 8 के अधीन संगत हकदारियों के लिए पात्र होगा। उपरोक्त के बावजूद, उपयुक्त डिसक्लेमर प्रस्तुत करने पर नीति के अध्याय 8 में विनिर्दिष्ट के अनुसार ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटें हकदारी प्राप्त करने के योग्य होगी। मान्य निर्यात शुल्क वापसी का दावा करने के लिए जहाँ भी वापसी की सभी उद्योग दरें उपलब्ध नहीं हैं, विकास आयुक्त द्वारा ब्राण्ड दरें निर्धारित करवाई जाएंगी।

(ख) बहुमूल्य और अर्द्धबहुमूल्य पत्थर, कृत्रिम पत्थर और प्रसंस्कृत मोतियों का डी टी ए से ई ओ यू को आपूर्ति करने वाले प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में उल्लिखित मदों के लिए और दरों पर प्रतिपूर्ति लाइसेंस प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(ग) इसके अलावा ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/एस ई जेड यूनिट निम्नलिखित के लिए पात्र होंगे।

- (1) भारत में विनिर्मित माल पर केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति।
- (2) भारत में विनिर्मित वस्तुओं पर डी टी ए से खरीदी गई वस्तुओं पर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट।
- (3) हटा दिया गया है।
- (4) घरेलू तेल कंपनियों से प्राप्त ईंधन पर अदा शुल्क को समय-समय पर विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचित शुल्क वापसी की दर से लौटा दिया जाएगा।
- (5) सेनवैट क्रेडिट पर सेवा शुल्क के भुगतान से छूट।

अन्य हकदारियाँ

6.12 ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटों की अन्य हकदारियाँ निम्नलिखित हैं;

- (क) आयकर अधिनियम की धारा 10क और 10ख के उपबन्धों के अनुसार आयकर के भुगतान से छूट।
- (ख) लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों के विनिर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग से छूट।

- (ग) हटा दिया गया है।
- (घ) निर्यात आय को 12 महीनों के भीतर प्राप्त करना होगा।
- (ङ) ई ई एफ सी. खाते में 100 प्रतिशत निर्यात अर्जन की अनुमति होगी।
- (च) यूनिटों को आयात करते समय या डी टी ए में जब कार्य करते समय बैंक गारन्टी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिन मामलों में यूनिट का (1) कारोबार 5 करोड़ रुपये या इससे अधिक है (2) यूनिट कम से कम 3 वर्षों से मौजूद है और (3) यूनिट का साफ सुथरा ट्रैक रिकार्ड है।
- (छ) एस ई जेड यूनिटों की तरह हो आटोमैटिक रूट के जरिए 100 प्रतिशत एफ डी आई निवेश की अनुमति दी जाएगी।

अनार यूनिट हस्तांतरण

- 6.13 (क) एक निर्यात अभिमुख यूनिट/ई एच टी पी/एस टी पी/ बी टी पी यूनिट से अन्य ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट को विनिर्मित माल के हस्तांतरण की अनुमति दी जाएगी तथा इसकी पूर्व सूचना वस्तुओं के इन-बॉर्ड-मूवमेंट की प्रक्रिया को अपनाने वाले संबंधित विकास आयुक्त और सीमाशुल्क प्राधिकारी को देनी होगी।
- (ख) संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारी तथा विकास आयुक्त को पूर्व सूचना देकर पूंजीगत वस्तुओं को किसी अन्य ई ओ यू/ ई एच टी पी/एस टी पी/ बी टी पी/ एस ई जेड यूनिटों को हस्तांतरित या ऋण पर दिया जा सकता है।
- (ग) किसी एक यूनिट द्वारा किसी दूसरे ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट को वस्तुओं की आपूर्ति, दूसरे यूनिट द्वारा डी टी ए बिक्री पर शुल्क के भुगतान के प्रयोजन के लिए दूसरे यूनिट के लिए आयातित वस्तुएं मानी जाएंगी।

उप-ठेके

6.14 (क) (1) ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट जिनमें रत्न और आभूषण यूनिटें शामिल हैं, सीमाशुल्क प्राधिकारियों की वार्षिक अनुमति के आधार पर डी टी ए में यूनिटों द्वारा फुटकर ठेके के आधार पर माल के रूप और किस्म में परिवर्तन करना भी शामिल है, का डी टी ए में उप-ठेके पर उत्पादन प्रक्रिया कर सकती है।

(2) ये यूनिटें सीमाशुल्क प्राधिकारियों की अनुमति से डी टी ए में जॉब वर्क के उप-ठेके के लिए मूल्य की शर्तों में पिछले वर्ष के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत तक भी उप-ठेके पर दे सकते हैं।

(ख)(1) ई ओ यू यूनिटों को डी टी ए निर्यातक के बदले में निर्यात हेतु जॉब वर्क की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते माल को ई ओ यू यूनिटों से सीधे निर्यात किया जाए और निर्यात दस्तावेज डी टी ए/ई ओ यू यूनिट के नाम में संयुक्त रूप से तैयार किया जाए। ऐसे निर्यात हेतु, शुल्क वापसी की ब्रांड दर के माध्यम से निविष्टियों पर अदा किए शुल्क को वापिस लेने के लिए डी टी ए यूनिटें हकदार होंगी।

(2) जब वर्क के आधार पर विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा ई ओ यू को दिए गए निर्यात आदेश को पूरा करने के लिए वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति इस शर्त के अधीन होगी कि कोई डी टी ए क्लियरेंस न दी जाए।

(3) यूनिट में रखे गये रिकार्ड के अनुसार अन्य ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/एस ई जेड/बी टी पी एककों के माध्यम से उत्पादन और उत्पादन प्रक्रिया दोनों के उप-ठेके की प्रक्रिया किसी सीमा के बिना शुरू कर सकते हैं।

(4) विकास आयुक्त के अनुमोदन से विदेश में उत्पादन प्रक्रिया के भाग के रूप में उप-ठेके की अनुमति दी जाएगी।

(ग) जब वर्कर के कार्यस्थल में पैदा हुए स्क्रेप/वेस्ट/टुकड़ों को या तो जब वर्कर के कार्यस्थल से लागू शुल्क के भुगतान पर दिया जा सकता है या सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क प्राधिकारी की उपस्थिति में नष्ट किया जा सकता है या आपूर्तिकर्ता यूनिट को वापिस किया जा सकता है। सोना, चांदी, प्लेटिनम, हीरा, कीमती और अर्द्ध कीमती पत्थरों को नष्ट करने की अनुमति नहीं होगी।

(घ) रत्न और आभूषण ई ओ यू इकाइयों द्वारा अन्य ई ओ यू/ एस ई जेड/ डी टी ए इकाइयों में उप-ठेका/विनिमय प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) निर्दिष्ट प्रक्रिया के तहत किया जा सकता है।

प्रयोग न किए गए माल की बिक्री

6.15 (क) यदि कोई निर्यातोन्मुख यूनिट/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी की यूनिट से आयातित या डी टी ए से प्राप्त किए गये माल और सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाती है तो (1) यह अन्य ई ओ यू/एस ई जेड/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी इकाइयों को हस्तांतरित कर सकती है या (2) सीमाशुल्क प्राधिकारियों के अनुमोदन से आयात लाइसेंस सौंपकर और लागू शुल्कों का भुगतान करके, यदि आवश्यक हो डी टी ए में उनका निपटान या (3) निर्यात कर सकती है। एक ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट से अन्य ऐसे यूनिटों को किए गये मदों का हस्तांतरण प्राप्तकर्ता इकाई के लिए आयात माना जाएगा।

(ख) पूंजीगत वस्तुएं और पुराने/अतिरिक्त कल पुर्जों का निर्यात या अन्य ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी/एस ई जेड इकाइयों को हस्तांतरण या लागू शुल्क के भुगतान के बाद डी टी ए में निपटान किया जा सकता है। डी टी ए में निपटान की स्थिति में यथा लागू मूल्यहास का लाभ लागू होगा। यदि पूंजीगत माल कच्चा माल, उपभोग्य कलपुर्जों, विनिर्मित माल, प्रसंसाधित या पैकिंग किया गया और स्क्रेप/वेस्ट/रैमनेन्स/रद्द माल को सीमाशुल्क प्राधिकारियों

को सूचित करने के बाद यूनिट के भीतर नष्ट करने पर या सीमाशुल्क प्राधिकारियों की अनुमति से यूनिट के बाहर नष्ट करने पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। सोना, चाँदी, प्लेटिनम, हीरा, कीमती और अर्द्ध कीमती पत्थरों पर उपर्युक्त विनष्टीकरण लागू नहीं होगा।

(ग) वस्त्र क्षेत्र के मामले में लागत बीमा भाड़ा मूल्य या आयात की मात्रा, जो भी कम हो, के 2 प्रतिशत तक बचे हुए माल/कपड़े का निपटान सौदा मूल्य पर शुल्क का भुगतान करने पर अनुमत होगा बशर्त कि केन्द्रीय उत्पाद/सीमा शुल्क अधिकारी यह प्रमाणित करे कि यह बचा हुआ माल है।

(घ) इस्तेमाल की गई पैकिंग सामग्री के निपटान की अनुमति सौदा मूल्य पर शुल्क का भुगतान करने पर दी जाएगी।

रिकंडिशनिंग/मरम्मत और पुनः इंजिनियरिंग करना

6.16 निर्यातोन्मुख/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी क्षेत्र की यूनिटों को रिकंडिशनिंग, मरम्मत, पुनर्निर्माण, परिक्षण, कैलीब्रेशन, गुणवत्ता सुधार प्रौद्योगिकी उन्नयन और पुनः इंजिनियरिंग जैसे कार्यों के लिए तथा विदेशी मुद्रा में निर्यातों के लिए अनुमोदन बोर्ड की स्वीकृति से स्थापित किया जा सकता है। ऐसे यूनिट उपयुक्त कार्यों के लिए किसी भी किस्म के माल का आयात कर सकते हैं। प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 6.29 और नीति के पैराग्राफों 6.8, 6.9, 6.10, 6.13, व 6.14 के प्रावधान ऐसे कार्यकलापों पर लागू नहीं होंगे।

आयातित/स्वदेशी वस्तुओं का प्रतिस्थापन/मरम्मत

6.17 (क) प्रतिस्थान/मरम्मत वस्तुओं के निर्यात के संबंधित नीति के सामान्य प्रावधान ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटों पर भी एक समान लागू होंगे यद्यपि प्रावधान के तहत न आने वाले मामलों पर विकास आयुक्त द्वारा गुण-दोष आधार पर विचार किया जाएगा।

(ख) डी टी ए में बेची गई वस्तुएं और खराब पाई गई वस्तुओं को सम्बन्धित अधिकार क्षेत्र के सीमाशुल्क/उत्पाद प्राधिकारियों की सूचना में मरम्मत/बदलने के लिए लाया जा सकता है।

(ग) आयात करने पर/स्वदेशी रूप से प्राप्त करने पर वस्तुएं अथवा उनके का हिस्से जो त्रुटिपूर्ण अथवा उपयोग हेतु अन्यथा अनुपयुक्त अथवा आयात के बाद क्षतिग्रस्त हो जाएं/लौटाए और प्रतिस्थापन प्राप्त किए जा सकते हैं अथवा नष्ट किए जा सकते हैं। प्रतिस्थापित करने के मामले में वस्तुएं विदेशी संभरकों अथवा भारत में उनके अधिकृत संभरकों/स्वदेशी संभरकों से वापिस ली जा सकती है। तथापि कीमती और अर्द्धकीमती धातुओं पर विनष्टीकरण लागू नहीं होगा।

ई ओ यू योजना से बहिर्गमन

6.18 (क) विकास आयुक्त के अनुमोदन से निर्यात अभिमुख यूनिट इस योजना को छोड़ सकती हैं। उस समय लागू सीमा-शुल्क और

उत्पाद शुल्क के भुगतान करने पर और बहिर्गमन से संबंधित निर्वर्तमान औद्योगिक नीति के तहत इस योजना को छोड़ा जा सकता है।

(ख) अगर यूनिट ने इस योजना के अन्तर्गत दायित्व को प्राप्त नहीं किया है तो योजना से बहिर्गमन, के समय उसे जुर्माना देना होगा।

(ग) रत्न व जेवरात युनिटों द्वारा कार्य करना बन्द करने पर आभूषण के निर्माण के लिए उपलब्ध स्वर्ण व अन्य बहुमूल्य धातु, मिश्रधातु, रत्न व अन्य सामग्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) द्वारा नामित एंजसी को उनके द्वारा निर्धारित कीमत पर हस्तांतरित करनी पड़ेगी।

(घ) प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में निर्दिष्ट के अनुसार मानक शर्तों और उस योजना के अधीन पात्रता संबंधी मानदण्डों को पूरा करने वाले निर्यातोन्मुख यूनिट/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट को एक बार के विकल्प के रूप में मौजूद ई पी सी जी योजनाओं के तहत पूंजीगत वस्तुओं पर शुल्क को भुगतान करने पर विकास आयुक्त द्वारा योजना छोड़ने की अनुमति दी जा सकती है।

(ङ) ई ओ यू योजना को छोड़ने का प्रस्ताव करने वाले यूनिटों को विकास आयुक्त/सीमाशुल्क प्राधिकारी और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी को लिखित में सूचित करना होगा। यूनिट डिबांडिंग के कारण उत्पन्न शुल्क संबंधी दायित्व का मूल्यांकन करेगा और ऐसे मूल्यांकन के ब्यौरे सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरणों को भेजेगा। सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी प्राथमिकता के आधार पर दायित्वों की पुष्टी करेंगे। शुल्क के भुगतान तथा सभी शुल्कों का भुगतान कर देने के पश्चात यूनिट सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी से 'बेबाकी प्रमाण पत्र' प्राप्त करेगा। सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा जारी 'बेबाकी प्रमाण-पत्र' के आधार पर यूनिट अन्तिम रूप से डिबांडिंग के लिए विकास आयुक्त को आवेदन करेगा। यदि विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 के तहत कोई मामला लंबित न होने पर विकास आयुक्त 7 कार्य दिवसों के भीतर अन्तिम डिबांडिंग आदेश जारी कर देगा। सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए 'बेबाकी प्रमाण पत्र' और विकास आयुक्त द्वारा जारी किया गया अन्तिम डिबांडिंग आदेश में बीच की अवधि के दौरान यूनिट पूंजीगत माल अथवा निविष्टी को प्राप्त करने के लिए किसी छूट का दावा करने का पात्र नहीं होगा।

तथापि वे अग्रिम लाइसेंस/डी ई पी बी/डी एफ आर सी/शुल्क वापसी का दावा कर सकते हैं।

(च) जिन मामलों में यूनिट ने लागू आयात शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् विदेश से या उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् घरेलू बाजार से मशीनें खरीद कर प्रारम्भ में डी टी ए यूनिट स्थापित किया गया है, और जिसे बाद में ई ओ यू में परिवर्तित कर दिया गया है, ऐसे मामलों में डीबान्डिंग के पश्चात् डी टी ए में ऐसी पूंजीगत वस्तुएँ तो जाने के लिए किसी शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। इसी प्रकार ई पी सी जी योजना के तहत यहां डी टी ए यूनिटों के रूप में पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया है और ई पी सी जी योजना के अन्तर्गत निर्यात दायित्व को पूर्णतः पूरा करने के पश्चात् और स्वयं को ई ओ यू में परिवर्तित करवाने पर यूनिट से डी टी ए ऐसी पूंजीगत वस्तुओं को ले जात समस्त पूंजीगत वस्तुओं से सीमाशुल्क नहीं लिया जाएगा।

परिवर्तन

6.19 (क) मौजूदा डी टी ए यूनिटें भी किसी निर्यात अभिमुख यूनिट/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट में परिवर्तित के लिए आवेदन कर सकती हैं और पहले से स्थापित संयंत्र, मशीनरी और उपस्कर के लिए योजना के अन्तर्गत आयकर अधिनियम की धारा 10 (क) और 10(ख) के तहत लाभ उपलब्ध होंगे।

(ख) विद्यमान ई एच टी पी/एस टी पी यूनिटें, ई ओ यू यूनिट में परिवर्तन/समाहित होने के लिए अथवा विलोमतः आवेदन कर सकती हैं। ऐसे मामलों में यूनिटें बांड के अधीन होंगी तथा संबद्ध योजनाओं के तहत लागू ड्यूटी एवं टैक्स छूट का लाभ उठा सकती हैं।

एन एफ डी की निगरानी

6.20 ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटों के कार्य निष्पादन की निगरानी एकक अनुमोदन समिति के द्वारा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में उल्लिखित मार्ग निर्देशों के अनुसार निगरानी की जाएगी।

प्रदर्शनी के माध्यम से निर्यात/निर्यात प्रोत्साहन यात्रा/विदेशी शोरूम के जरिए निर्यात/शुल्क मुक्त दुकानें

6.21 ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटें निम्नलिखित के हकदार होंगे:

- (1) विकास आयुक्त की अनुमति से विदेशों में प्रदर्शन करने/शामिल होने के लिए वस्तुओं का निर्यात करना।
- (2) स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनियम जेबरात, बहुमूल्य, अर्धबहुमूल्य पत्थर, माणिक व अन्य व्यक्तिगत सामान।
- (3) विदेशों में स्थापित/अनुमोदित दुकानों में प्रदर्शन/विक्रय के लिए मालों का निर्यात।

(4) विदेशों में स्थापित/अनुमोदित दुकानों या उनके वितरकों/एजेंटों के शो रूम में प्रदर्शन/विक्री हेतु निर्यात।

(5) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में शो रूम/खुदरा दुकानों की स्थापना।

वैयक्तिक सामानों का आयात/विदेशी बांड पैसेन्जर सहित निर्यात पार्सल

6.22 रत्न और आभूषणों का आयात/निर्यात व्यक्तिगत रूप से सीमा-शुल्क द्वारा निर्धारित प्रक्रिया नियमों के अधीन किया जा सकता है। तथापि, निर्यात आय को सामान्य बैंकिंग चैनलों के द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा। रत्न और आभूषण इकाई के अलावा अन्य यूनिटों के लिए आयात-निर्यात व्यक्तिगत रूप से करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते वस्तुएं वाणिज्यिक मात्रा में हो।

डाक/कोरियर द्वारा निर्यात/आयात

6.23 निःशुल्क नमूनों सहित अन्य मालों को सीमा-शुल्क नियमों के अधीन हवाई जहाज या विदेश डाक खाना या कोरियर द्वारा निर्यात/आयात किया जा सकता है।

ई ओ यू यूनिटों का प्रशासन/विकास आयुक्त को प्रदत्त शक्तियाँ

6.24 ई ओ यू यूनिटों के प्रशासन और विकास आयुक्त को प्रदत्त शक्तियाँ का ब्यौरा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में दिया गया है।

रुग्ण यूनिटों का पुनरुत्थान

6.25 उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा यूनिट को रुग्ण घोषित करने पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा यूनिट के पुनरुत्थान या अधिग्रहण के विचार किया जा सकता है।

ई एच टी पी/एस टी पी के लिए अनुमोदन

6.26 ई एच टी पी/एस टी पी योजनाओं के अधीन यूनिटों के मामलों में इस अध्याय के संबंधित पैरा के अधीन आवश्यक अनुमोदन/अनुमति के विकास आयुक्त के बजाए सूचना व प्रौद्योगिक मंत्रालय के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामित अधिकारी द्वारा और अनुमोदन बोर्ड के बजाए अंतर्मंत्रालय स्थायी समिति (आई एम एस सी) द्वारा दी जाएगी।

बी टी पी का अनुमोदन

6.27 जैव प्रौद्योगिकी पार्कों (बी टी पी) को जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सिफारिशों पर विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचित किया जाए। बी टी पी में यूनिटों के मामले में इस अध्याय के संबंध उपबन्धों के अधीन आवश्यक अनुमोदन/अनुमति प्रौद्योगिकी विभाग के नामजद अधिकारी द्वारा दी जाएगी।

अध्याय -7

विशेष आर्थिक जोन

विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंधित नीति विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 और इसके अन्तर्गत बनाये गए विधियों द्वारा शासित होती है।

अध्याय-7क

मुक्त व्यापार और गोदाम जोन

मुक्त व्यापार और गोदाम जोन से संबंधित नीति विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 और इसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों द्वारा शासित होती है।

अध्याय - 8

मान्य निर्यात

मान्य निर्यात

8.1 'मान्य निर्यात' का अर्थ उस लेन-देन से है जिसमें आपूर्ति किया गया माल देश से बाहर नहीं जाता और इन आपूर्तियों के लिए भुगतान या तो भारतीय रुपये में या मुक्त विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया जाता है।

संभरण की श्रेणियाँ

8.2 इस नीति के तहत निम्नलिखित श्रेणियों के माल का मुख्य/उप ठेकेदारों द्वारा आपूर्ति को मान्य निर्यात के रूप में माना जाएगा बशर्ते कि माल भारत में विनिर्मित हुआ हो :—

- (क) शुल्क मुक्त/शुल्क वापसी स्कीम के तहत अग्रिम लाइसेंस/वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम लाइसेंस डी एफ आर सी के प्रति माल का संभरण ;
- (ख) निर्यातोन्मुख यूनिटों या साफ्टवेयर टेक्नालोजी पार्क्स (एटीपी) या इलेक्ट्रॉनिक हार्ड वेयर टेक्नालोजी पार्क (ई एच टी पी) वायोटेकनालौजी पार्क (बी टी पी) में स्थित यूनिटों को माल की आपूर्ति।
- (ग) निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ई पी सी जॉ) स्कीम के अन्तर्गत लाइसेंसधारियों को पूंजीगत माल की आपूर्ति।
- (घ) वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के तहत बहुपक्षीय या द्विपक्षीय अधिकरणों/निधियों द्वारा वित्त-पोषित परियोजनाओं को उन अधिकरणों/निधियों की प्रक्रियाओं के अनुसार माल का संभरण, जहां विधिक करारों में सीमाशुल्क को शामिल किए बिना टैंडर मूल्यांकन की व्यवस्था हो।

इन अधिकरणों/निधियों की प्रक्रियाओं के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के तहत वित्त मंत्रालय,

आर्थिक कार्य विभाग द्वारा यथाअधिसूचित बहुपक्षीय या द्विपक्षीय अधिकरणों/निधियों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए जिनके लिए बोली आमंत्रित की गई है और विदेश में विनिर्मित वस्तुओं के लिए डी डी पी मूल्यों के आधार पर मूल्यांकित है वस्तुओं के लिए डी डी पी मूल्यों के आधार पर मूल्यांकित है वस्तुओं और उपस्करों को अधिष्ठापित करने के लिए आपूर्ति (टर्नकी ठेकों का एकल उत्तरदायित्व)

- (ङ) पूंजीगत माल की आपूर्ति जिसमें उर्वरक संयंत्रों की स्थापना हेतु इस पूंजीगत माल के लिए आवश्यक अनअसैम्बलड/डिसअसैम्बलड हालत में तथा कच्चा माल अर्न्तवर्ती, संघटक, कलपुर्जे शामिल है और एफ ओ आर मूल्य के 10 प्रतिशत तक हिस्से पुर्जों एवं वाणिज्यिक उत्पाद की आपूर्ति।
 - (च) शून्य सीमाशुल्क पर ऐसे माल के आयात की अनुमति देते हुए किसी परियोजना या प्रयोजन के लिए वित्त मंत्रालय की एक अधिसूचना के तहत घरेलु संभरण के लिए माल की आपूर्ति।
 - (छ) ऊपर (च) में शामिल न किए गए पावर और रिफाइनरी को माल की आपूर्ति।
 - (ज) 100 प्रतिशत ई ओ यू (घरेलु भाड़ा कन्टेनरों के विनिर्माताओं) द्वारा समुद्री फ्रेट कन्टेनरों की आपूर्ति, बशर्ते उक्त कन्टेनरों का भारत से 6 महीनों या सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा अनुमत अवधि के भीतर निर्यात किया गया हो।
 - (झ) संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठनों द्वारा वित्त पोषित संगठनों को की गई आपूर्ति।
 - (ञ) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता बोली के विपरीत प्रतियोगी बोली के आधार पर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्टों को माल की आपूर्ति।
- पैराग्राफ (घ), (ङ), (च) और (छ) के तहत मान्य निर्यात के लाभ केवल तभी उपलब्ध होंगे यदि आपूर्ति अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली की प्रक्रिया के अन्तर्गत की गई है।

मान्य निर्यातों के लिए लाभ

8.3 मान्य निर्यात के रूप में पात्र माल के विनिर्माण और आपूर्ति के संदर्भ में मान्य निर्यात पर निम्नलिखित लाभ दिए जाएंगे बशर्ते कि यह प्रक्रिया पुस्तक खण्ड (1) में दी गयी शर्तों के अनुसार होगा—

- (क) अग्रिम प्राधिकार
- (ख) मान्य निर्यात शुल्क वापसी।
- (ग) जहाँ आपूर्तियाँ अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के मद्दे की

गई है वहाँ अन्तिम उत्पाद शुल्क से छूट होगी। अन्य मामलों में अन्तिम उत्पाद शुल्क वर्गित किया जाएगा।

आपूर्तिकर्ता को लाभ

- 8.4.1 (1) नीति के पैरा 8.2 (क) के संबंध में अग्रिम लाइसेंस के मदे की गई आपूर्तियों के लिये आपूर्तिकर्ता, अन्तर्वर्तीय आपूर्ति हेतु अग्रिम संबंधित एक हकदार होगा।
- (2) यदि आपूर्तिकर्ता ने नीति के पैरा 4.1.11 और 4.1.12 की शर्तों के अनुसार अग्रिम रिलीज आदेश (ए आर ओ) या बैंक टू बैंक साख-पत्र के अनुसार आपूर्ति की है तो वह नीति के पैरा 8.3 ख और ग में कोई भी लागू हो में दिए गए लाभों का हकदार होगा।
- (3) उन मामलों में जहाँ डी एफ आर सी के मदे अग्रिम रिलीज आदेश या बैंक-टू-बैंक ऋण पत्र के अनुसार आपूर्ति की गई है, आपूर्तिकर्ता नीति के पैरा 8.3ख में उल्लिखित लाभ का हकदार होगा।
- 8.4.2 नीति के पैरा 8.2 (ख) के अनुसार ईओयू/ईएच टीपी/एस टी पी/बीटीपी को माल की आपूर्ति के संबंध में, आपूर्तिकर्ता नीति के पैरा 8.3(क),(ख)और (ग) जो भी लागू हो में उल्लिखित लाभों का हकदार होगा।
- 8.4.3 नीति के पैरा 8.2 ग के अधीन आपूर्ति के संबंध में आपूर्तिकर्ता नीति के पैरा 8.3 (क),(ख) और (ग) जो भी लागू हो में निर्दिष्ट लाभों के पात्र होंगे।
- 8.4.4 (1) नीति के अन्तर्गत पैरा 8.2 (घ),(च) और(छ) के तहत आपूर्तियों के मामले में, आपूर्तिकर्ता पैरा 8.3(क),(ख) और (ग) में सूचीबद्ध लाभों, जो भी लागू हों, का पात्र होगा।
- (2) पैरा 8.2घ में बताये अनुसार केवल ऐसे अभिकरणों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं की आपूर्ति, जो वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा अधिसूचित हो, मान्य निर्यात लाभों के पात्र होंगी। ऐसे अभिकरणों/निधियों की सूची परिशिष्ट 13 में दी गई है।
- (3) नीति के पैरा 8.2(च) के तहत मान्य निर्यात के लाभ उन मदों पर लागू होंगे, जिनका आयात शून्य सीमा-शुल्क पर राजस्व विभाग द्वारा अनुमत होगा अर्थात् कि वह समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क अधिसूचना सं. 21/2002, दिनांक 1-3-2002 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करते हों।
- (4) पैरा-8.2 छ के अनुसार विद्युत परियोजनाओं को की गई पूंजीगत माल और पूंजीगत माल के रेल पर्यन्त

निःशुल्क मूल्य के 10 प्रतिशत तक पुर्जा की आपूर्ति मान्य निर्यात लाभों के लिए पात्र होंगी अर्थात् कि वह स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक (आई पी पी)/इंजीनियरिंग एण्ड, प्रोक्योरमेंट कान्ट्रेक्ट (ई पी सी)/स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक खोली प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद की गई हो। मान्य निर्यात के लाभ पावर संयंत्रों के नवीकरण/आधुनिकरण हेतु भी उपलब्ध होंगे। (आपूर्तिकर्ता नीति के पैरा 8.3क, ख में दिए गए जो भी लागू हों लाभों के लिए पात्र होंगे।) तथापि समय समय पर यथासंशोधित राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 21/2002 सीमाशुल्क दिनांक 1-3-2002 की क्रम सं. 400 में निर्दिष्ट कोई बड़ी पावर परियोजना स्थापित करने के लिए अपेक्षित वस्तुओं की आपूर्ति निर्यात और आयात नीति के पैराग्राफ 8.3 क, ख और ग में यथा उल्लिखित मान्य निर्यात के लाभ पाने की पात्र होंगी, यदि ऐसी बड़ी योजना :-

- (क) अन्तर्राज्य थर्मल पावर संयंत्र जिसकी क्षमता 1000 मैगावाट या इससे अधिक है।
- (ख) 500 मैगावाट या उससे अधिक की क्षमता वाले एक अन्तर्राज्य हाइड्रल पावर प्लान्ट।
- (5) नीति के पैराग्राफ 8.2छ के अन्तर्गत उन नई रिफाइनरियों को जो नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में लगी हैं और दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि तक चलेंगी को आपूर्ति अधिसूचना संख्या 21/2002 सीमाशुल्क दिनांक 1-3-2002 समय-समय पर यथासंशोधित, की क्रम संख्या 228 में सूची संख्या 17 में विनिर्दिष्ट माल के लिए मान्य निर्यात के लाभ की हकदार होगी। आपूर्तिकर्ता के पैरा 8.3(क) और (ख) में सूचीबद्ध लाभों जो भी लागू है, के लिए पात्र होंगे।
- 8.4.5 नीति के पैरा 8.2(ड) के तहत की गई आपूर्तियों के मामले में आपूर्तिकर्ता नीति के पैरा 8.3 (क) और (ख) में सूचीबद्ध लाभों, जो भी लागू हो, के लिए पात्र होगा। मान्य निर्यातों के लाभ उर्वरक संयंत्रों के पूंजीगत माल और पुर्जों के लिए भी उपलब्ध होंगे जिन्हें नौवीं योजना के दौरान स्थापना/दुरुस्त/विस्तार आधुनिकीकरण किया गया है मान्य निर्यातों के लाभ उर्वरक संयंत्रों को की जाने वाली उन आपूर्तियों के लिए भी उपलब्ध होंगे जो आठवीं/नौवीं योजना में शुरू हुई हैं और दसवीं योजना तक चलेंगी।
- 8.4.6 नीति के पैरा 8.2(झ) के अन्तर्गत आने वाली संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वित्तपोषित परियोजना को माल की आपूर्ति नीति के पैरा 8.3 (क) और (ख) में सूचीबद्ध लाभों, जो भी लागू हो, के लिए पात्र होंगी।

न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्टों को आपूर्ति

8.4.7 नीति के पैरा 8.2 (अ) के तहत न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को की गई आपूर्तियों के सम्बन्ध में, नीति के पैरा 8.3 (क), (ख) और (ग) जो भी लागू हों, में विनिर्दिष्ट लाभों के पात्र होंगे। समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 1-3-2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सीमाशुल्क की सूची संख्या 43 के क्रम संख्या 401 के अनुसार न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जिनकी क्षमता 440 एम डब्ल्यू या अधिक हो जिसे आणविक उर्जा विभाग, भारत सरकार में संयुक्त सचिव के स्तर के नीचे का अधिकारी न हो ने प्रमाणित किया हो की गई आपूर्ति मान्य निर्यात लाभ के हकदार होंगी बशर्ते की ऐसी आपूर्तियाँ प्रतिस्पर्धात्मक बोली (न कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली) प्रक्रिया के अधीन हुई हो।

टर्मिनल उत्पाद शुल्क वापसी/शुल्क वापसी के भुगतान से छूट

8.5 माल की आपूर्ति नीति के पैरा 8.3 (ग) के संबंध में टर्मिनल उत्पाद शुल्क की वापसी के लिए पात्र होगी बशर्ते कि माल के प्राप्तकर्ता ने ऐसे माल पर सेनवेट क्रेडिट/छूट प्राप्त न किया हो। इसी प्रकार आपूर्तियाँ निविष्टि/संघटकों पर अदा किए गए केन्द्रीय उत्पाद पर नीति के पैरा 8.3 (ख) के संबंध में मान्य निर्यात वापसी के लिए पात्र होंगी बशर्ते कि आवेदक द्वारा सेनवेट क्रेडिट सुविधा/छूट प्राप्त न की गई हो। तथापि ऐसी आपूर्तियाँ निविष्टि/संघटकों पर अदा किए गए सीमाशुल्क पर मान्य निर्यात वापसी के लिए पात्र होंगी।

मुख्य/उप ठेकेदार द्वारा की जाने वाली आपूर्तियाँ

8.6.1 मान्य निर्यात के सभी मामलों में आपूर्तियाँ प्रत्यक्षतः नामित प्रोजेक्ट्स एजेंसियों/यूनिटों/अग्रिम प्राधिकार/ई पी सी जी प्राधिकार धारक को की जाएंगी। तथापि, उप-ठेकेदार पैरा 8.4 के अनुसार नामित एजेंसियों/प्रोजेक्ट्स के बजाय मुख्य ठेकेदार को आपूर्तियाँ कर सकता है।

उप-ठेकेदारों को लाभ

8.6.2 भारतीय या विदेशी मुख्य ठेकेदारों के भारतीय उप-ठेकेदार द्वारा की गयी आपूर्तियाँ भी मान्य निर्यात के लिए पात्र होंगी बशर्ते कि करार में मूल रूप में या बाद में उप-ठेकेदार का नाम भी दर्शाया गया हो तथा परिशिष्ट-22ग (खण्ड-1) में निर्धारित प्रपत्र में उप-ठेकेदार के नाम में परियोजना अधिकारी द्वारा भुगतान प्रमाण-पत्र जारी किया हो।

अध्याय—नौ**परिभाषाएं**

9.1 इस नीति के उद्देश्य के लिए, जब तक कि प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों के निम्नलिखित अर्थ होंगे :—

9.2 'उपांग' या 'संलग्नी' का अर्थ है एक भाग, उप-संयोजक अथवा संयोजक जो उपस्कर के मूल कार्यों को परिवर्तित किए बिना उपस्कर के एक अंश की कार्यक्षमता या कारगरता में सहयोग देता है।

9.3 'अधिनियम' का अर्थ है—विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22)।

9.4 'वास्तविक उपयोक्ता' का अर्थ है वास्तविक उपयोक्ता जो औद्योगिक अथवा गैर-औद्योगिक हो सकता है।

9.5 'वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक)' का अर्थ उस व्यक्ति से है जो आयातित माल का प्रयोग अपनी निजी यूनिट में विनिर्माण के लिए अथवा फुटकर सहित किसी अन्य यूनिट में अपने निजी प्रयोग के लिए करता है।

9.6 'वास्तविक उपयोक्ता (गैर-औद्योगिक)' का अर्थ उस व्यक्ति से है जो अपने स्वयं के इस्तेमाल के लिए आयातित सामग्री का निम्नलिखित में इस्तेमाल करता हो :—

1. कोई भी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जो कोई व्यवसाय, व्यापार या पेशा कर रहा हो; या
2. कोई भी प्रयोगशाला, वैज्ञानिक या अनुसंधान और विकास संस्था, विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल; या
3. कोई सेवा उद्योग।

9.7 'ए ई जैड' का अर्थ है प्रख्यात पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट 8 में महानिदेशक विदेश व्यापार द्वारा अधिसूचित कृषि निर्यात क्षेत्र।

9.8 हटा दिया गया है।

9.9 'आवेदक' का अर्थ है वह व्यक्ति जिसकी तरफ से आवेदन किया जाए और जहाँ संदर्भ में आवश्यक हो, इसमें आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति भी शामिल है।

9.9.1 'प्राधिकार' का अर्थ है इस नीति की शर्तों के अनुसार आयात अथवा निर्यात की अनुमति जैसा कि विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992, 1992 की सं० 22 में बताया गया है।

9.10 'बी ओ ए' का अर्थ है अनुमोदन बोर्ड जैसा कि वाणिज्य विभाग द्वारा अधिसूचित है।

9.11 'बीटीपी' से अभिप्राय उन बायोटेक्नालोजी पार्कों से है जिन्हें बायोटेक्नालोजी विभाग की सिफारिश पर महानिदेशक द्वारा अधिसूचित किया गया है।

- 9.12 'पूँजीगत माल' का अर्थ है माल के, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उत्पादन के लिए या सेवा अर्पित करने के लिए अपेक्षित संयंत्र, मशीनरी, उपकरण या उपसाधित्र जिनमें प्रतिस्थापना, आधुनिकीकरण, पौद्योगिकी के उन्नयन या विस्तार के लिए अपेक्षित सामग्री भी शामिल हैं। मैकेजिंग मशीनरी और उपकरण, प्रारंभिक लाइनिंग हेतु रिफ़्रेक्टरीज, प्रशीतन उपकरण, ऊर्जा अर्जित करने वाले मोटर, मशीन टूल्स, इलेक्ट्रिकल वाहन के लिए कन्ट्रोलिस्ट और परीक्षण अनुसंधान और विकास, गुणवत्ता और प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपस्कर एवं उपकरण शामिल हैं। पूँजीगत माल के निर्माण, खनन, कृषि, जलचर पालन, पशु पालन, मृष्य कृषि, भागवानी, मत्स्य पालन, मुर्गीपालन और रेशम-उत्पादन एवं अंगूरों/उत्पादन के साथ साथ सेवा विभाग में भी उपयोग में लाया जा सकता है।
- 9.13 'सक्षम प्राधिकारी' का अर्थ है—वह प्राधिकारी जो अधिनियम अथवा उसके तहत बने नियमों एवं आदेशों अथवा इस नीति के तहत किसी शक्ति का प्रयोग करने, कर्तव्य को पूरा करने के लिए सक्षम हो।
- 9.14 'संयोजक' का अर्थ उप संयोजन या संयोजन का वह पुर्जा जिससे एक विनिर्मित उत्पाद तैयार किया जाता है या जिसमें वह विघटित हो जाए। संयोजक में उसके सहायक या उपपंगी भी शामिल हैं।
- 9.15 'उपभोग्य' माल का अर्थ है—कोई मद जो विनिर्माण प्रक्रिया में शामिल हो या जिम्मेकी आवश्यकता हो परन्तु जो तैयार उत्पाद का भाग न हो। मदें जिनका वास्तविक रूप में पूर्णतया उपभोग कर लिया जाता है, उन्हें उपभोग्य मदें माना जाएगा।
- 9.16 'उपभोक्ता माल' का अर्थ खपत के उस माल से है जो किसी अन्य संसाधन के बिना मनुष्य की आवश्यकताओं को सीधे ही पूरा कर सकता है और इसमें उपभोक्ता के लिए टिकाऊ उपभोग्य माल और उसके अनुपंगी भी शामिल होंगे।
- 9.17 'प्रतिसंतुलन व्यापार' (काउंटर ट्रेड) का अर्थ उस व्यवस्था से है जिसके अन्तर्गत भारत से/को किया जाने वाला आयात/निर्यात व्यापार समझौते या अन्यथा तहत आयात/निर्यात करने वाले देश से सीधे अथवा तीसरे देश के जरिये संतुलित होता हो। प्रतिसंतुलन व्यापार (काउंटर ट्रेड) के अन्तर्गत निर्यात/आयात की अनुमित एस्को एकाउंट, वापस खरीदने की व्यवस्था, वस्तु विनिमय व्यापार या किसी ऐसी ही अन्य व्यवस्था के अन्तर्गत दी जा सकती है। ऐसा प्रतिसंतुलन पूर्णतया या आंशिक तौर पर नकद, माल और/या सेवाओं के रूप में हो सकता है।
- 9.18 'विकासकर्ता' का अर्थ है—एक व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय, कम्पनी, फर्म और ऐसे ही अन्य निजी या सरकारी उद्यम, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अन्य सुविधाओं को और बुनियादी सुविधाओं के एक भाग या सम्पूर्ण सुविधाओं का विकास, निर्माण करता है डिजाइन तैयार करता है, स्थापना, संवर्धन करता है, प्रचार वित्तीय सहायता प्रचालन, रख-रखाव या प्रबंध करता है।
- 9.19 'विकास आयुक्त' का अर्थ है विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास आयुक्त।
- 9.20 'डी एफ आर सी' का अर्थ है जारी शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र
- 9.21 'घरेलू टैरिफ क्षेत्र' का अर्थ है भारत के भीतर का क्षेत्र जो कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों और ई ओ यू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी से बाहर है।
- 9.22 'शुल्क वापसी' का अर्थ है भारत में विनिर्मित और निर्यात किए गए किसी माल के संबंध में किसी आयातित माल पर अथवा ऐसे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त उत्पाद शुल्क देय माल पर उगाहे जाने वाले शुल्क में कटौती। भारत में विनिर्मित पूँजीगत माल सहित आयातित कल-पुर्जे, यदि आपूर्ति की गई है, माल में शामिल है।
- 9.23 'ई.एच.टी.पी.' का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नालोजी पार्क।
- 9.24 'ई.ओ.यू.' का अर्थ है निर्यात उन्मुख एकक जिम्मेके लिए विकास आयुक्त द्वारा अनुमति पत्र जारी किया गया हो।
- 9.25 'उत्पाद शुल्क देय माल' का अर्थ है—कोई माल जिसका भारत में निर्माण किया गया हो और वह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1994 (1994 का 1) के अधीन हो।
- 9.26 'निर्यातक' का अर्थ उस व्यक्ति से है जो निर्यात करता है, निर्यात करना चाहता है और जो निर्यातक आयातक कोड नम्बर धारक हो, जब तक अन्यथा विशेष रूप से छूट न दी गई हो।
- 9.27 'निर्यात दायित्व' का अर्थ है लाइसेंस अथवा अनुज्ञा में शामिल उत्पाद अथवा उत्पादों का लाइसेंसिंग या सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित मात्रा अथवा मूल्य अथवा दोनों में निर्यात करने का दायित्व।
- 9.28 'कम्पनी समूह' से अभिप्राय दो या अधिक इन्टरप्राइजेज जो परीक्ष या अपरीक्ष रूप से ऐसी स्थिति में हों—

(i) अन्य इन्टरप्राइजेज में मताधिकार का 26 प्रतिशत या अधिक भागीदार होगा, या

(ii) अन्य इन्टरप्राइजेज में निदेशक मण्डल के सदस्यों का प्रतिशत 50 प्रतिशत से अधिक हो, या

समूह कम्पनी के लाभ के दावे या गुप के अन्य सदस्यों द्वारा लाभ के दावों के लिए उनके निर्यात की गणना की जायेगी, समूह कम्पनी नीति की किसी अधिसूचित निर्यात संवर्धन योजना के अधीन आवेदन की तारीख को कम से कम 2 वर्ष पूर्व अवस्थित होना चाहिए।

9.29 'प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1)' का अर्थ प्रक्रिया-पुस्तक (खण्ड-1) से है और 'प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-2)' का नीति के पैरा 2.4 के पैरा के प्रावधानों के अधीन प्रकाशित प्रक्रिया-पुस्तक (खण्ड-2) से है।

9.30 'आयातक' का अर्थ उस व्यक्ति से है जो आयात करता है, आयात करना चाहता है और जो आयातक-निर्यातक कोड नम्बर धारी हो, जब तक अन्यथा विशेष रूप से छूट न दी गई हो।

9.31 'संरचनात्मक सुविधा' का अर्थ है औद्योगिक, व्यावसायिक और सामाजिक संरचना या कोई अन्य सुविधा जो कि यथाअधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए हो।

9.32 'आई टी सी (एच एस)' का अर्थ निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण से है।

9.33 'जाबिंग' का अर्थ है—जाब वर्कर को आपूर्ति कच्चे माल या अर्ध-परिष्कृत माल का प्रसंस्करण या उसमें परिवर्तन करना ताकि प्रक्रिया का कोई हिस्सा या संपूर्ण प्रक्रिया पूरी हो सके जिसके परिणामस्वरूप वस्तु का विनिर्माण या परिष्करण हो या कोई भी कार्रवाई जो उपरोक्त प्रक्रिया के लिए जरूरी हो।

9.34 'लाइसेंसिंग प्राधिकारी' का अर्थ उस प्राधिकारी से है जो अधिनियम/आदेश के अधीन लाइसेंस देने के लिए सक्षम हो।

9.35 'लाइसेंसिंग वर्ष' का अर्थ उस वर्ष से है जो 1 अप्रैल से आरम्भ होकर आगामी वर्ष के 31 मार्च को समाप्त हो।

9.36 'होटल प्रबंधन' से अभिप्राय तीन स्टार या ऊपर के होटल/होटल श्रृंखला द्वारा होटल चलाना/होटल श्रृंखला तथा होटल प्रबंधन चलाने के मध्य कम से कम तीन वर्ष के दौरान एक प्रबंधन चलाने के करार के अधीन प्रबंधन से है। प्रबंधन करार होटल चलाने के प्रबंधन/कार्यकलापों के क्षेत्र आवश्यक रूप शामिल किया जायेगा।

9.37 'विनिर्माण' का अर्थ है—विशेष नाम, गुण या उपयोग वाला नया उत्पाद जो हाथ अथवा मशीन से बनाया गया, उत्पन्न किया गया, गढ़ा गया, संयोजित किया गया, संसाधित किया गया अथवा तैयार किया गया हो और उसमें ऐसे संसाधन शामिल हैं, जैसे रेफ्रिजेशन, पुनः पैकिंग, पॉलिशिंग, लेबलिंग, रि-कन्डीशनिंग, मरम्मत, रि-मेकिंग, रि-फिनिशिंग, टेस्टिंग, कैलिब्रेशन रि-इन्जीनियरिंग। विनिर्माण में, इस नीति के उद्देश्य के लिए कृषि, जलचर पालन, पशुपालन, पुष्पोदपादन, बागवानी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, रेशम-उत्पादन, अंगूरोत्पादन एवं खनन भी शामिल हैं।

9.38 'विनिर्माता निर्यातक' का अर्थ उस व्यक्ति से है जो अपने द्वारा निर्मित माल का निर्यात करता है अथवा ऐसे माल का निर्यात करना चाहता है।

9.39 'एम. ए. आई.' का अर्थ बाजार पहुंच पहल स्कीम जिसे वाणिज्य विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया है।

9.40 'व्यापारी निर्यातक' का अर्थ उस व्यक्ति से है जो व्यापार के कार्य और निर्यात के कार्य में संलग्न हो अथवा माल निर्यात करना चाहता हो।

9.40.1 'एन सी' अर्थात् 'मानदण्ड' समिति का अर्थ है शुल्क से मुक्त स्कीम के अधीन लाइसेंस प्रदान करने के लिए सिफारिश करने और महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले निवेश उत्पादन मूल्य संवर्धन मानदण्डों की सिफारिश करने वाली विदेश व्यापार महानिदेशालय की मानदण्ड समिति।

9.41 'एन एफ ई' का अर्थ निवल विदेशी मुद्रा अर्जन से है।

9.42 'अधिसूचना' का अर्थ उस अधिसूचना से है जो सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की जाए।

9.43 'आदेश' का अर्थ है अधिनियम के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया आदेश।

9.44 'पुर्जे' का अर्थ है उपसंयोजन या संयोजन का एक तत्व जो सामान्यतया स्वयं उपयोगी न हो और जो रख-रखाव के उद्देश्य के लिए आगे से असंयोजन के योग्य न हो। 'पुर्जा' एक संघटक स्पेयर अथवा उपसाधन हो सकता है।

9.45 'व्यक्ति' का अर्थ है कोई व्यक्ति विशेष, फार्म, सोसायटी, कम्पनी, कॉर्पोरेशन अथवा अन्य कोई वैध व्यक्ति।

9.46 'नीति' का अर्थ है समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2004—2009।

9.47 'निर्धारित' का अर्थ है विदेश व्यापार (विकास और विनियम) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22)

	अथवा इसके अन्तर्गत बनाये गए नियम अथवा आदेश या नीति के तहत निर्धारित से है।	9.55	'जहाज' का अर्थ समुद्र से किए जाने वाले व्यापार या समुद्रतट पर किए जाने वाले व्यापार के लिए प्रयुक्त सभी प्रकार के पोतों से है इसमें पुराने पोत भी शामिल हैं।
9.48	'सार्वजनिक सूचना' का अर्थ नीति के पैरा 2.4 के प्रावधानों के अधीन प्रकाशित सूचना से है।		
9.49	'कच्ची सामग्री' का अर्थ है: 1. मूल सामग्री जिसकी माल के विनिर्माण में आवश्यकता होती है, परन्तु वह अभी कच्ची, प्राकृतिक, अपरिष्कृत अथवा अविनिर्मित अवस्था में हो, और 2. किसी विनिर्माण के लिए वह सामग्री या माल जिसकी उसे विनिर्माण प्रक्रिया में आवश्यकता होती हो, चाहे वह सामग्री या माल वास्तव में पहले से विनिर्मित हो या संसाधित किया जाए या वह अब भी कच्ची या प्राकृतिक अवस्था में हो।	9.56	'एस आई ओ एन' का अर्थ विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा प्रकिया पुस्तक (खण्ड-2) 2002—2007 में अधिसूचित/अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित, मानक निवेश उत्पादन मानदण्डों से है।
		9.57	'स्पेयर्स' का तात्पर्य प्रतिस्थापन के लिए किसी पुर्जे या उप-असेम्बली या असेम्बली के अर्थात् किसी समान या एक ही तरह के भाग या उप-असेम्बली के स्थान पर रखे जाने वाले किसी भाग से है में संघटक या सहायक उपकरण शामिल होते हैं।
		9.58	'विनिर्दिष्ट' का तात्पर्य इस नीति के प्रावधानों द्वारा या के तहत विनिर्दिष्ट से है।
9.50	'पंजीकरण सह-सदस्यता प्रमाण-पत्र' (आर. सी. एम. सी) का तात्पर्य नीति या प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में यथानिर्धारित किसी निर्यात संवर्धन परिपद/वस्तु बोर्ड/विकास प्राधिकरण या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए गए पंजीकरण सह-सदस्यता प्रमाण-पत्र से है।	9.59	'स्तर धारक' का आशय उस निर्यातक से है जिसे विदेश व्यापार महानिदेशक या विकास आयुक्त ने पाँच सितारा व्यापार सदन के रूप में मान्यता दी हो।
9.51	'नियमों' का अर्थ है अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियम।	9.60	'एस टी पी' का अर्थ साफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क से है।
9.52	'सेवाओं में' सेवाओं के व्यापार पर सामान्य करार के अन्तर्गत आने वाली सभी व्यापारिक सेवाएं और मुक्त विदेशी मुद्रा अर्जित करना शामिल है।	9.61	'सहायक' विनिर्माण का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो किसी उत्पाद या उसके हिस्सों/उपांगों/संघटकों का विनिर्माण करता है। सहायक विनिर्माता के साथ-साथ निर्यातक का नाम निर्यात दस्तावेजों पर अवश्य निर्दिष्ट करना चाहिए।
9.53	'सेवा प्रदान करने वाला' का अर्थ है वह व्यक्ति जो:— 1. भारत से किसी और देश के लिए 'सेवा' प्रदान करता है, 2. भारत में किसी और देश के उपभोक्ता को भारत से प्रदान की गई सेवा की आपूर्ति करता है, और 3. भारत से किसी अन्य देश की धरती पर व्यापारिक या भौतिक उपस्थिति के माध्यम से सेवा की आपूर्ति करता है, 4. भारत में निर्यात से सम्बन्धित सेवा की आपूर्ति जिसका भुगतान मुक्त विदेशी मुद्रा में किया गया हो या भारतीय मुद्रा जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्यथा मुक्त विदेशी मुद्रा माना हो।	9.62	'तीसरी पार्टी द्वारा निर्यात' का आशय है निर्यातक या विनिर्माता द्वारा दूसरे निर्यातक की ओर से किए गए निर्यात। ऐसे मामलों में निर्यात दस्तावेजों जैसे शिपिंग बिल आदि में विनिर्माता निर्यातक/विनिर्माता और तीसरी पार्टी दोनों के नामों का उल्लेख होगा। बी आर सी जी आर घोषणा, निर्यात आदेश और बीजक तीसरी पार्टी निर्यातक के नाम से होना चाहिए।
		9.63	'विनियम मूल्य' से अभिप्राय है जो कि राजस्व विभाग के सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम में बताई गई है।
		9.64	'यूनिट अनुमोदन समिति का अर्थ है इसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाली विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई से सम्बन्धित विषयों पर/प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए अधिसूचित समिति।
9.54	'एस ई जेड' का तात्पर्य विशेष आर्थिक क्षेत्र है जिसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया है।	9.65	'वन्य प्राणी' का अर्थ है कोई वन्य प्राणी वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के खण्ड-2(36) में परिभाषित है।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th April, 2006

No. 1 (RE-2006)/2004—2009

S.O. 512(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) read with paragraph 1.2 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009, the Central Government hereby notifies the Foreign Trade Policy, 2004—2009 incorporating the Annual Supplement as updated on 7th April 2006 and contained in Annexure to this notification. The policy shall come into force w.e.f. 1st April, 2006.

This issues in Public interest.

[F. No. 01/94/180/Foreign Trade Policy/AM07/PC-I]

K. T. CHACKO, Director General of Foreign Trade and
Ex-Officio Addl. Secy.**ANNEXURE****FOREIGN TRADE POLICY, 2004—2009****PREAMBLE****CONTEXT**

For India to become a major player in world trade, an all encompassing, comprehensive view needs to be taken for the overall development of the country's foreign trade. While increase in exports is of vital importance, we have also to facilitate those imports which are required to stimulate our economy. Coherence and consistency among trade and other economic policies is important for maximizing the contribution of such policies to development. Thus, while incorporating the existing practice of enunciating an annual Exim Policy, it is necessary to go much beyond and take an integrated approach to the developmental requirements of India's foreign trade. This is the context of the new Foreign Trade Policy.

OBJECTIVES

Trade is not an end in itself, but a means to economic growth and national development. The primary purpose is not the mere earning of foreign exchange, but the stimulation of greater economic activity. The Foreign Trade Policy is rooted in this belief and built around two major objectives. These are :

- (i) To double our percentage share of global merchandise trade within the next five years; and
- (ii) to act as an effective instrument of economic growth by giving a thrust to employment generation.

STRATEGY

These objectives are proposed to be achieved by adopting, among others, the following strategies :

- (i) Unshackling of controls and creating an atmosphere of trust and transparency to

unleash the innate entrepreneurship of our businessmen, industrialists and traders.

- (ii) Simplifying procedures and bringing down transaction costs.
- (iii) Neutralizing incidence of all levies and duties on inputs used in export products, based on the fundamental principle that duties and levies should not be exported.
- (iv) facilitating development of India as a global hub for manufacturing, trading and services.
- (v) Identifying and nurturing special focus areas which would generate additional employment opportunities, particularly in semi-urban and rural areas, and developing a series of 'Initiatives' for each of these.
- (vi) Facilitating technological and infrastructural upgradation of all the sectors of the Indian economy, especially through import of capital goods and equipment, thereby increasing value addition and productivity, while attaining internationally accepted standards of quality.
- (vii) Avoiding inverted duty structures and ensuring that our domestic sectors are not disadvantaged in the Free Trade Agreements/Regional Trade Agreements/Preferential Trade Agreements that we enter into in order to enhance our exports.
- (viii) Upgrading our infrastructural network, both physical and virtual, related to the entire Foreign Trade chain, to international standards.
- (ix) Revitalising the Board of Trade by redefining its role, giving it due recognition and inducting experts on Trade Policy.
- (x) Activating our Embassies as key players in our export strategy and linking our commercial Wings abroad through an electronic platform for real time trade intelligence and enquiry dissemination.

PARTNERSHIP

The new Policy envisages merchant exporters and manufacturer exporters, business and industry as partners of Government in the achievement of its stated objectives and goals. Prolonged and unnecessary litigation vitiates the premise of partnership. In order to obviate the need for litigation and nurture a constructive and conducive atmosphere, a suitable Grievance Redressal Mechanism will be established which, it is hoped, would substantially reduce litigation and further a relationship of partnership.

The dynamics of a liberalized trading system sometimes results in injury caused to domestic industry on account of dumping. When this happens, effective measures to redress such injury will be taken.

ROADMAP:

This Policy is essentially a roadmap for the development of India's foreign trade. It contains the basic principles and points the direction in which we propose to go. By virtue of its very dynamics, a trade policy cannot be fully comprehensive in all its details. It would naturally require modification from time to time. We propose to do this through continuous updation, based on the inevitable changing dynamics of international trade. It is in partnership with business and industry that we propose to erect milestones on this roadmap.

KAMAL NATH, Minister for Commerce & Industry, Government of India

New Delhi

31st August, 2004

CHAPTER 1A LEGAL FRAME WORK

Preamble

1.1 **Preamble:** The Preamble spells out the broad framework and is an integral part of the Foreign Trade Policy.

Duration

1.2 In exercise of the powers conferred under Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), the Central Government hereby notifies the Foreign Trade Policy for the period 2004—2009 incorporating the Export and Import Policy for the period 2002—2007, as modified. This Policy shall come into force with effect from 1st September, 2004 and shall remain in force upto 31st March, 2009 unless as otherwise specified.

Amendments

1.3 The Central Government reserves the right in public interest to make any amendments to this Policy in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Act. Such amendment shall be made by means of a Notification published in the Gazette of India.

Transitional Arrangement

1.4 Any Notification made or Public Notices issued or anything done under the previous Export/Import policies, and in force immediately before the commencement of this Policy shall, in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Policy, continue to be in force and shall be deemed to have been made, issued or done under this Policy.

Authorisations, certificates and permission issued before the commencement of this Policy shall continue to be valid for the purpose and duration for which such Authorisation, certificate or permission was issued, unless otherwise stipulated.

1.5 In case an export or import that is permitted freely under this Policy is subsequently subjected to any

restriction or regulation, such export or import will ordinarily be permitted notwithstanding such restriction or regulation, unless otherwise stipulated, provided that the shipment of the export or import is made within the original validity of an irrevocable letter of credit established before the date of imposition of such restriction.

CHAPTER IB**SPECIAL FOCUS INITIATIVES****Special Focus Initiatives**

IB.1 With a view to doubling our percentage share of global trade within 5 years and expanding employment opportunities, especially in semi-urban and rural areas, certain special focus initiatives have been identified for the agriculture, handlooms, handicraft, gems & jewellery, leather and marine sectors.

Government of India shall make concerned efforts to promote exports in these sectors by specific sectoral strategies that shall be notified from time to time.

New Sectoral Initiatives to be announced

Further Sectoral Initiatives in other sectors will also be announced from time to time.

For the present, the thrust sectors indicated below shall be extended the following facilities:

- (i) Agriculture and Village Industry
 - (a) A new scheme called the Vishesh Krishi and Gram Udyog Yojana (Special Agricultural and Village Industry Scheme) for promoting export of Fruits, Vegetables, Flowers, Minor forest produce, Dairy, Poultry and their value added products and Gram Udyog products has been introduced (Para 3.8).
 - (b) Funds shall be earmarked under ASIDF for development of Agri Export Zones (AEZ)
 - (c) Deleted.
 - (d) Deleted.
 - (e) Capital goods imported under EPCG shall be permitted to be installed anywhere in the AEZ.
 - (f) Import of restricted items, such as panels, shall be allowed under the various export promotion schemes.
 - (g) Import of inputs such as pesticides shall be permitted under the Advance Authorisation for agro exports.
 - (h) New towns of export excellence with a threshold limit of Rs. 250 crore shall be notified

(ii) Handlooms :

- (a) Specific fund would be earmarked under MAI/MDA Scheme for promoting handloom exports.
- (b) Duty free import entitlement of specified trimmings and embellishments shall be 5% of FOB value of exports during the previous financial years.
- (c) Duty free import entitlement of hand knotted carpet samples shall be 1% of FOB value of exports during the previous financial years.
- (d) Duty free import of old pieces of hand knotted carpets on consignment basis for re-export after repair shall be permitted.
- (e) New towns of export excellence with a threshold limit of Rs 250 crore shall be notified.
- (f) Government has decided to develop a trade mark for Handloom on lines similar to 'Woolmark' and 'Silkmark'. This will enable handloom products to develop a niche market with a distinct identity.

(iii) Handicrafts :

- (a) New Handicraft SEZs shall be established which would procure products from the cottage sector and do the finishing for exports.
- (b) Duty free import entitlement of trimmings and embellishments shall be 5% of the FOB value of exports during the previous financial year. The entitlement is broad banded, and shall extend also to merchant exporters tied up with supporting manufacturers.
- (c) The Handicraft Export Promotion Council shall be authorized to import trimmings, embellishments and consumables on behalf of those exporters for whom directly importing may not be viable.
- (d) Specific funds would be earmarked under MAI & MDA Schemes for promoting Handicraft exports.
- (e) CVD is exempted on duty free import of trimmings, embellishments and consumables.
- (f) New towns of export excellence with a reduced threshold limit of Rs. 250 crore shall be notified.

(iv) Gems & Jewellery :

- (a) Import of gold of 8K and above shall be allowed under the replenishment scheme subject to the import being accompanied by an Assay Certificate specifying the purity, weight and alloy content.
- (b) Duty free import entitlement of consumables for metals other than Gold, Platinum shall be 2% of FOB value of exports during the previous financial year.
- (c) Duty free import entitlement of commercial samples shall be Rs 300,000.
- (d) Duty free re-import entitlement for rejected jewellery shall be 2% of the FOB value of exports
- (e) Cutting and polishing of gems and jewellery shall be treated as manufacturing for the purposes of exemption under Section 10A of the Income Tax Act.

(v) Leather and Footwear :

- (a) Duty free import entitlement of specified items shall be 5% of FOB value of exports during the preceding financial year.
- (b) The duty free entitlement for the import of trimmings, embellishments and footwear components for footwear (leather as well as synthetic), gloves, travel bags and handbags shall be 3% of FOB value of exports of the previous financial year. The entitlement shall also cover packing material, such as printed and non-printed shoeboxes, small cartons made of wood, tin or plastic materials for packing footwear.
- (c) Machinery and equipment for effluent Treatment Plants shall be exempt from basic customs duty.
- (d) Re-export of unsuitable imported materials such as raw hides & skins and wet blue leathers is permitted.
- (e) CVD is exempted on lining and interlining material notified at S. No. 168 of Customs Notification No. 21/2002 dated 01-03-2002.
- (f) CVD is exempted on raw, tanned and dressed fur skins falling under Chapter 43 of ITC (HS).

Package for Marine Sector

- (vi) (a) Duty free import of specified specialised inputs/ chemicals and flavouring oils etc. to be allowed to the extent of 1% of FOB value of preceding financial years export.
- (b) To allow import of monofilament long line system for tuna fishing at a concessional rate of duty.
- (c) A self removal procedure for clearance of seafood waste to be applicable subject to prescribed wastage norms.

Optimum Development Programme for Pragati Maidan

1B.2 In order to showcase our industrial and trade prowess to its best advantage and leverage existing facilities to enhance the quantity of space and service, Pragati Maidan will be transformed into a world-class complex with visitor friendliness ingress and egress system. The complex utilisation will be improved, increased and diversified. There shall be brand new, state-of-the art, environmentally-controlled, air-conditioned exhibition areas, and Permanent Exhibition Marts. In addition, a large Convention Centre to accommodate ten thousand delegates will be developed, with multiple and flexible hall spaces, auditoria and meeting rooms with hi-tech equipment. A year round Food and Beverage destination will be developed, with a large number of outlets covering all cuisines and pricing levels. There will be a multi-level park to accommodate over nine thousand vehicles within the envelope of Pragati Maidan.

CHAPTER-1C**Board of Trade****Board of Trade**

1C.1 The Board of Trade has been revamped and given a clear and dynamic role in advising government on relevant issues connected with Foreign Trade Policy. There would be a process of continuous interaction between the Board of Trade and Government in order to achieve the desired objective of boosting India's exports.

Terms of Reference

1C.2 The Board of Trade would have the following terms of reference :

- I To advise the Government on Policy measures for preparation and implementation of both short and long term plans for increasing exports in the light of emerging national and international economic scenarios;
- II To review export performance of various sectors, identify constraints and suggest industry specific measures to optimize export earnings;

III To examine the existing institutional framework for imports & exports and suggest practical measures for further streamlining to achieve the desired objectives;

IV To review the policy instruments and procedures for imports & exports and suggest steps to rationalize and channelise such schemes for optimum use;

V To examine issues which are considered relevant for promotion of India's foreign trade, and to strengthen the international competitiveness of Indian goods and services, and

VI To commission studies for furtherance of the above objectives.

Composition

1C.3 Government shall nominate an eminent person or expert on trade policy to be Chairman of the Board of Trade. Government shall also nominate 25 persons, of whom at least 10 will be experts in trade policy. In addition, Chairmen of recognized Export Promotion Councils and President or Secretary-Generals of National Chambers of Commerce will be ex-officio members.

Meetings

1C.4 The Board will meet at least once every quarter and make recommendations to Government on issues pertaining to its terms of reference.

Sub-committee

1C.5 The Board of Trade will have the power to set up sub-committees and to co-opt experts to these, to make recommendations on specific sectors and objectives.

Secretariat and Budget Head

1C.6 The Board of Trade will have a Secretariat and Budget Head and shall be serviced by the Department of Commerce.

CHAPTER-2**General Provisions Regarding Imports and Exports****Exports and Imports free unless regulated**

2.1 Exports and Imports shall be free, except in cases where they are regulated by the provisions of this Policy or any other law for the time being in force. The item wise export and import policy shall be, as specified in ITC (HS) published and notified by Director General of Foreign Trade, as amended from time to time.

Compliance with Laws

2.2 Every exporter or importer shall comply with the provisions of the Foreign Trade (Development and

Regulation) Act, 1992, the Rules and Orders made thereunder, the provisions of this Policy and the terms and conditions of any Licence/certificate/permission/Authorisation granted to him, as well as provisions of any other law for the time being in force. All imported goods shall also be subject to domestic Laws, Rules, Orders, Regulations, technical specifications, environmental and safety norms as applicable to domestically produced goods. No Import or Export of rough diamonds shall be permitted unless the shipment parcel is accompanied by Kimberley Process (KP) Certificate required under the procedure specified by the Gem & Jewellery Export Promotion Council (GJEPC).

Interpretation of Policy

2.3 If any question or doubt arises in respect of the interpretation of any provision contained in this policy, or regarding the classification of any item in the ITC (HS) or Handbook (Vol. 1) or Handbook (Vol. 2), or Schedule of DEPB Rate the said question or doubt shall be referred to the Director General of Foreign Trade whose decision thereon shall be final and binding.

If any question or doubt arises whether a licence/certificate/permission has been issued in accordance with this Policy or if any question or doubt arises touching upon the scope and content of such documents, the same shall be referred to the Director General of Foreign Trade whose decision thereon shall be final and binding.

Procedure

2.4 The Director General of Foreign Trade may, in any case or class of cases, specify the procedure to be followed by an exporter or importer or by any licensing or any other competent authority for the purpose of implementing the provisions of the Act, The Rules and the Orders made thereunder and this Policy. Such procedures shall be included in the Handbook (Vol. 1), Handbook (Vol. 2), Schedule of DEPB Rate and in ITC (HS) and Published by means of a Public Notice. Such procedures may, in like manner, be amended from time to time.

The Handbook (Vol. 1) is a supplement to the Foreign Trade Policy and contains relevant procedures and other details. The procedure of availing benefits under various schemes of the Policy are given in the Handbook (Vol. 1).

Exemption from Policy/Procedure

2.5 Any request for relaxation of the provisions of this Policy or of any procedure, on the ground that there is genuine hardship to the applicant or that a strict application of the Policy or the procedure is likely to have an adverse impact on trade, may be made to the Director General of Foreign Trade for such relief as may be necessary. The Director General of Foreign Trade may pass such orders or grant such relaxation or relief, as he may deem fit and proper.

The Director General of Foreign Trade may, in public interest, exempt any person or class or category of persons

from any provision of this Policy or any procedure and may, while granting such exemption, impose such conditions as he may deem fit. Such request may be considered only after consulting Norms Committee (NC) if the request is in respect of a provision of Chapter-4 (excluding any provision relating to Gem & Jewellery sector) and EPCG Committee if the request is in respect of a provision of Chapter-5 of the Policy/Procedure. However, any such request in respect of a provision other than Chapter-4, Chapter-5 and Gem & Jewellery sector as given above may be considered only after consulting Policy Relaxation Committee.

Principles of Restriction

2.6 DGFT may, through a notification, adopt and enforce any measure necessary for :—

- i Protection of public morals.
- ii Protection of human, animal or plants life or health.
- iii Protection of patents, trademarks and copyrights and the prevention of deceptive practices.
- iv Prevention of use of prison labour.
- v Protection of national treasures of artistic, historic or archeological value.
- vi Conservation of exhaustible natural resources.
- vii Protection of trade of fissionable material or material from which they are derived; and
- viii Prevention of traffic in arms, ammunition and implements of war.

Restricted Goods

2.7 Any goods, the export or import of which is restricted under ITC (HS) may be exported or imported only in accordance with a licence/certificate/permission or a public notice issued in this behalf.

Terms and Conditions of a Licence/Certificate/Permission

2.8 Every Licence/certificate/permission/Authorisation shall be valid for the period of validity specified in the Licence/certificate/permission and shall contain such terms and conditions as may be specified by the licensing authority which may include:

- (a) The quantity, description and value of the goods;
- (b) Actual Use condition;
- (c) Export obligation;
- (d) The value addition to be achieved; and
- (e) The minimum export price.

Authorisation/Licence/Certificate/Permission not a Right

2.9 No person may claim a licence/certificate/permission as a right and the Director General of Foreign Trade or the regional authority shall have the power to refuse to grant or renew a Licence/certificate/permission/Authorisation in accordance with the provisions of the Act and the Rules made thereunder.

Penalty

2.10 If a Licence/certificate/Permission/Authorisation holder violates any condition of the Licence/certificate/permission or fails to fulfill the export obligation, he shall be liable for action in accordance with the Act, the Rules and Orders made thereunder, the Policy and any other law for the time being in force.

State Trading

2.11 Any goods, the import or export of which is governed through exclusive or special privileges granted to State Trading Enterprise(s), may be imported or exported by the State Trading Enterprise(s) as specified in the ITC (HS) Book subject to the conditions specified therein. The Director General of Foreign Trade may, however, grant a Licence/certificate/Permission/Authorisation to any other person to import or export any of these goods.

In respect of goods the import or export of which is governed through exclusive or special privileges granted to State Trading Enterprise(s), the State Trading Enterprise(s) shall make any such purchases or sales involving imports or exports solely in accordance with commercial considerations, including price, quality, availability, marketability, transportation and other conditions of purchase or sale. These enterprises shall act in a non-discriminatory manner and shall afford the enterprises of other countries adequate opportunity, in accordance with customary business practice, to compete for participation in such purchases or sales.

Importer-Exporter Code Number

2.12 No export or import shall be made by any person without an Importer-Exporter Code (IEC) number unless specifically exempted. An Importer-Exporter Code (IEC) number shall be granted on application by the competent authority in accordance with the procedure specified in the Handbook (Vol. 1).

Trade with neighbouring Countries

2.13 The Director General of Foreign Trade may issue, from time to time, such instructions or frame such schemes as may be required to promote trade and strengthen economic ties with neighbouring countries.

Transit Facility

2.14 Transit of goods through India from or to countries adjacent to India shall be regulated in accordance with the bilateral treaties between India and those countries

and will be subject to such restrictions as may be specified by DGFT in accordance with International Conventions.

Trade with Russia under Debt-Repayment Agreement

2.15 In the case of trade with Russia under the Debt Repayment Agreement, the Director General of Foreign Trade may issue, from time to time, such instructions or frame such schemes as may be required, and anything contained in this Policy, in so far as it is inconsistent with such instructions or schemes, shall not apply.

Actual User Condition

2.16 Capital goods, raw materials, intermediates, components, consumables, spares parts, accessories, instruments and other goods, which are importable without any restrictions, may be imported by any person.

However, if such imports require a licensee/certificate/permission, the actual user alone may import such goods unless the actual user condition is specifically dispensed with by the licensing authority.

Second Hand Goods

2.17 All second hand goods, except second hand capital goods, shall be restricted for imports and may be imported only in accordance with the provisions of this Policy, ITC (HS), Handbook (Vol. 1), Public Notice or a Licence/certificate/permission/Authorisation issued in this behalf.

Import of second hand capital goods, including refurbished/re-conditioned spares shall be allowed freely. However, second hand personal computers/laptops, photocopier machines, air conditioners, diesel generating sets will only be allowed against a license issued in this behalf.

Import of re-manufactured goods shall be allowed only against a licence issued in this behalf.

Import of samples

2.18 Import of samples shall be governed by the provisions given in Handbook (Vol. 1).

Import of Gifts

2.19 Import of gifts shall be permitted where such goods are otherwise freely importable under this Policy. In other cases, a Customs Clearance Permit (CCP) shall be required from the DGFT.

Passenger Baggage

2.20 Bonafide household goods and personal effects may be imported as part of passenger baggage as per the limits, terms and conditions thereof in the Baggage Rules notified by the Ministry of Finance.

Samples of such items that are otherwise freely importable under this Policy may also be imported as part of passenger baggage without a Licence/Certificate/Permission/Authorisation.

Exporters coming from abroad are also allowed to import drawings, patterns, labels, price tags, buttons, belts, trimming and embellishments required for export, as part of their passenger baggage without a Licence/certificate/permission/Authorisation.

Import on Export basis

2.21 New or second hand capital goods, equipments, components, parts and accessories, containers meant for packing of goods for exports, jigs, fixtures, dies and moulds may be imported for export without a Licence/certificate/permission/Authorisation on execution of Legal Undertaking/Bank Guarantee with the Customs Authorities provided that the item is freely exportable without any conditionality/requirement of Licence/Permission as may be required under ITC(HS) Schedule II.

Re-import of goods repaired abroad

2.22 Capital goods, equipments, components, parts and accessories, whether imported or indigenous, except those restricted under ITC (HS) may be sent abroad for repairs, testing, quality improvement or upgradation or standardization of technology and re-imported without a Licence/certificate/permission/Authorisation.

Import of goods used in projects abroad

2.23 After completion of the projects abroad, project contractors may import, without a licence/certificate/permission, used goods including capital goods provided they have been used for at least one year.

Sale on High Seas

2.24 Sale of goods on high seas for import into India may be made subject to this Policy or any other law for the time being in force.

Import under Lease Financing

2.25 Permission of licensing authority is not required for import of new capital goods under lease financing.

Clearance of Goods from Customs

2.26 The goods already imported/shipped/arrived, in advance, but not cleared from Customs may also be cleared against the Licence/certificate/permission issued subsequently.

Execution of BG/LUT

2.27 Wherever any duty free import is allowed or where otherwise specifically stated, the importer shall execute a Legal Undertaking (LUT)/Bank Guarantee (BG)/Bond with the Customs Authority before clearance

of goods through the Customs, in the manner as may be prescribed. In case of indigenous sourcing, the Licence/certificate/permission holder shall furnish LUT/BG/Bond to the licensing authority before sourcing the material from the indigenous supplier/nominated agency.

Exemption from Bank Guarantee

2.27.1 All the exporters who have an export turnover of at least Rupees 5 crore in the current or preceding licencing year and have a good track record of three years of exports will be exempted from furnishing a BG for any of the schemes under this Policy and may furnish a LUT in lieu of BG.

Private/Public Bonded Warehouses for Imports

2.28 Private/Public bonded warehouses may be set up in the Domestic Tariff Area as per the terms and conditions of notification issued by the Department of Revenue.

Any person may import goods except prohibited items, arms and ammunition, hazardous waste and chemicals and warehouse them in such private/public bonded warehouses.

Such goods may be cleared for home consumption in accordance with the provisions of this Policy and against Licence/certificate/permission, wherever required. Customs duty as applicable shall be paid at the time of clearance of such goods.

If such goods are not cleared for home consumption within a period of one year or such extended period as the custom authorities may permit, the importer of such goods shall re-export the goods.

Free Exports

2.29 All goods may be exported without any restriction except to the extent such exports are regulated by ITC (HS) or any other provision of this Policy or any other law for the time being in force.

The Director General of Foreign Trade may, however, specify through a public notice such terms and conditions according to which any goods, not included in the ITC (HS), may be exported without a licence/certificate/permission.

Export of Samples

2.30 Export of samples and Free of charge goods shall be governed by the provisions given in Handbook (Vol. I).

Export of Passenger Baggage

2.31 Bonafide personal baggage may be exported either alongwith the passenger or, if unaccompanied, within one year before or after the passenger's departure from India. However, items mentioned as Restricted in ITC (HS) shall require a Licence/certificate/permission Authorisation.

Export of Gifts

2.32 Goods, including edible items, of value not exceeding Rs. 5,00,000/- in a licensing year, may be exported as a gift.

However, items mentioned as restricted for exports in ITC (HS) shall not be exported as a gift, without a Licence/certificate/permission/Authorisation.

Export of Spares

2.33 Warranty spares, whether indigenous or imported, of plant, equipment, machinery, automobiles or any other goods, except those restricted under ITC(HS), may be exported alongwith the main equipment or subsequently but within the contracted warranty period of such goods subject to approval of RBI.

Third Party Exports

2.34 Third party exports, as defined in Chapter 9 shall be allowed under the policy.

Export of Imported Goods

2.35 Goods imported, in accordance with this Policy, may be exported in the same or substantially the same form without a Licence/certificate/permission/Authorisation provided that the item to be imported or exported is not mentioned as restricted for import or export in the ITC (HS).

Exports of such goods imported against payment in freely convertible currency would be permitted against payment in freely convertible currency.

2.36 Goods, including those mentioned as restricted item for import (except prohibited items) may be imported under Customs Bond for export in freely convertible currency without a licence/certificate/permission provided that the item is freely exportable without any conditionality/requirement of Licence/permission as may be required under ITC (HS) Schedule II.

Export of Replacement Goods

2.37 Goods or parts thereof on being exported and found defective damaged or otherwise unfit for use may be replaced free of charge by the exporter and such goods shall be allowed clearance by the customs authorities provided that the replacement goods are not mentioned as restricted items for exports in ITC (HS).

Export of Repaired Goods

2.38 Goods or parts, except restricted under ITC (HS), thereof on being exported and found defective, damaged or otherwise unfit for use may be imported for repair and subsequent re-export.

Such goods shall be allowed clearance without a licence/certificate/permission and in accordance with customs notification issued in this behalf.

Private Bonded Warehouses for Exports

2.39 Private bonded warehouses exclusively for exports may be set up in DTA as per the terms and conditions of the notifications issued by Department of Revenue.

Such warehouses shall be entitled to procure the goods from domestic manufacturers without payment of duty. The supplies made by a domestic supplier to the notified warehouses shall be treated as physical exports provided the payments for the same are made in free foreign exchange.

Denomination of Export Contracts

2.40 All export contracts and invoices shall be denominated either in freely convertible currency or Indian rupees but the export proceeds shall be realised in freely convertible currency.

However export proceeds against specific exports may also be realized in rupees provided it is through a freely convertible Vostro account of a non resident bank situated in any country other than a member country of ACU or Nepal or Bhutan. Additionally, the rupee payment through the Vostro account must be against payment in free foreign currency by the buyer in his non resident bank account. The free foreign exchange remitted by the buyer to his non resident bank (after deducting the bank service charges) on account of this transaction would be taken as the export realization under the export promotion schemes of this Policy.

Contracts for which payments are received through the Asian Clearing Union (ACU) shall be denominated in ACU Dollar. The Central Government may relax the provisions of this paragraph in appropriate cases. Export contracts and Invoices can be denominated in Indian rupees against EXIM Bank/Government of India line of credit.

Realisation of export Proceeds

2.41 If an exporter fails to realise the export proceeds within the time specified by the Reserve Bank of India, he shall, without prejudice to any liability or penalty under any law for the time being in force, be liable to action in accordance with the provisions of the Act the Rules and Orders made thereunder and the provisions of this Policy.

Free Movement of Export Goods

2.42 Consignments of items meant for exports shall not be withheld/delayed for any reason by any agency of the Central/State Government. In case of any doubt, the authorities concerned may ask for an undertaking from the exporter.

No Seizure of Stock

2.42.1 No seizure of stock shall be made by any agency so as to disrupt the manufacturing activity and delivery schedule of export goods. In exceptional cases,

the concerned agency may seize the stock on the basis of *prima facie* evidence. However, such seizure should be lifted within 7 days.

Export Promotion Councils

2.43 The basic objective of Export Promotion Councils is to promote and develop the exports of the country. Each Council is responsible for the promotion of a particular group of products, projects and services. The list of the councils, and their main functions are given in Handbook (Vol. 1).

Registration-cum-Membership Certificate

2.44 Any person, applying for (i) a licence/authorisation/certificate/permission to import/export, [except items listed as restricted items in ITC (HS)] or (ii) any other benefit or concession under this policy shall be required to furnish Registration-cum-Membership Certificate (RCMC) granted by the competent authority in accordance with the procedure specified in the Handbook (Vol. 1) unless specifically exempted under the policy.

2.45. Deleted

Trade Facilitation through EDI Initiatives

2.45.1 It is endeavour of the Government to work towards greater simplification, standardization and harmonization of trade documents using international best practices. As a step in this direction DGFT shall move towards an automated environment for electronic filing, retrieval and authentication of documents based on agreed protocols and message exchange with other community partners including Customs and Banks.

DGCI&S Commercial Trade Data

2.45.2 To enable the users to make commercial decisions in a more professional manner, DGCI&S trade data shall be made available with a minimum time lag in a query based structured format on a commercial criteria.

Fiscal Incentives to Promote EDI Initiatives Adoption

2.45.3 With a view to promote the use of Information Technology, DGFT will provide fiscal incentives to the user community. The details are enumerated in the Handbook (Vol. 1).

Regularization of EO Default and Settlement of Customs Duty and Interest through Settlement Commission

2.46 With a view to providing assistance to firms who have defaulted under the Foreign Trade Policy for reasons beyond their control as also facilitating the merger, acquisition and rehabilitation of sick units, it has been

decided to empower the Settlement Commission in the Central Board of Excise and Customs to decide such cases also with effect from 1-04-2005.

Easing of Documentation Requirement

2.47 Pending the finalisation of Single Common Document (SCD) for international trade, the Government Departments dealing with exports and imports will honour the permission license/certificate issued by the other Government departments based on the verification of the export documents like Shipping bill, Bank realization certificate, Packing list, Bill of lading etc. and will not insist upon fresh submission of these documents.

Remission of Service Tax in DTA

2.48.1 For all goods and services which are exported from Unit in Domestic Tariff Area (DTA) and units in EOU/EHTP/STP/BTP remission of service tax levied shall be allowed.

Exemption from Service Tax in SEZ

2.48.2 Units in SEZ shall be exempted from service tax.

GRIEVANCE REDRESSAL

DGFT as a Facilitator of Exports/Imports

2.49 DGFT has a commitment to function as a facilitator of exports and imports. Our focus is on good governance, which depends on clean, transparent and accountable delivery systems.

Citizen's Charter

2.49.1 DGFT has in place a Citizen's Charter which lays down its commitment to serve importers and exporters. It also gives time schedules for providing services to clients, and details of grievance committees at different levels.

Grievance Redressal Mechanism

2.49.2 In order to facilitate speedy redressal of grievances of trade and industry, a new grievance redressal mechanism has been put in place by a Government Resolution.

The Government is committed to resolving all outstanding problems and disputes pertaining to the past policy periods through the Grievance Redressal Committee set up on 27-10-2004, for condoning delays, regularizing breaches by exporters in *bonafide* cases, resolving disputes over entitlements, granting extensions for utilization of licences etc.

2.49.3 Deleted

CHAPTER-3**PROMOTIONAL MEASURES*****Assistance to States for Infrastructure Development of Exports (ASIDE)***

3.1 The State Government shall be encouraged to participate in promoting exports from their respective States. For this purpose, Department of Commerce has formulated a scheme called ASIDE.

Suitable provision has been made in the Annual Plan of the Department of Commerce for allocation of funds to the States on the twin criteria of gross exports and the rate of growth of exports.

The States shall utilise this amount for developing infrastructure such as roads connecting production centres with the ports, setting up of Inland Container Depots and Container Freight Stations, creation of new State level export promotion industrial parks/zones, augmenting common facilities in the existing zones, equity participation in infrastructure projects, development of minor ports and jetties, assistance in setting up of common effluent treatment facilities, stabilizing power supply and any other activity as may be notified by Department of Commerce from time to time.

Market Access Initiative (MAI)

3.2 The Market Access Initiative (MAI) scheme is intended to provide financial assistance for medium term export promotion efforts with a sharp focus on a country and product.

The financial assistance is available for Export Promotion Councils, Industry and Trade Associations, Agencies of State Governments, Indian Commercial Missions abroad and other eligible entities as may be notified from time to time.

A whole range of activities can be funded under the MAI scheme. These include market studies, setting up of showroom/warehouse, sales promotion campaigns, international departmental stores, publicity campaigns, participation in international trade fairs, brand promotion, registration charges for pharmaceuticals and testing charges for engineering products etc. Each of these export promotion activities can receive financial assistance from the Government ranging from 25% to 100% of the total cost depending upon the activity and the implementing agency, as indicated in the detailed guidelines. The full text of the guidelines can be seen at <http://commerce.nic.in>.

Marketing Development Assistance (MDA)

3.2.1 The Marketing Development Assistance (MDA) Scheme is intended to provide financial assistance for a range of export promotion activities implemented by export promotion councils, industry and trade associations on a regular basis every year.

As per the revised MDA guidelines, assistance under MDA is available for exports with annual export turnover up to Rs. 10 crores.

These include participation in Trade Fairs and Buyer Seller meets abroad or in India, export promotion seminars etc.

Further, assistance for participation in Trade Fairs abroad and travel grant is available to such exporters if they travel to countries in one of the four Focus Areas, such as, Latin America, Africa, CIS Region, ASEAN countries, Australia and New Zealand.

For participation in trade fairs etc., in other areas financial assistance without travel grant is available.

Meeting Legal expenses for Trade related matters

3.2.1.1 Financial assistance would be provided to deserving exporters on the recommendation of Export Promotion Councils for meeting the cost of legal expenses relating to trade related matters.

Towns of Export Excellence

3.3 A number of towns in specific geographical locations have merged as dynamic industrial clusters contributing handsomely to India's exports. It is necessary to grant recognition to these industrial clusters with a view to maximizing their potential and enabling them to move higher in the value chain and tap new markets.

Selected towns producing goods of Rs. 1000 crore or more will be notified as Towns of Exports Excellence on the basis of potential for growth in exports. However, for the Towns of Export Excellence in the handloom, handicraft, Agriculture and Fisheries sector, the threshold limit would be Rs. 250 crores.

Common service providers in these areas shall be entitled for the facility of the EPCG Scheme.

The recognized associations of units will be able to access the funds under the Market Access Initiative scheme for creating focused technological services.

Further such areas will receive priority for assistance for rectifying identified critical infrastructure gaps from the ASIDE scheme.

The notified towns of export excellence are listed in Appendix 7.

Brand Promotion and Quality

3.4.1 The Central Government aims to encourage manufacturers and exports to attain internationally accepted standards of quality for their products. The Central Government will extend support and assistance to Trade and Industry to launch a nationwide programme on quality awareness and to promote the concept of total quality management.

Test Houses

3.4.2 The Central Government will assist in the modernisation and upgradation of test houses and laboratories in order to bring them at par with international standards.

Quality Complaints/Disputes

3.4.3 The Regional Sub-Committee on Quality Complaints (RSCQC) set up at the Regional Offices of the Directorate General of Foreign Trade shall investigate quality complaints received from foreign buyers. The guidelines for settlement of quality complaints, in particular, and such other complaints, in general, are given in Appendix-16 of Handbook of Procedures (Vol. I).

Trade disputes affecting trade relations

3.4.4 If it comes to the notice of the Director General of Foreign Trade or he has reason to believe that an export or import has been made in a manner that

- (i) is gravely prejudicial to the trade relations of India with any other country; and/or
- (ii) is gravely prejudicial to the interest of other persons engaged in exports or imports; and/or
- (iii) has brought disrepute to the country;

The Director General Foreign Trade may take action against the exporter or importer concerned in accordance with the provisions of the Act, The Rules and Orders made thereunder and this Policy.

3.5 STAR EXPORT HOUSES**Star Export House**

3.5.1 Merchant as well as Manufacturer Exporters, Service Providers, Export Oriented Units (EOUs) and units located in Special Economic Zones (SEZs), Agri Export Zones (AEZs), Electronic Hardware Technology Parks (EHTPs), Software Technology Parks (STPs) and Bio Technology Parks (BTPs) shall be eligible for applying for status as Star Export Houses.

Status Category

3.5.2 The applicant shall be categorized depending on his total FOB (FOR—for deemed export) export performance during the current plus the previous three years :

Category	Performance (Rupees in Crores)
One Star Export House	15
Two Star Export House	100
Three Star Export House	500
Four Star Export House	1500
Five Star Export House	5000

Note 1. Exporters in the Small Scale Industry/Tiny Sector/Cottage Sector. Units, registered with KVICs/KVIBs, Units located in North Eastern States, Sikkim and J&K. Units exporting handloom/handicrafts/hand knitted or silk carpets, exports exporting to countries in Latin America/CIS/sub-Saharan Africa as listed in Appendix-9. Units having ISO 9000 (series)/ISO 14000 (series)/WHOGMP/HACCP/SIEM CMM level-II and above status granted by agencies listed in Appendix-6. exports of services and exports of agro products shall be entitled for double weightage on exports made for grant of Star Export House status. The Double Weightage shall be admissible to Merchant as well as Manufacturer Exporters. However, a shipment can get double weightage only once in any one of the above categories.

- 1(a) Transfer of export performance from one to another is not permitted. Therefore disclaimer system shall not be allowed for counting of export turnover.
2. Exports made on re-export basis shall not be counted for the purpose of recognition.
3. Exports made by a subsidiary of a limited company shall be counted towards export performance of the limited company for the purpose of recognition only if the limited company has a majority share holding in the subsidiary company.
4. Recognition of One Star Export House status shall be considered only in case the exporter has minimum export performance of Rs. 15 Crores or more during any two years out of the current and preceding three years.

Privileges

3.5.2.1 A Star Export House shall be eligible for the following facilities :

- (i) Authorisation/Licence/certificate/permissions and Customs clearances for both imports and exports on self-declaration basis;
- (ii) Fixation of Input-Output norms on priority within 60 days;
- (iii) Exemption from compulsory negotiation of documents through banks. The remittance, however, would continue to be received through banking channels;
- (iv) 100% retention of foreign exchange in EEEFC account;
- (v) Enhancement in normal repatriation period from 180 days to 360 days;

- (vi) Deleted
- (vii) Exemption from furnishing of Bank Guarantee in Schemes under this Policy.
- (viii) Two Star Export Houses and above shall be permitted to establish Export Warehouses, as per the guidelines issued by Department of Revenue in this regard.

Validity Period

3.5.3 All status certificates issued or renewed on or after 01-09-2004 shall be valid from 1st April of the licensing year during which the application for the grant of such recognition is made upto 31st March, 2009, unless otherwise specified.

On the expiry of status certificate, application for grant of status shall be required to be made within a period as prescribed in the Handbook of Procedures (Vol. I), as a fresh application for continued recognition. During the intervening period, the star export house shall be eligible to claim the usual privileges under Para 3.5.2.1 above; subject to furnishing of an undertaking by the applicant at the time of claiming such facilities and benefits that they are eligible for continued recognition as per current policy.

3.6 SERVICES EXPORTS

Services Exports

3.6.1 Services include all the 161 tradable services covered under the General Agreement on Trade in Services where payment for such services is received in free foreign exchange or in Indian Rupees which are otherwise considered as having been paid for in free foreign exchange by RBI. A list of services is given in Appendix-10 of Handbook of Procedures (Vol. I). All provisions of this Policy shall apply mutatis mutandis to export of services as they apply to goods, unless otherwise specified.

Export Promotion Council for Services

3.6.2 Service exporters are required to register themselves with the Federation of Indian Exporters Organisation. However, software exporters shall register themselves with Electronic and Software Export Promotion Council.

In order to give proper direction, guidance and encouragement to the Services Sector, an exclusive Export Promotion Council for Services shall be set up.

The Services Export Promotion Council shall :

- (i) Map opportunities for key services in key markets and develop strategic market access programmes for each component of the matrix.
- (ii) Co-ordinate with sectoral players in undertaking intensive brand building and marketing programmes in target markets.
- (iii) Make necessary interventions with regard to policies, procedures and bilateral/multilateral

issues, in co-ordination with recognised nodal bodies of the services industry.

Common Facility Centres

3.6.3 Government shall promote the establishment of Common Facility Centres for use by home-based service providers, particularly in areas like Engineering & Architectural design, Multi-media operations, Software developers etc., in State and District-level towns, to draw in a vast multitude of home-based professionals into the services export arena.

3.6.4 SERVED FROM INDIA SCHEME

Objective

3.6.4.1 The objective is to accelerate the growth in export of services so as to create a powerful and unique 'Served From India' brand, instantly recognized and respected world over.

Eligibility

3.6.4.2 All Services providers of services listed in Appendix-10 of Handbook of Procedures (Vol. I) who have a total foreign exchange earning or earning in Indian Rupees which are otherwise considered as having been paid for in free foreign exchange by RBI, of at least Rs. 10 lakhs in the preceding or current financial year shall be eligible to qualify for a duty credit script.

For individuals who are service providers of services listed in Appendix-10 of Handbook of Procedures (Vol. I), the total foreign exchange earned or earning in Indian Rupees which are otherwise considered as having been paid for in free foreign exchange by RBI criteria would be Rs. 5 lakhs in the preceding financial year.

Entitlement

3.6.4.3 All Service providers: including Healthcare and Educational Service providers as well as Engineering Process Outsourcing (EPO) and Knowledge Process Outsourcing (KPO) service providers; of services listed in Appendix-10 of Handbook of Procedures (Vol. I) (other than service providers covered by Para 3.6.4.4) shall be entitled to duty credit script equivalent to 10 % of the foreign exchange earned by them in the preceding financial year. However services or service providers as listed in Para 3.18.1 of Handbook of Procedures (Vol. I) shall not be entitled for benefits under the scheme.

Remittances

3.6.4.3.1 The foreign exchange earned through International Credit Cards and other instruments as permitted by RBI for rendering of service by the service providers shall also be taken into account for the purposes of computation of duty credit entitlement under the scheme.

Hotels & Restaurants

3.6.4.4 Hotels of one-star and above (including managed hotels and heritage hotels) approved by the

Department of Tourism and other Service providers in the tourism sector registered with the Department of Tourism shall be entitled to duty credit equivalent to 5% of the foreign exchange earned by them in the preceding financial year.

Stand-alone restaurants will be entitled to duty credit equivalent to 10% of the foreign exchange earned by them in the preceding financial year.

Imports allowed

3.6.4.5 Duty credit scrip may be used for import of any capital goods including spares, office equipment and professional equipment, office furniture and consumables; that are otherwise freely importable under ITC (HS) Classification of Export and Import items. The imports shall relate to any service sector business of the applicant.

Utilization of duty credit earned under the scheme shall not be permitted for payment of duty in case of import of vehicles, even if such vehicles are freely importable under ITC (HS).

In the case of hotels, golf resorts and stand-alone restaurants having catering facilities, the duty credit entitlement may also be used for the import of consumables including food items and alcoholic beverages.

Non Transferability

3.6.4.6 The entitlement and the goods imported shall be non-transferable.

However, transfer of duty credit scrips/goods imported under the scheme shall be allowed within the service providers of the Group Company as defined in chapter 9 and managed hotels with actual user condition.

Healthcare & Education

3.6.4.7 Deleted

Special provisions

3.6.4.8 Government reserves the right in public interest to specify from time to time the category or type of service exports which shall not be eligible for calculation of either eligibility or of entitlement.

Similarly, Government may from time to time also notify the goods, which shall not be allowed for import under the duty free entitlement certificate issued under the scheme.

Import under Lease financing

3.6.4.9 Utilization of duty free credit scrip earned under the scheme shall be permitted for payment of duty in case of import of capital goods under lease financing in terms of provision in Para 2.25 of this Policy.

3.7 Deleted

3.8 VISHESH KRISHI AND GRAM UDYOG YOJANA

(SPECIAL AGRICULTURE AND VILLAGE INDUSTRY SCHEME)

Objective

3.8.1 The objective of Vishesh Krishi and Gram Udyog Yojana (Erstwhile Vishesh Krishi Upaj Yojana) is to promote export of Fruits, Vegetables, Flowers, Minor Forest produce, Dairy, Poultry and their value added products, and Gram Udyog Products by incentivising exporters of such products.

Entitlement

3.8.2 Export of Fruits, Vegetables, Flowers, Minor Forest Produce, Dairy, Poultry and their value added products shall be entitled for duty credit scrip equivalent to 5% of the FOB value of exports. A detailed list of these agricultural products and the period of exports for which this entitlement is to be granted is given in Appendix 37A of the Handbook of Procedures (Vol. I).

Gram Udyog products as listed in Appendix 37A of the Handbook of Procedures (Vol. I) shall be entitled for duty credit scrip equivalent to 5% of the FOB value of exports in respect of the exports made on or after 1st April, 2006.

However, the duty credit scrip shall be granted only at a reduced rate of 3.5% of the FOB value of exports in such cases where the exporters has availed the benefits under Chapter 4 of this Policy for import of Agriculture Inputs (other than catalysts, consumables and packing materials) relating to export item under this scheme.

The scrip and the items imported against it shall be freely transferable.

3.8.2.1 Under the Scheme, exports of all eligible items (including the value added variants) are eligible for benefits as per Para 3.8.2 above provided they are specifically listed in Appendix 37A of the Handbook of Procedures (Vol. I). Items which are restricted or prohibited for export under Schedule-2 of the Export Policy in the ITC (HS) Classification of Export and Import items shall not be eligible for any benefits under Para 3.8.2.

3.8.2.2 Following exports shall not be taken into account for duty credit entitlement under the scheme:

- (a) Export of imported goods covered under Para-2.35 of the Foreign Trade Policy or exports made through trans-shipment.
- (b) Deemed Exports.
- (c) Exports made by SEZs units and EOUs units.

Imports allowed

3.8.3 The Duty Credit may be used for import of inputs or goods, which are otherwise freely importable under ITC (HS) Classifications of Export and Import Items.

Imports from a port other than the port of export shall be allowed under TRA facility as per the terms and conditions of the notification issued by Department of Revenue.

3.8.3.1 Items listed in Appendix 37A of the Handbook of Procedures (Vol. I) shall not be allowed to be imported under the scheme.

Cenvat/Drawback

3.8.4 Additional customs duty/excise duty paid in cash or through debit under Vishesh Krishi and Gram Udyog Yojana shall be adjusted as CENVAT Credit or Duty Drawback as per rules framed by the Department of Revenue.

Special Provision

3.8.5 Government reserves the right in public interest, to specify from time to time the export products, which shall not be eligible for calculation of entitlement.

3.9 FOCUS MARKET SCHEME**Objective**

3.9.1 The objective is to offset the high freight cost and other disabilities to select international markets with a view to enhance our export competitiveness to these countries.

Eligibility

3.9.2 Exports of all products to the notified countries shall be entitled for duty credit scrip equivalent to 2.5% of the FOB value of exports for each licensing year commencing from 1st April, 2006. The scrip and the items imported against it would be freely transferable.

3.9.2.1 Under the Scheme, export to all countries as given in Appendix 37C of the Handbook of Procedures (Vol. I) shall qualify for export benefits as per Para 3.9.2 above. Items which are restricted or prohibited for export under Schedule-2 of the Export Policy in the ITC (HS) Classification of Export and Import items shall not be eligible for any benefits under Para 3.9.2.

3.9.2.2 The following exports shall not be taken into account for calculation of export performance or for computation of entitlement under the scheme:

- a. Export of imported goods covered under Para 2.35 of the Foreign Trade Policy or exports made through trans-shipment.
- b. Export turnover of units operating under SEZ/EOU/EHTP/STPI/BPT

Schemes or supplies made to such units or products manufactured by them and exported through DTA units.

- c. Deemed Exports.
- d. Service Exports.
- e. Diamonds and other precious, semi-precious stones.
- f. Gold, silver, platinum and other precious metals in any form, including plain and studded Jewellery.
- g. Ores and Concentrates of all types and in all forms.
- h. Cereals, of all types.
- i. Sugar, of all types and in all forms.
- j. Crude/Petroleum Oil & Crude/Petroleum based Products covered under ITC HS codes 2709 to 2715, of all types and in all forms.

3.9.2.3 Exporters shall have the option to apply for benefit either under the Focus Market Scheme or under the Focus Product Scheme or under Vishesh Krishi and Gram Udyog Yojana in respect of the same exported product/s.

Imports allowed

3.9.3 The Duty Credit may be used for import of inputs or goods including capital goods, provided the same is freely importable under ITC (HS).

Imports from a port other than the port of export shall be allowed under TRA facility as per the terms and conditions of the notification issued by Department of Revenue.

Cenvat/Drawback

3.9.4 Additional customs duty/excise duty paid in cash or through debit under this scrip shall be adjusted as CENVAT Credit or Duty Drawback as per rules framed by the Department of Revenue.

Special Provisions

3.9.5 Government reserves the right in public interest, to specify from time to time the export products or exports to such countries, which shall not be eligible for calculation of entitlement.

3.10 FOCUS PRODUCTS SCHEME**Objective**

3.10.1 The objective is to incentivise export of such products which have high employment intensity in rural and semi urban areas so as to offset the inherent infrastructure inefficiencies and other associated costs involved in marketing of these products.

Eligibility

3.10.2 Exports of notified products to all countries shall be entitled for duty credit scrip equivalent to 2.5% of the FOB value of exports for each licensing year commencing from 1st April, 2006. However only 50% of the export turnover of such products shall be counted for benefits under the Scheme. The scrip and the items imported against it would be freely transferable.

3.10.2.1 Under the Scheme, export of all such products as given in Appendix 37D of the Handbook of Procedures (Vol. I) shall qualify for export benefits as per Para 3.10.2 above.

3.10.2.2 The following exports shall not be taken into account for calculation of export performance or for computation of entitlement under the scheme;

- a. Export of imported goods covered under Para 2.35 of the Foreign Trade Policy or exports made through transshipment.
- b. Export turnover of units operating under SEZ Scheme and 100% EOU Scheme or products manufactured by them and exported through DTA units.
- c. Deemed Exports.

3.10.2.3 Exporters shall have the option to apply for benefit either under the Focus Market Scheme or under the Focus Product Scheme or under Vishesh Krishi and Gram Udyog Yojana in respect of the same exported product/s.

Imports allowed

3.10.3 The Duty Credit may be used for import of inputs or goods including capital goods, provided the same is freely importable under ITC (HS).

Imports from a port other than the port of export shall be allowed under TRA facility as per the terms and conditions of the notification issued by Department of Revenue.

Cenvat/Drawback

3.10.4 Additional customs duty/excise duty paid in cash or through debit under this scrip shall be adjusted as CENVAT Credit or Duty Drawback as per rules framed by the Department of Revenue.

Special Provisions

3.10.5 Government reserves the right in public interest, to specify from time to time the export products or exports to such countries, which shall not be eligible for calculation of entitlement.

CHAPTER-4**DUTY EXEMPTION & REMISSION SCHEMES****Duty Exemption and Remission Schemes**

4.1 Duty exemption schemes enable duty free import of inputs required for export production. Duty Exemption Scheme consists of (a) Advance Authorisation Scheme

and (b) Duty Free Import Authorisation Scheme (DFIA). A Duty Remission Scheme enables post export replenishment/remission of duty on inputs used in the export product. Duty remission schemes consists of (a) DFRC (Duty Free Replenishment Certificate), (b) DEPB (Duty Entitlement Passbook Scheme) and (c) DBK (Duty Drawback Scheme).

Re-import of exported goods under Duty Exemption/Remission Scheme

4.1.1 Goods exported under Advance Authorisation/DFIA/DFRC/DEPB may be re-imported in the same or substantially the same form subject to such condition as may be specified by the Department of Revenue from time to time.

Value Addition

4.1.2 The value addition for the purposes of this chapter (Except for the Gems and Jewellery) shall be :—

$$V. A. = \frac{A-B}{B} \times 100, \text{ where}$$

V. A.	Value Addition
A	FOB value of the export realised/FOR value of supply received.
B	CIF value of the imported inputs covered by the authorisation, plus any other imported materials used on which the benefit of duty drawback is being claimed.

**ADVANCE AUTHORISATION SCHEME
(ERSTWHILE ADVANCE LICENCE SCHEME)****Advance Authorisation**

4.1.3 An Advance Authorisation is issued to allow duty free import of inputs, which are physically incorporated in the export product (making normal allowance for wastage). In addition, fuel, oil, energy, catalysts etc. which are consumed/utilised in the course of their use to obtain the export product, may also be allowed under the scheme. However, the Director General of Foreign Trade, by means of Public Notice, may in public interest exclude any product(s) from the purview of advance Authorisation.

Duty free import of mandatory spares upto 10% of the CIF value of the Authorisation which are required to be exported/supplied with the resultant product may also be allowed under Advance Authorisation.

Advance Authorisations are issued on the basis of the inputs and export items given under SION. However, they can also be issued on the basis of Ad hoc norms or self-declared norms as per para 4.7 of Handbook of

Procedures (Vol. I). Advance Authorisation can be issued either to a manufacturer exporter or merchant exporter tied to supporting manufacturer(s) :

- (i) for Physical exports (including exports to SEZ); and/or
- (ii) for Intermediate supplies; and/or
- (iii) to the main contractor for supply of goods to the categories mentioned in paragraph 8.2 (b), (c), (d), (e), (f), (g), (i) and (j) of the Policy;
- (iv) supply of stores on board of the foreign going vessel/aircraft subject to the condition that there is specific SION in respect of the item(s) supplied.

for import of inputs required in the manufacture of goods. In addition, in respect of supply of goods to specified projects mentioned in paragraph 8.2 (d), (e), (f), (g) and (j) of the Policy, an Advance Authorisation can also be availed by the sub-contractor of the main contractor to such project provided the name of the sub-contractor(s) appears in the main contract.

Such Authorisation can also be issued for supplies made to United Nations Organisations or under the Aid Programme of the United Nations or other multilateral agencies and paid for in free foreign exchange.

4.1.4 Advance Authorisation is issued for duty free import of inputs, as defined in paragraph 4.1.3 subject to actual user condition. Such Authorisations are exempted from payment of basic customs duty, additional customs duty, education cess, anti-dumping duty and safeguard duty, if any. However, the imports for supplies covered under paragraph 8.2 (i) & (j) will not be exempted from the payment of applicable anti-dumping and safeguard duty, if any.

4.1.5 Advance Authorisation and/or materials imported thereunder shall not be transferable even after completion of export obligation. However, the Authorisation holder will have the option to dispose off the product manufactured out of the duty free inputs once the export obligation is completed.

4.1.6 Advance Authorisation shall be issued with a positive value addition.

However, for physical exports for which payments are not received in freely convertible currency, the same shall be subject to value addition as specified in Appendix-11 of Handbook of Procedures (Vol. I). In case of supplies to SEZ Units, irrespective of the currency of realization, Advance Authorisation shall be issued with a positive value addition.

In case of Tea, the minimum value addition under advance Authorisation shall be 100 %.

In case of spices (covered by Chapter 9 of the ITC (HS) Classification of Export & Import Items, 2004—09), the

minimum value addition under advance Authorisation shall be 15 %.

4.1.7 Advance Authorisation shall be issued in accordance with the Policy and procedure in force on the date of issue of Authorisation.

The validity period of advance authorisation for import shall be as prescribed in the Handbook of Procedures (Vol. I).

4.1.8 The facility of Advance Authorisation shall be available where some or all of the inputs are supplied free of cost to the exporter.

In such cases, for calculation of value addition, the notional value of free of cost inputs along with value of other dutyfree inputs shall be taken into consideration. However, if all the inputs are supplied free of cost, the exporter shall also have the option to follow the provision prescribed in paragraph 4.2.7 of the Policy.

Export Obligation

4.1.9 The period for fulfilment of the export obligation under Advance Authorisation shall be as prescribed in the Handbook of Procedures (Vol. I).

Provision for BIFR units

4.1.9 A Any firm/company registered with BIFR or any firm/company acquiring a unit, which is under BIFR shall be allowed EOP extension as per the rehabilitation package prepared by the operating agency subject to subsequent approval of BIFR.

However, in cases where the rehabilitation package does not specify the EOP extension period, a time period upto 5 years reckoned from the date of issue of authorisation would be permitted on merits of the case for fulfilment of export obligation.

Similarly, SSI units shall also be entitled for similar facility as per the rehabilitation scheme of the concerned State Government. However, in cases where the State rehabilitation scheme does not specify the export obligation extension period, a time period upto 5 years reckoned from the date of issue of authorisation would be permitted on merits of the case for fulfilment of export obligation.

Export Obligation Period Extension, as mentioned above, shall be without the payment of composition free for cases where rehabilitation package has been announced/approved.

Advance Authorisation for Annual Requirement

4.1.10 Advance Authorisation can also be issued on the basis of annual requirement for physical exports, intermediate supplies and/or deemed exports.

One to Five Star Export House shall be entitled for the Advance Authorisation for annual requirement. All other categories of exporters having past export

performance (in the preceding two years) shall also be entitled for the Advance Authorisation for annual requirement.

In addition, a merchant exporter shall also be issued the Advance Authorisation for Annual Requirement provided they agree to the endorsement of the name(s) of the supporting manufacturer(s) on the relevant Authorisation.

The entitlement in terms of CIF value of imports under this scheme shall be upto 300% of FOB value of physical export and/or FOR value of deemed export in the preceding licensing year or Rs. 1 Crore, whichever is higher. Such Authorisation shall have value addition as specified in para 4.1.6 of the Foreign Trade Policy.

Advance Release Orders

4.1.11 An Advance Authorisation holder, holder of advance Authorisation for annual requirement, holder of Diamond Impreset Authorisation, holder of DFIA and holder of DFRC intending to source the inputs from indigenous sources/State Trading Enterprises/EOU/SEZ/EHTP/STP/BTP units in lieu of direct import has the option to source them against Advance Release Orders denominated in free foreign exchange/Indian rupees.

The transferee of a DFIA or a DFRC shall also be eligible for ARO facility. However, supplies may be obtained against the Authorisation from EOU/EHTP/BTP/STP/SEZ units, without conversion into ARO.

The validity period of ARO shall be as prescribed in the Handbook of Procedures (Vol. I)

Back-to-Back Inland Letter of Credit

4.1.12 An Advance Authorisation holder, holder of advance Authorisation for annual requirement, holder of DFIA, holder of Diamond Impreset Authorisation and holder of DFRC may, instead of applying for an Advance Release Order, avail of the facility of Back-to-Back Inland Letter of Credit in accordance with the procedure specified in Handbook of Procedures (Vol. I).

Prohibited Items

4.1.13 Prohibited items of imports mentioned in ITC (HS) shall not be imported under the advance Authorisation/DFIA/DFRC. Further the items reserved for imports by State Trading Enterprises cannot be imported against advance Authorisation/DFIA/DFRC. However those items can be procured from State Trading Enterprises against ARO or Invalidation letter issued to the holder of advance Authorisation/DFIA/DFRC.

The State Trading Enterprises are also allowed to sell the goods on High Sea Sale basis to the holders of Advance Authorisation/DFIA/DFRC.

In addition, the State Trading Enterprises are permitted to issue "No Objection Certificate (NOC)" if they

so desire, for import by holder of advance Authorisation. DFIA holders would also be eligible to import such items based on No Objection Certificate (NOC) from the SITs for only such products as notified by DGFT. However, the Authorisation holder would be required to file Quarterly Returns of the imports effected against such "No Objection Certificate" to the concerned State Trading Enterprises (STEs) and STEs, in turn, would submit Half-yearly import figures of such imports to the concerned administrative Department for monitoring with a copy endorsed to the Department of Commerce.

Similarly prohibited items of exports mentioned in the ITC (HS) shall not be exported under the Authorisation issued under the Advance Authorisation /DFIA/DFRC Scheme. Further, export of restricted items shall be subject to all conditionalities or requirements of export Authorisation or permission as may be required under Schedule II of ITC (HS).

Admissibility of Drawback

4.1.14. In the case of an Advance Authorisation, the drawback shall be available in respect of any of the duty paid materials, whether imported or indigenous, used in the goods exported as per drawback rate fixed by Ministry of Finance (Directorate of Drawback). The Drawback shall however be restricted to the duty paid materials as mentioned in the application.

DUTY FREE REPLENISHMENT CERTIFICATE

Duty Free Replenishment Certificate (DFRC)

4.2. DFRC is issued to a merchant exporter or manufacturer exporter for the import of inputs used in the manufacture of goods without payment of basic customs duty.

However, such inputs shall be subject to the payment of additional customs duty equal to the excise duty at the time of import.

4.2.1. DFRC shall be issued on minimum value addition of 25 % except for items in gems and jewellery sector for which value addition as given in paragraph 4A. 2.1. of the Handbook of Procedures (Vol. I) and items for which higher value addition is prescribed under Advance Authorisation Scheme shall be applicable.

4.2.2. DFRC may be issued for physical exports against freely convertible currency/physical exports to SEZ, whether against freely convertible currency or non-convertible currency/ supplies effected under paragraph 8.2. of the Policy (except for supplies made to DFRC holder).

DFRC may also be issued in respect of physical exports (other than supplies to SEZ) for which payments are received in non-convertible currency. Such exports shall, however, be subject to value addition and conditions as specified in Appendix-I I of Handbook of Procedure (Vol. I).

4.2.3. DFRC shall be issued only in respect of products covered under the Standard Input Output Norms as notified by DGFT.

However, in respect of Standard Input Output Norms which are subject to "actual user" condition or where the export proceeds have not been realised at the time of filing application or for import of fuel under the general norms, DFRC shall be issued with actual user condition for these inputs.

However for fuel, the import entitlement may be transferred only to the companies which have been granted Authorisation to market fuel by the Ministry of Petroleum & Natural Gas.

In cases where Standard Input Output Norms allow import of Acetic Anhydride, ephedrine and Pseudo Ephedrine, DFRC shall be issued provided these items are specifically deleted from the list of import items.

DFRC will not be issued against SION which prescribe a prior import condition for inputs.

Provisions of paragraph 4.1.13 of FTP shall be applicable for the DFRC holder.

4.2.4. DFRC shall be issued for import of inputs as per SION as indicated in the shipping bills. The validity of such Authorisations will be governed by the provision stipulated in the Handbook of Procedures (Vol I) DFRC and or the material(s) imported against it shall be freely transferable. However, DFRC with actual user condition or the material(s) imported against it shall not be transferable.

4.2.5. The export products, which are eligible for modified VAT shall be eligible for CENVAT credit/Service tax credit.

However, non excisable, non-dutiable or non CENVAT products, shall be eligible for drawback at the time of exports in lieu of additional customs duty to be paid at the time of imports under the Scheme.

4.2.6. The exporter shall be entitled for drawback benefits in respect of any of the duty paid materials, whether imported or indigenous, used in the export product as per the drawback rate fixed by Directorate of Drawback (Ministry of Finance).

The drawback shall however be restricted to the duty paid materials not covered under SION.

Jobbing, repairing etc. for re-export

4.2.7. Import of goods, including those mentioned as restricted in ITC (HS) but excluding prohibited items, supplied free of cost may be permitted for the purpose of jobbing without a authorisation/certificate/permission as per the terms of notification issued by Department of Revenue from time to time.

Similarly, import of goods for carrying out repairs, reconditioning, re-engineering, testing etc. shall be allowed as per the terms and conditions of the Customs notification even though the goods may be restricted for import under the Foreign Trade Policy/ITC (HS) Classification of Imports and Exports Book.

The above provisions shall, however, be subject to all conditionality or requirement of Authorisation or permission, as may be required, under Schedule II of ITC (HS).

Termination of the Scheme

4.2.8. DFRC scheme shall be available for exports effected upto 30-4-2006.

DUTY ENTITLEMENT PASSBOOK (DEPB) SCHEME

Duty Entitlement Passbook Scheme (DEPB)

4.3. The objective of DEPB is to neutralise the incidence of Customs duty on the import content of the export product. The neutralisation shall be provided by way of grant of duty credit against the export product.

The DEPB scheme will continue to be operative until it is replaced by a new scheme which will be drawn up in consultation with exporters.

4.3.1. Under the DEPB scheme, an exporter may apply for credit, as a specified percentage of FOB value of exports, made in freely convertible currency or the payment made from the Foreign Currency Account of the SEZ unit in case of supply by DTA to SEZ unit.

The credit shall be available against such export products and at such rates as may be specified by the Director General of Foreign Trade by way of public notice issued in this behalf, for import raw materials, intermediates components parts, packaging material etc. The credit may also be utilized for payment of Customs duty on any items which is freely importable.

4.3.2. The holder of DEPB shall have the option to pay additional customs duty, if any, in cash as well.

Validity

4.3.3 The validity period of DEPB for import shall be as prescribed in the Handbook of Procedures (Vol. I).

Transferability

4.3.4. The DEPB and/or the items imported against it are freely transferable. The transfer of DEPB shall however be for import at the port specified in the DEPB, which shall be the port from where exports have been made.

Imports from a port other than the port of export shall be allowed under TRA facility as per the terms and conditions of the notification issued by Department of Revenue.

Applicability of Drawback

4.3.5. Normally, the exports made under the DEPB Scheme shall not be entitled for drawback. However, the additional customs duty/excise duty paid in cash or through debit under DEPB shall be adjusted as CENVAT Credit or Duty Drawback as per rules framed by the Department of Revenue.

DUTY FREE IMPORT AUTHORISATION**Scheme**

4.4.1. A Duty Free Import Authorisation is issued to allow duty free import of inputs which are used in the manufacture of the export product (making normal allowance for wastage), and fuel, energy catalyst etc. which are consumed or utilised in the course their use to obtain the export product. However, the Director General of Foreign Trade, by means of Public Notice, may in public interest, exclude any product(s) from the purview of this scheme. This scheme will come into force from 1st May, 2006.

Entitlement

4.4.2. The Authorisation shall be issued on the basis of inputs and export items given under Standard Input and Output Norms (SION). The import entitlement shall be limited to the quantity mentioned in SION.

Duty Free import of mandatory spares upto 10 % of the CIF value of Authorisation which are required to be exported/supplied with the resultant product may also be allowed under the scheme.

Such Authorisation can be issued either to a manufacturer exporter or merchant exporter tied to supporting manufacturers(s):

- (i) for Physical exports (including exports to SEZ); and/or
- (ii) for Intermediate supplies; and/or
- (iii) to the main contractor for supply of goods to the categories mentioned in paragraph 8.2 (b), (c), (d), (e), (f), (g), (i) and (j) of the Policy;

for import of inputs required in the manufacture of goods. In addition, in respect of supply of goods to specified projects mention in paragraph 8.2 (d), (e), (f), (g) and (j) of the Policy, a DFIA can also be availed by the sub-contractor of the main contractor to such project provided the name of the sub-contractor(s) appears in the main contract.

Such Authorisation can also be issued for supplies made to United Nation Organisations or under the Aid Programme of the United Nations or other multilateral agencies and paid for in free foreign exchange.

A manufacturer exporter or a merchant exporter tied up with the supporting manufacturer can apply for the Authorisation under the Scheme. Before affecting exports under scheme, an applicant is required to file an application to the Regional Authority.

Such Authorisation shall be initially issued with actual user condition and shall be exempted from payment of basic custom duty, additional customs duty, education cess, anti-dumping duty and safeguard duty, if any.

Import items

4.4.3 Prohibited items of imports mentioned in ITC (HS) shall not be imported under the Authorisation issued under the Scheme.

Duty Free procurement from domestic market will be available as in case of Advance Authorisation Scheme against ARO/invalidation letter/back to back Inland letter of credit etc.

Provisions of paragraph 4.1.13 of FTP shall be applicable for the DFIA holder.

Value Addition

4.4.4 A minimum 20 % value addition shall be required for issuance of such Authorisation except for items in gems and jewellery sector for which value addition as given in paragraph 4A.2.1 of the Handbook of Procedure (Vol. 1) and items for which higher value addition is prescribed under Advance Authorisation Scheme shall be applicable.

Export Obligation

4.4.5. Procedure related to fulfilment of Export Obligation under the scheme and the time period allowed to fulfil it has been laid down in Chapter 4 of Handbook of procedure, Vol. I.

Transferability

4.4.6 Once export obligation has been fulfilled, request for transferability of the Authorisation or the inputs imported against it may be made before the Regional Authority. Once, transferability is endorsed the authorisation holder will be at liberty to transfer the duty free inputs, other than fuel and any other items(s) notified by DGFT for this purpose.

However, in respect of Standard Input Output norms, which are subject to "actual user" condition or for import of fuel under the general norms or where Standard Input Output Norms allow import of Acetic Anhydride, Ephedrine and Pseudo Ephedrine, DFIA shall be issued with actual user condition for these inputs and no transferability shall be allowed for these inputs even after fulfilment of the export obligation. Transfer of items that are restricted for imports or the DFIA for such items shall be

allowed under the DFIA scheme only against a specific import licence for that item.

However, for fuel the import entitlement may be transferred only to the companies which have been granted Authorisation to market fuel by the Ministry of Petroleum and Natural Gas.

CENVAT Facility

4.4.7 No CENVAT credit facility shall be available for inputs either imported or procured indigenously against the Authorisation.

Drawback Facility

4.4.8 The draw back shall be available in respect of any of the duty paid material, whether imported or indigenous, used in the goods exported, as per the drawback rate fixed by Ministry of Finance. The drawback shall, however, be restricted to the duty paid materials mentioned in the application.

GEMS AND JEWELLERY

Scheme for Gems and Jewellery

4A. Exporters of Gems and Jewellery can import/procure duty free inputs required for manufacture of gems and jewellery items.

Replenishment Authorisation

4A. 1. Exporters of Gems and Jewellery are eligible to import their inputs duty free by obtaining Replenishment (REP) Authorisations from the licensing authorities in accordance with the procedure specified in this regard in the Handbook of Procedures of Procedure (Vol.1).

4A 1.1. The exporters of gems and jewellery products listed in Appendix-12A of the Handbook of procedures (Vol.1) shall be eligible for grant of replenishment Authorisations at the rate and for the items mentioned in the said Appendix to import and replenish their input.

Replenishment authorisation may also be issued for import of consumables as per the details given in paragraph 4A. 28 of Handbook of Procedures (Vol.1).

Export of Cut & Polished Diamonds for Certification/Grading

4.A.2 Gem and Jewellery exporters may be permitted to send cut and polished diamonds each weighing 0.25 of a carat and above for certification/grading to Indian Diamond Institute, Surat, Gujarat. In addition, Gem and Jewellery exporters with a track record of at least three years and having an annual average turnover of Rs. 5 crores and above during the preceding three licensing years or the authorized offices/agencies in India of

Gemological Institute of America (GIA), The Robert Mouawad Campus International Gemological Institute (IGI), and European Gemological laboratory (EGL) in USA, Hoge Road Voor Diamond, Antwerp, (HRD), World Diamond Centre of Diamonds High Council, Antwerp, Belgium, Central Gem Laboratory, Miyagi Building, 5-15-14 Ueno Taito-Ku, Tokyo, Japan American Gem Society laboratories (AGS Laboratories, 8917 West Sahara Avenue, Las Vegas, Nevada 89117 and Diamond Trading company, Maidenhead, U.K. may also be permitted to export cut and polished diamonds each weighing 0.25 of a carat and above to the said laboratories/agencies for the purpose of certification/grading reports by them with a condition that the same should be re-imported with the certificate/grading reports issued by them without any import duty at the time of re-import.

4A.2.1. At the time of export of cut and polished diamonds for certification/grading, exporter should give an undertaking to the customs that the cut and polished diamonds will be re-imported within three months of exports for certification/grading.

The export invoice should clearly indicate the estimated value, height, circumference, weight of each diamond to be exported for certification/grading so that at the time of their import, the above specification could be compared with the original ones to establish their identity. Subsequently these cut and polished diamonds would be exported as per the provisions of the Policy.

Schemes for Gold/Silver/Platinum Jewellery

4.A.3. Exporters of Gold/Silver/Platinum Jewellery and articles thereof may import their essential inputs such as gold, silver, platinum, mountings, findings, rough gems, precious and semi-precious stones, synthetic stones and unprocessed pearls etc. in accordance with the procedure specified in this behalf.

Nominated Agencies

4A.4 Exporters (excepting units operating under EOU/SEZ schemes) availing the schemes of gold/Silver/platinum jewellery and articles thereof may obtain gold/silver/platinum from the nominated agencies. The nominated agencies are MMTC Ltd, Handicraft and Handloom Export Corporation (HHEC), State Trading Corporation (STC), the Project and Equipment Corporation of India Ltd. (PEC), Five Star Export House under Paragraph 3.5.2 of the Policy and any other agency authorised by Reserve Bank of India (RBI).

A Bank authorised by RBI is allowed export of gold scrap for refining and import in the form of standard gold bars. The detailed procedure for the import of gold will be as per the guidelines notified by RBI separately.

Items of Export

4A.5 The following items, if exported, would be eligible for the facilities under the schemes stipulated in paragraph 4A of the Foreign Trade Policy:

- (a) Gold jewellery, including partly processed jewellery and any articles including medallions and coins (excluding the coins of the nature of legal tender), whether plain or studded, containing gold of 8 carats and above;
- (b) Silver jewellery including partly processed jewellery, silverware, silver strips and any articles including medallions and coins (excluding the coins of the nature of legal tender and any engineering goods) containing more than 50% silver by weight;
- (c) Platinum jewellery including partly processed jewellery and any articles including medallions and coins (excluding the coins of nature of legal tender and any engineering goods) containing more than 50% platinum by weight.

Value Addition

4A.6 The value addition for the purpose of gems and jewellery sector shall be as per paragraph 4A.2.1 of Handbook of Procedures (Vol. 1).

$$V.A. = \frac{A-B}{B} \times 100, \text{ where}$$

V.A. — Value Addition,

A — FOB value of the export realised/FOR value of supply received.

B — The Value of inputs such as gold/silver/platinum content in the export product plus the admissible wastage along with the value of the other items such as gemstone etc. 'Value' for this purpose includes both imported as well as domestically procured inputs. Wherever gold has been obtained on loan basis, the value shall also include interest paid in free foreign exchange to the foreign supplier.

Wastage Norms

4A.7 Under the schemes for gold/silver/platinum jewellery, the wastage or manufacturing loss shall be admissible as per paragraph 4A.2 of the Handbook of Procedure (Vol. 1).

Export Against Supply by Foreign Buyer

4A.8 Where export orders are placed on the nominated agencies/status holder/exporters of three years standing having an annual average turnover of Rs. Five

Crore during the proceeding three licensing years, the foreign buyer may supply to the nominated agencies/status holder/exporter, in advance and free of charge, gold/silver/platinum, alloys, findings and mountings of gold/silver/platinum for manufacture and export.

The exports may be made by the nominated agencies directly or through their associates or by the status holder/exporter/ as the case may be. The import and export of findings shall be on net to net basis. The foreign buyer may also supply to the nominated agencies/status holder/exporter in advance and free of charge plain, semi finished gold/silver/platinum jewellery including findings/mountings/components for repairs/re-make and export subject minimum value addition of 10%. However, if the so imported semi finished gold/silver/platinum jewellery is exported as studded jewellery, value addition of 15% shall be achieved. In such cases of export wastage of 2% may be permitted.

The procedures in this regard shall be as prescribed in the Handbook of Procedures (Vol. 1).

Export Against Supply by Nominated Agencies

4A.9 The exporter may obtain the gold/silver/platinum as an input for export products from nominated agencies in advance or as replenishment after exports in accordance with the procedure specified in this behalf.

Export Against Advance Authorisation

4A.10 An Advance Authorisation may be granted for the duty free import of:

- (a) Gold of fineness not less than 0.995 and mountings, sockets, frames and findings of 8 carats and above;
- (b) Silver of fineness not less than 0.995 and mountings, sockets, frames and findings containing more than 50% silver by weight;
- (c) Platinum of fineness not less than 0.900 and mountings, sockets, frames and findings containing more than 50% platinum by weight.

4A.11 Such authorisations shall carry an export obligation which will be required to be fulfilled in accordance with the procedure specified in paragraph 4A of the Handbook of Procedures (Vol. 1).

The Advance Authorisation holder may obtain gold/silver/platinum from the nominated agencies in lieu of direct import in accordance with the procedure specified in this behalf.

Gem Replenishment Authorisation

4A.12 Gem Replenishment (Gem & Jewellery REP) Authorisation may be issued under the schemes for export of gold/silver/platinum jewellery and articles thereof as given in paragraph 4A.8, 4A.9 and 4A.10 of the Policy. In the case of plain gold/silver/platinum jewellery and articles,

the value of such Authorisations shall be determined with the reference to the realisation in excess of the prescribed minimum value addition.

In the case of studded gold/silver/platinum jewellery and articles thereof, the value of Gem Replenishment Authorisation shall be determined by taking into account the value of studdings used in items exported, after accounting for the value addition on gold/silver/platinum including admissible wastage.

Such Gem REP Authorisations shall be freely transferable.

Gem REP Rate and Item

4A.13 The scale of replenishment and the item of import will be as prescribed in Appendix 12B of Handbook of Procedures (Vol. 1).

Diamond Imprest Authorisation

4A.14 Diamond Imprest Authorisation for import of cut and polished diamonds including semi processed diamonds, half cut diamonds, broken in any form, for mixing with cut and polished diamond or for export as it is, may be issued for export of cut and polished diamonds.

Such Authorisations shall carry an export obligation, which has to be discharged in accordance with the procedure specified in this behalf.

Eligibility

4A.14.1 An exporter of cut and polished diamonds who is status holder may be issued an Authorisation for import of cut and polished diamonds upto 5% of the export performance of the preceding year of cut and polished diamonds.

Export Obligation

4A.14.2 The export obligation under the scheme will be governed by the provisions of paragraph 4A of Chapter 4 of the Handbook of Procedures (Vol. 1).

Export Promotion Tours/Export of Branded Jewellery

4A.15 The nominated agencies and their associates, with the approval of Department of Commerce, and others with the approval of Gem and Jewellery Export Promotion Council (GJEPC), may export gold/silver/platinum jewellery and articles thereof for holding/participating in exhibitions abroad.

Personal carriage of gold/silver/platinum jewellery, precious, semi-precious stones, beads and articles and export of branded jewellery is also permitted. These exports shall be subject to the conditions as given in the Handbook of Procedures (Vol. 1).

Personal Carriage of Export/Import Parcels

4A.16 Personal carriage of gems and jewellery export parcels by foreign bound passengers and personal

carriage of gems and jewellery import parcels by an Indian importer/foreign national may be permitted as per the conditions given in Handbook of Procedures (Vol. 1).

Export by Post

4A.17 In case of exports through Foreign Post Office which may include export via Speed Post through Foreign Post Office, the value of the jewellery parcels shall not exceed US\$50000 and 20 kg. by weight. The detailed procedure is laid down in Chapter 4 of the Handbook of Procedures (Vol. 1).

Private/Public Bonded Warehouse

4A.18 Private/Public Bonded Warehouses may be set up in SEZ/DTA for import and re-export of cut and Polished diamonds, cut and polished coloured gemstones, uncut and unset precious and semi-precious stones. Import and re-export of cut and polished diamonds and cut and polished coloured gemstones will be subject to achievement of minimum value addition of 5%.

Diamond and Jewellery Dollar Accounts

4A.19 Firms and companies dealing in the purchase/sale of rough or cut and polished diamonds/precious metal jewellery plain, minakari and/or studded with/without diamond and/or other stones with a track record of at least 3 years in import or export of diamonds/coloured gemstones/diamond and coloured gemstones studded jewellery/plain gold jewellery and having an average annual turnover of Rs. 5 crore or above during preceding three licensing years may also carry out their business through designated Diamond Dollar Accounts.

The Diamond Dollar Account Scheme shall operate under the current licensing scheme of this chapter. This scheme shall be optional and those importers/exporters who wish to continue to use Rupee Accounts shall be allowed to do so under the existing policies.

Dollars in such accounts available from bank finance and/or export proceeds shall be used only for:

- (i) Import/purchase of rough diamonds from overseas/local sources.
- (ii) Purchase of cut and polished diamonds, coloured gemstones and plain gold jewellery from local sources.
- (iii) Import/purchase of gold from overseas/nominated agencies and repayment of dollar loans from the bank; and
- (iv) Transfer to the Rupee Account of the exporter. Details of this Diamond Dollar Accounts Scheme (DDAS) are given in the Handbook of Procedures (Vol. 1). The procedure outlined in the Handbook of Procedures (Vol. 1) shall also apply to diamond studded jewellery.

A non-DDA holder is also permitted to supply cut and polished diamonds to DDA holder, receive payment in dollars and convert same into rupees within the period of 7 days and cut and polished diamonds and coloured gemstones so supplied by non-DDA holder will also be counted towards the discharge of his export obligation and/or entitle him to replenishment Authorisation as the case may be.

Export of cut & polished precious and semi-precious stones for treatment and re-import

4A.20.1 Gems & Jewellery exporters shall be allowed to export cut and polished precious and semi-precious stones for the treatment and re-import as customs rules and regulations.

Import of precious metal scrap/used jewellery for melting and re-export of jewellery.

4A.21 Import of precious metal scrap/used jewellery shall be allowed for melting, refining and re-export of jewellery as per the procedure laid down in the Handbook of Procedures, Vol. I. However, such import shall not be allowed through hand baggage.

Re-import of rejected jewellery

4A.22 Gems & Jewellery exporters shall be allowed to re-import the rejected precious metal jewellery as per the procedure laid down in para 4A.32 and 4A.32. I of Handbook of Procedures, Vol. I.

Export of Jewellery on consignment basis

4A.23 Gems & Jewellery exporters shall be allowed to export jewellery on consignment basis as per the procedure given in Chapter 4 of the Handbook of Procedures, Vol. I and as per the Customs rules and regulations in this behalf.

CHAPTER-5

EXPORT PROMOTION CAPITAL GOODS SCHEME

EPCG Scheme

5.1 The scheme allows import of capital goods for pre production, production and post production (including CKD/SKD thereof as well as computer software systems) at 5% Customs duty subject to an export obligation equivalent to 8 times of duty saved on capital goods imported under EPCG scheme to be fulfilled over a period of 8 years reckoned from the date of issuance of Authorisation.

In the case of agro units, import of capital goods at 5% Customs duty shall be allowed subject to a fulfilment of an export obligation equivalent to 6 times the duty saved (on capital goods imported under the Scheme) over a period of 12 years from the date of issue of Authorisation.

However for SSI units, import of capital goods at 5% Customs duty shall be allowed subject to a fulfilment of an

export obligation equivalent to 6 times the duty saved (on capital goods imported under the Scheme) over a period of 8 years from the date of issue of Authorisation provided the landed CIF value of such imported Capital Goods under the Scheme does not exceed Rs. Twenty Five Lakhs and the total investment in plant and machinery after such imports does not exceed the SSI limit.

However, in respect of EPCG Authorisations with a duty saved of Rs.100 crore or more, the same export obligation, as the case may be shall be required to be fulfilled over a period of 12 years.

In case CVD is paid in cash on imports under EPCG, the incidence of CVD would not be taken for computation of net duty saved provided the same is not Cenvated.

The capital goods shall include spares (including refurbished/reconditioned spares), tools, jigs, fixtures, dies and moulds. EPCG Authorisation may also be issued for import of components of such capital goods required for assembly or manufacturer of capital goods by the Authorisation holder.

Second hand capital goods without any restriction on age may also be imported under the EPCG scheme.

However, import of motor cars, sports utility vehicles/all purpose vehicles shall be allowed only to hotel, travel agents, tour operators or tour transport operators and companies owing/operating golf resorts whose total foreign exchange earning from the hotel, travel & tourism and golf tourism sectors in the current and preceding three licensing year is Rs. 1.5 crores or more. The 'duty saved' amount on all EPCG Authorisations issued in a licensing year for import of motor cars, sports utility vehicles/all purpose vehicles shall not exceed 50% of the average foreign exchange earnings from the hotel, travel & tourism and golf tourism sectors in the preceding three licensing years. However, the parts of motor cars, sports utility vehicles all purpose vehicles such as chassis etc. cannot be imported under the EPCG Scheme.

Import of Restricted items of imports mentioned under ITC (HS) shall only be allowed to be imported under the Scheme after approval from the Import Licensing Committee.

5.1A Spares (including refurbished/reconditioned spares), tools, spare refractories, catalyst and consumable for the existing plant and machinery imported/to be imported under the Scheme shall also be allowed subject to an export obligation equivalent to 8 times of duty saved to be fulfilled over a period of 8 years reckoned from the date of issuance of Authorisation.

EPCG for Projects

5.1B An EPCG Authorisation can also be issued for import of capital goods under the Scheme for Projects Imports notified by the Central Board of Excise and

Customs under S.No. 441 of Customs Exemption Notification No. 21/2002 dated 1-3-2002 wherein the basic customs duty on imports is 10% with a CVD of 16%.

The export obligation for such EPCG Authorisations would be eight times the duty saved. The duty saved would be the difference between the effective duty under the aforesaid Customs Notification and the concessional duty under the EPCG Scheme.

EPCG for Retail Sector

5.1C To create modern infrastructure in the retail sector, concessional duty benefits under EPCG scheme shall be extended for import of capital goods required by retailers having minimum area of 1000 sq. meters. The retailer shall fulfil the export obligation i.e. 8 times the duty saved in 8 years.

Eligibility

5.2 The scheme covers manufacturer exporters with or without supporting manufacturer(s)/vendor(s), merchant exporters tied to supporting manufacturer(s) and service providers.

Conditions for Import of Capital Goods

5.3 Import of capital goods shall be subject to Actual User condition till the export obligation is completed.

Export Obligation

5.4 The following conditions shall apply to the fulfilment of the export obligation:—

- (i) The export obligation shall be fulfilled by the export of goods capable of being manufactured or produced by the use of the capital goods imported under the scheme.

The export obligation may also be fulfilled by the export of same goods, for which EPCG Authorisation has been obtained, manufactured or produced in different manufacturing units of the Authorisation holder/specified supporting manufacturer(s).

When Capital Goods are imported for pre/post-production or license is taken for import of spares, the license holder shall fulfil the export obligation by export of products manufactured from the plant/project to which the pre/post-production capital goods/spares are related.

The export obligation under the scheme shall be, over and above, the average level of exports achieved by him in the preceding three licensing years for same and similar products within the overall export obligation period including extended period, if any except for categories mentioned in Handbook (Vol. I).

Alternatively, export obligation may also be fulfilled by exports of other good(s) manufactured or service(s) provided by the same firm/company or group company/managed hotel which has the EPCG Authorisation.

However, in such cases, the additional export obligation imposed under EPCG scheme shall be over and above the average exports achieved by the unit/company/group company/managed hotel in preceding three years for both the original and the substitute product(s)/service(s) even in cases where the average is exempt for the substitute product(s)/service(s) as given in para 5.7.6 of the Handbook (Vol. I).

The incremental exports to be fulfilled by the Authorisation holder for fulfilling the remaining export obligation can include any combination of exports of the original product/service and the substitute product(s)/service(s). The exporter of goods can opt to get the export obligation refixed for the export of services and vice versa.

The Authorisation holder can also opt for the refixation of the balance export obligation based on 8 times of the duty saved amount for the CIF value in proportion to the balance Export obligation under the scheme. The guidelines for the re-fixation of export obligation is given in para 5.19 of the Handbook (Vol. I).

The aforesaid facilities shall only be available to manufacturer exporters/service provider on all the Authorisations where export obligation period including extended export obligation period is valid on the date of application. In this regard, exports made only on or after submission of application for alternate item and/or re-fixation of the export obligation based on duty saved amount will be taken into account for fulfilment of export obligation.

- (ii) The export obligation under the scheme shall be, in addition to any other export obligation undertaken by the importer, except the export obligation for the same product under Advance Authorisation, DFRC, DEPB or Drawback Scheme.
- (iii) The export obligation can also be fulfilled by the supply of ITA-1 items to the DTA provided the realization is in free foreign exchange.
- (iv) Exports shall be physical exports. However, deemed exports as specified in paragraph 8.2

(a), (b), (d), (f), (g) & (j) of Policy shall also be counted towards fulfilment of export obligation along with the usual benefits available under paragraph 8.3 of the Policy.

Royalty payments received in freely convertible currency and foreign exchange received for R & D services shall also be counted for discharge under the EPCG scheme. Payment received in rupee terms for the port handling services, in terms of Chapter 9 of the Foreign Trade Policy shall also be counted for export obligation discharge under the Scheme.

Payments received against 'Counter Sales' in free foreign exchange through banking channels as per the RBI guidelines shall be counted for fulfillment of export obligation under Para 5.1.C.

Provision for BIFR units

5.5.1 Any firm/company registered with BIFR or any firm/company acquiring a unit, which is under BIFR shall be allowed EO extension as per the rehabilitation package prepared by the operating agency subjected to subsequent approval of BIFR.

However, in cases where the rehabilitation package does not specify the EO extension period, a time period up to 12 years reckoned from the date of issue of Authorisation would be permitted on merits of the case for fulfillment of export obligation.

Similarly, small-scale SSI units shall also be entitled for similar facility as per the rehabilitation scheme of the concerned State Government. However, in cases where the State rehabilitation scheme does not specify the export obligation extension period, a time period up to 12 years reckoned from the date of issue of Authorisation would be permitted on merits of the case for fulfillment of export obligation.

EPCG for agro units

5.5.2 In the case of EPCG Authorisations issued to agro units in the agri export zones, a period of 12 years reckoned from the date of issue of the Authorisation would be permitted for the fulfillment of export obligation.

The agro units in the agri export zones would also have the facility of moving the capital good(s) imported under the EPCG within the agri export zone.

An LUT/Bond or a 15% BG (as the case may be) may be given for EPCG Authorisation granted to units in the Agri Export Zones provided the EPCG Authorisation is taken for export of the primary agricultural product (s) notified in Appendix 8 or their value added variants.

Indigenous Sourcing of Capital Goods and benefits to Domestic Supplier

5.6 A person holding an EPCG Authorisation may source the capital goods from a domestic manufacturer instead of importing them. The domestic manufacturer supplying capital goods to EPCG Authorisation holders shall be eligible for deemed export benefit under paragraph 8.3 of the Policy.

Benefits to Domestic Supplier

5.7 In the event of a firm contract between the EPCG Authorisation holder and domestic manufacturer for such sourcing, the domestic manufacturer may apply for the issuance of Advance Authorisation for the import of inputs including components required for the manufacturer of said capital goods.

The domestic manufacturer may also replenish the inputs including components after supply of capital goods to the EPCG Authorisation holders.

Fixation of Export Obligation

5.7A In case of direct imports, the export obligation relating to the EPCG Authorisation shall be reckoned with reference to the duty saved value on the CIF value of capital goods (including spares, jigs, fixtures, dies and moulds) actually imported. In case of domestic sourcing, the export obligation relating to EPCG shall be reckoned with reference to the notional Customs Duties saved on the FOR of capital goods (including spares, jigs, fixtures, dies and moulds).

5.8 Service provider in Agri export zone shall have the facility to move or shift the capital goods within the zone provided he maintains accurate record of such movements. However, such equipments shall not be sold or leased by the Authorisation holder.

Maintenance of Average exports under EPCG

5.9 As per the provisions of para 5.4 (i), the EPCG Authorisation holder would have to maintain the average level of exports equivalent to the average of the exports in the preceding three licencing years for the same and similar products except for exempted categories given in Handbook (Vol. 1) during the entire period of export obligation.

Notwithstanding the above, the Authorisation holder shall maintain the average exports in any particular year(s) provided the same is offset by excess exports to fulfil the average in other year(s).

Technological Upgradation of existing EPCG machinery

5.10 EPCG Authorisation holders can opt for Technological Upgradation of the existing capital goods imported under the EPCG Authorisation.

The conditions governing the Technological Upgradation of the existing capital goods are as under :

- (i) The minimum time period for applying for Technological Upgradation of the existing capital goods imported under EPCG is 5 years from the date of issuance of the Authorisation.
- (ii) The minimum exports made under the old capital goods must be 40% of the total export obligation imposed on the first EPCG Authorisation.
- (iii) The export obligation would be refixed such that the total export obligation mandated for both the capital goods would be the sum total of 6 times the duty saved on both the capital goods.
- (iv) The procedure governing the replacement of capital goods is given in para 5.20 of the Handbook (Vol. 1).
- (v) The facility for technological upgradation shall be available only once and the minimum imports to be made shall be at least 10% of the existing investment in plant and machinery by the applicant firm.

Incentives for Fast Track Companies

5.11 To incentivise fast track companies with a view to accelerate exports under the Scheme, in cases where the Authorisation holder has fulfilled 75% or more of the export obligation under the Scheme (including average level of exports) in half or less than half the original export obligation period specified in the Authorisation, the remaining export obligation shall be condoned and the Authorisation redeemed by the licensing authority concerned.

However no benefits under Para 5.12 of Handbook (Vol. I) shall be available in such cases.

CHAPTER 6

EXPORT ORIENTED UNITS (EOUs), ELECTRONICS HARDWARE TECHNOLOGY PARKS (EHTPs), SOFTWARE TECHNOLOGY PARKS (STPs) AND BIO-TECHNOLOGY PARKS (BTPs)

Eligibility

6.1 Units undertaking to export their entire production of goods and services (except permissible sales in the DTA), may be set up under the Export Oriented Unit (EOU) Scheme, Electronic Hardware Technology Park (EHTP) Scheme, Software Technology Park (STP) Scheme or Bio-Technology Park (BTP) scheme for manufacture of goods, including repair, remaking, reconditioning, re-engineering and rendering of services. Trading units, however, are not covered under these schemes.

Export and Import of Goods

6.2(a) An EOU/EHTP/STP/BTP unit may export all kinds of goods and services except items that are prohibited in the ITC (HS). Export of Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies (SCOMET) shall be subject to fulfillment of the conditions indicated in the ITC (HS).

Procurement and supply of export promotion materials like brochure/literature, pamphlets, hoardings, catalogues, posters etc. up to a maximum value limit of 1.5% of FOB value of previous years exports shall also be allowed.

- (b) An EOU/EHTP/STP/BTP unit may import and/or procure from DTA or bonded warehouses in DTA/international exhibition held in India without payment of duty all types of goods, including capital goods, required for its activities, provided they are not prohibited items of import in the ITC (HS). Any permission required for import under any other law shall be applicable. The units shall also be permitted to import goods including capital goods required for the approved activity, free of cost or on loan/lease from clients. The import of capital goods will be on a self certification basis. Goods imported by a unit shall be with actual user condition and shall be utilized for export production.
- (c) State Trading regime shall not apply to EOU manufacturing units.
- (d) EOU/EHTP/STP/BTP units may import/procure from DTA without payment of duty certain specified goods for creating a central facility which will be used by software units. These software units can be EOU/DTA units who will use the facility for export of software.
- (e) An EOU engaged in agriculture, animal husbandry, aquaculture, floriculture, horticulture, pisciculture, viticulture, poultry or sericulture may be permitted to remove specified goods in connection with its activities for use outside the bonded area.
- (f) Gems and jewellery EOUs may source gold/silver/platinum through the nominated agencies on loan/outright purchase basis. The units obtaining gold/silver/platinum from the nominated agencies, either on loan basis or outright purchase basis shall export gold/silver/platinum within 90 days from the date of release.
- (g) EOU/EHTP/STP/BTP units, other than service units, may export to Russian Federation in

Indian Rupees against repayment of State Credit/Escrow Rupee Account of the buyer subject to RBI clearance, if any.

- (h) Procurement and export of spares/components upto 1.5% of the FOB value of exports may be allowed to the same consignee/buyer of the export article within the warranty period.

Second Hand Capital Goods

6.3 Second hand capital goods, without any age limit, may also be imported duty free.

Leasing of Capital Goods

6.4 An EOU/EHTP/STP/BTP unit may, on the basis of a firm contract between the parties, source the capital goods from a domestic/foreign leasing company without payment of customs/excise duty. In such a case, the EOU/EHTP/STP/BTP unit and the domestic/foreign leasing company shall jointly file the documents to enable import/procurement of the capital goods without payment of duty.

Net Foreign Exchange Earnings (NFE)

6.5 EOU/EHTP/STP/BTP unit shall be a positive net foreign exchange earner except for sector specific provision of Appendix 14-1-C of Handbook, where a higher value addition shall be required. Net Foreign Exchange Earning (NFE) shall be calculated cumulatively in blocks of five years, starting from the commencement of production.

Letter of Permission/Letter of Intent and Legal Undertaking

- 6.6(a) On approval, a Letter of Permission (LOP)/Letter of Intent (LOI) shall be issued by the Development Commissioner/designated officer to EOU/EHTP/STP/BTP unit. The LOP/LOI shall have an initial validity of 3 years by which time the unit should have commenced production. Its validity may be extended further upto 3 years by the competent authority. However, proposals for extension beyond six years shall be considered in exceptional circumstances, on a case-to-case basis by the BOA. Once the unit commences production, LOP/LOI issued shall be valid for a period of 5 years for its activities. This period may be extended further by the Development Commissioner for a period of 5 years at a time.
- (b) LOP/LOI issued to EOU/EHTP/STP/BTP units by the concerned authority subject to compliance of provision in para 6.2 above, would be construed as an Authorisation for all purposes.
- (c) The unit shall execute a legal undertaking with the Development Commissioner concerned.

Failure to ensure positive NFE or to abide by any of the terms and conditions of the LOP/LOI/IL/LUT shall render the unit liable to penal action under the provisions of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 and the Rules and Orders made thereunder without prejudice to action under any other law/rules and cancellation or revocation of LOP/LOI/IL.

Investment Criteria

- (d) Only projects having a minimum investment of Rs. 1 Crore in Plant & Machinery shall be considered for establishment as EOUs under the scheme. This shall, however, not apply to existing units and units in EHTP/STP/BTP, Handicrafts/Agriculture/Floriculture/Aquaculture/Animal Husbandry/Information Technology, Services, Brass Hardware and Handmade jewellery sectors. The Board of Approval (BOA) may also allow establishment of EOUs with a lower investment criteria.

Application & Approvals

- 6.7(a) Applications for setting up of units under EOU scheme other than proposals for setting up of units in the services sector (except R & D, software and IT enabled services, or any other service activity as may be delegated by the BOA), shall be approved or rejected by the Units Approval Committee within 15 days as per the criteria indicated in Handbook (Vol-I).
- (b) In other cases, approval may be granted by the Board of Approval (BOA) set up for this purpose as indicated in the Handbook (Vol-I)
- (c) Proposals for setting up EOU requiring industrial licence may be granted approval by the Development Commissioner after clearance of the proposal by the Board of Approval and Department of Industrial Policy and Promotion within 45 days.

DTA Sale of Finished Products/Rejects/Waste/Scrap/Remnants and By-products

6.8 The entire production of EOU/EHTP/STP/BTP units shall be exported subject to the following:

- (a) Units, other than gems and jewellery units, may sell goods upto 50% of FOB value of exports subject to fulfilment of positive NFE on payment of concessional duties. Within the entitlement of DTA sale, the unit may sell in DTA its products similar to the goods, which are exported or expected to be exported from the units. No DTA sale at concessional duty shall be permissible in respect of motor cars.

alcoholic liquors, books, tea (except instant tea), pepper & Pepper products, marble and such other items as may be notified from time to time. Such DTA sale shall also not be permissible to units engaged in the activities of packaging/labeling/segregation/refrigeration/compacting/micronisation/pulverization/granulation/conversion of monohydrate form of chemical to anhydrous form or *vice-versa*.

Sales made to a unit in SEZ shall also be taken into account for the purpose of arriving at FOB value of export by EOU provided payment for such sales are made from Foreign Exchange Account of SEZ unit. Sale to DTA would also be subject to mandatory requirement of registration of pharmaceutical products (including bulk drugs).

- (b) For services, including software units, sale in the DTA in any mode, including on line data communication shall also be permissible up to 50% of FOB value of exports and/or 50% of foreign exchange earned, where payment of such services is received in foreign exchange.
- (c) Gems and jewellery units may sell upto 10% of FOB value of exports of the preceding year in DTA subject to fulfilment of positive NFE. In respect of sale of plain jewellery, the recipient shall pay concessional rate of duty as applicable to sale from nominated agencies. In respect of studded jewellery, duty shall be payable as applicable.
- (d) Unless specifically prohibited in the LOP, rejects within an overall limit of 50% may be sold in the Domestic Tariff Area (DTA) on payment of duties as applicable to sale under paragraph 6.8 (a) on prior intimation to the Customs authorities. Such sales shall be counted against DTA sale entitlement. Sale of rejects upto 5% of FOB value of export shall not be subject to achievement of NFE.
- (e) Scrap/waste/remnants arising out of production process or in connection therewith may be sold in the DTA as per the Standard Input-Output norms notified under the Duty Exemption Scheme on payment of concessional duties as applicable within the overall ceiling of 50% of FOB value of exports. Such sales shall not, however, be subject to achievement of positive NFE. In respect of items not covered by the norms, the Development Commissioner may fix ad-hoc norms on the basis of data for a period of six

months and within this period, he shall get the norms fixed by the BOA. Sale of waste/scrap/remnants by units not entitled to DTA sale or sales beyond the DTA sale entitlement, shall be on payment of full duties. The scrap/waste/remnants may also be exported.

- (f) There shall be no duties/taxes on scrap/waste/remnants in case the same are destroyed with the permission of Customs authorities.
- (g) By-products included in the LOP may also be sold in the DTA subject to achievement of positive NFE on payment of applicable duties within the overall entitlement of paragraph 6.8(a). Sale of by-products by units not entitled to DTA sales or beyond the entitlements of paragraph 6.8 (a) shall also be permissible on payment of full duties.
- (h) EOU/EHTP/STP/BTP units may sell finished products, except pepper and pepper products and marble which are freely importable under the Policy in the DTA under intimation to the Development Commissioner against payment of full duties provided they have achieved the positive NFE.
- (i) In the case of units manufacturing electronics hardware and software, the NFE and DTA sale entitlement shall be reckoned separately for hardware and software.
- (j) In case of DTA sale of goods manufactured by EOU/EHTP/STP/BTP, where basic duty and CVD is nil, such goods may be considered as non-excisable for the purpose of payment of duty.
- (k) In case of new EOUs, advance DTA sale will be allowed not exceeding 50% of its estimated exports for the first year except the pharmaceutical units where this will be based on its estimated exports for the first two years.

Other Supplies in DTA

6.9 Following supplies effected from EOU/EHTP/STP/BTP units to DTA will be counted for the purpose of fulfilment of positive NFE :

- (a) Supplies effected in DTA to holders of advance Authorisation/advance Authorisation for annual requirement/DFRC under the duty exemption/remission scheme/EPCG scheme.
- (b) Deleted
- (c) Supplies to other EOU/EHTP/STP/BTP/SEZ units provided that such goods are permissible for procurement in terms of paragraph 6.2 of the Policy.

- (d) Supplies made to bonded warehouses set up under the policy and/or under Section 65 of the customs act and free trade and warehousing zones, where payment is received in foreign exchange.
- (e) Supplies of goods and services to such organizations which are entitled for duty free import of such items in terms of general exemption notification issued by the Ministry of Finance.
- (f) Supply of services (by services units) relating to exports paid for in free foreign exchange or for such services rendered in Indian Rupees which are otherwise considered as having been paid for in free foreign exchange by RBI.
- (g) Supplies of Information Technology Agreement (ITA-1) items and notified zero duty telecom/electronic items.

Export through others

6.10 An EOU/EHTP/STP/BTP unit may export goods manufactured/software developed by it through another exporter or any other EOU/EHTP/STP/SEZ unit subject to the conditions mentioned in para 6.19 of Handbook.

Entitlement for supplies from the DTA

- 6.11(a) Supplies from the DTA to EOU/EHTP/STP/BTP units will be regarded as "deemed exports" and the DTA supplier shall be eligible for the relevant entitlements under chapter 8 of the Policy besides discharge of export obligation, if any, on the supplier. Notwithstanding the above, EOU/EHTP/STP/BTP units shall, on production of a suitable disclaimer from the DTA supplier, be eligible for obtaining the entitlements specified in chapter 8 of the Policy. For the purpose of claiming deemed export duty drawback, they shall get Brand Rates fixed by the Development Commissioner. Wherever All Industry Rates of Drawback are not available.
- (b) Suppliers of precious and semi-precious stones, synthetic stones and processed pearls from DTA to EOU shall be eligible for grant of Replenishment Licenses at the rates and for the items mentioned in the Handbook (Vol. I).
- (c) In addition, the EOU/EHTP/STP/BTP units shall be entitled to the following :—
 - i. Reimbursement of Central Sales Tax on goods manufactured in India.
 - ii. Exemption from payment of Central Excise Duty on goods procured from DTA on goods manufactured in India.

- iii. deleted
- iv. Reimbursement of Duty paid on fuels procured from domestic oil Companies as per the rate of Drawback notified by the DGFT from time to time.
- v. CENVAT Credit on service tax paid.

Other Entitlements

6.12 Other entitlements of EOU/EHTP/STP/BTP units are as under :

- (a) Exemption from payment of Income Tax as per the provisions of Section 10A and 10B of Income Tax Act.
- (b) Exemption from industrial licensing for manufacture of items reserved for SSI sector.
- (c) deleted
- (d) Export proceeds will be realized within 12 Months.
- (e) Will be allowed to retain 100% of its export earning in the EEFC account.
- (f) The Units will not be required to furnish bank guarantee at the time of import or going for job work in DTA, where the unit has (i) a turnover of Rupees 5 crores or above, (ii) the unit is in existence for at least three years and (iii) unit having an unblemished track record.
- (g) 100% FDI investment permitted through Automatic Route similar to SEZ units.

Inter Unit Transfer

- 6.13 (a) Transfer of manufactured goods from one EOU/EHTP/STP/BTP unit to another EOU/EHTP/STP/BTP unit is allowed with prior intimation to the concerned Development Commissioner and Customs authorities following the procedure of inbound movement of goods.
- (b) Capital goods may be transferred or given on loan to other EOU/EHTP/STP/BTP/SEZ units with prior intimation to the concerned Development Commissioner and Customs authorities.
- (c) Goods supplied by one unit of EOU/EHTP/STP/BTP to another unit shall be treated as imported goods for the second unit for the purpose of payment of duty, on DTA sale by the second unit.

Sub-Contracting

- 6.14 (a) (i) EOU/EHTP/STP/BTP units, including gem and jewellery units, may on the basis of annual permission from the Customs authorities, sub-contract production

processes to DTA through job work which may also involve change of form or nature of goods, through job work by units in the DTA.

- (ii) These units may also sub-contract upto 30% of the overall production of the previous year in value terms for job work in DTA with the permission of the Customs Authorities.
- (b)(i) EOU may, on the basis of annual permission from the Customs Authorities, undertake job work for export, on behalf of DTA exporter, provided that the goods are exported directly from EOU and export document shall jointly be in the name of DTA/EOU. For such exports, the DTA units will be entitled for refund of duty paid on the inputs by way of Brand Rate of duty drawback.
- (ii) Duty free import of goods for execution of export order placed on EOU by Foreign Supplier on job work basis would be allowed subject to the condition that no DTA clearance shall be allowed.
- (iii) Subcontracting of both production and production processes may also be undertaken without any limit through other EOU/EHTP/STP/SEZ/BTP units on the basis of records maintained in the unit.
- (iv) Subcontracting of part of production process may also be permitted abroad with the approval of the Development Commissioner.
- (c) Scrap/waste/remnants generated through job work may either be cleared from the job worker's premises on payment of applicable duty on transaction value or destroyed in the presence of Customs/Excise authorities or returned to the unit. Destruction shall not apply to gold, silver, platinum, diamond, precious and semi-precious stones.
- (d) Sub-contracting/exchange by gems and jewellery EOUs through other EOUs or SEZ units or units in DTA shall be as per procedure indicated in Handbook (Vol.-I).

Sale of Un-utilised Material

- 6.15 (a) In case an EOU/EHTP/STP/BTP unit is unable to utilize the goods and services, imported or procured from DTA, it may be (i) transferred to another EOU/SEZ/EHTP/STP/BTP unit or (ii) disposed off in the DTA with the approval of

the Customs authorities on payment of applicable duties and submission of import Authorization, if required, or (iii) exported. Such transfer from EOU/EHTP/STP/BTP unit to another such unit would be treated as import for the receiving unit.

- (b) Capital goods and spares that have become obsolete/surplus, may either be exported, transferred to another EOU/EHTP/STP/BTP/SEZ or disposed of in the DTA on payment of applicable duties. The benefit of depreciation, as applicable, will be available in case of disposal in DTA. No duty shall be payable in case capital goods, raw material, consumable, spares, goods manufactured processed or packaged, and scrap/waste/remnants/rejects are destroyed within the Unit after intimation to the Customs authorities or destroyed outside the Unit with the permission of Customs authorities. Destruction as stated above shall not apply to gold, silver, platinum, diamond, precious and semi-precious stones.
- (c) In the case of textile sector, disposal of leftover material/fabrics upto 2% of cif value or quantity of import, whichever is lower, on payment of duty on transaction value may be allowed, subject to certification of central excise/custom officers that these are leftover items.
- (d) Disposal of used packing material will be allowed on payment of duty on transaction value.

Reconditioning/Repair and Re-engineering

- 6.16 EOU/EHTP/STP/BTP units may be set up with the approval of BOA to carry out re-conditioning, repair, remaking, testing, calibration, quality improvement, up-gradation of technology and re-engineering activities for export in foreign currency. The provisions of paragraphs 6.8, 6.9, 6.10, 6.13, 6.14 of policy and para 6.29 of Handbook shall not, however, apply to such activities.

Replacement/Repair of imported/Indigenous Goods

- 6.17 (a) The general provisions of the Policy relating to export/import of replacement/repair of goods would also apply equally to EOU/EHTP/STP/BTP units. Cases not covered by these provisions shall be considered on merits by the Development Commissioner.
- (b) The goods sold in the DTA and not accepted for any reasons may be brought back for repair/replacement, under intimation to the concerned jurisdictional Customs/Excise authorities.

- (c) Goods or parts thereof on being imported/indigenously procured and found defective or otherwise unfit for use or which have been damaged or become defective subsequently may be returned and replacement obtained or destroyed. In the event of replacement, the goods may be brought back from the foreign suppliers or their authorized agents in India or indigenous suppliers. However destruction shall not apply to precious and semi-precious stones and precious metals.

Exit from EOU Scheme

- 6.18(a) With the approval of the Development Commissioner, EOU units may opt out of the scheme. Such exit from the scheme shall be subject to payment of Excise and Customs duties and the industrial policy in force at the time of exit.
- (b) If the unit has not achieved the obligations under the scheme, it shall also be liable to penalty at the time of exit.
- (c) In the event of a gem and jewellery unit ceasing its operation, gold and other precious metals, alloys, gem and other materials available for manufacture of jewellery, shall be handed over to an agency nominated by the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce) at the price to be determined by that agency.
- (d) An EOU/EHTP/STP/BTP unit may also be permitted by the Development Commissioner, to exit from the scheme on payment of duty on capital goods under the prevailing EPCG Scheme as a one time option. This will be subject to fulfilment of the eligibility criteria under that Scheme and standard conditions indicated in Handbook (Vol-I).
- (e) The unit proposing to exit out of the EOU scheme shall intimate the Development Commissioner and Customs and Central Excise authorities in writing. The unit shall assess the duty liability arising out of debonding and submit the details of such assessment to customs and Central Excise authorities. The Customs and Central Excise authorities shall confirm the duty liabilities on priority basis. After payment of duty and clearance of all dues the unit shall obtain "No Dues Certificate" from the Customs and Central Excise authorities. On the basis of No dues certificate so issued by the Customs and Central Excise authorities, the unit shall apply to the Development Commissioner for final debonding. In case there is no proceeding pending under FT(DR) Act, 1992, the Development Commissioner shall issue final debonding order within a period of 7 working days. During the

period between "No dues certificate" issued by the Customs and Central Excise authorities and the final debonding order by the Development Commissioner, the unit shall not be entitled to claim any exemption for procurement of capital goods or input. The unit can however, claim Advance License/DEPB/ Duty Drawback.

- (f) In cases where a unit is initially established as DTA unit with machine procured from abroad after payment of applicable import duty or from domestic market after payment of excise duty and the unit is subsequently converted to EOU, in such cases removal of such capital goods to DTA after debonding would be without payment of duty. Similarly, in cases where a DTA unit imported capital goods under the EPCG Scheme and after completely fulfilling the export obligation under the EPCG scheme gets converted into EOU, the unit would not be charged customs duty on capital goods at the time of removal of such capital goods in DTA at the time of debonding.

Conversion

- 6.19(a) Existing DTA units, may also apply for conversion into an EOU/EHTP/STP/BTP unit, and Income Tax benefits under Section 10-A & 10-B will be available under the scheme for plant, machinery and equipment already installed.
- (b) The existing EHTP/STP units may also apply for conversion/merger to EOU unit and vice-versa. In such cases, the units will remain in bond and avail the exemptions in duties and taxes as applicable under the relevant scheme.

Monitoring of NFE

6.20 The performance of EOU/EHTP/STP/BTP units shall be monitored by the Units Approval Committee as per the guidelines given in Handbook (vol-I).

Export through exhibitions/Export Promotion Tours/Export through showrooms abroad/Duty Free Shops.

6.21 EOU/EHTP/STP/BTP are permitted to:

- (i) Export goods for holding/participating in exhibitions abroad with the permission of Development Commissioner.
- (ii) Personal carriage of gold/silver/platinum jewellery, precious, semi-precious stones, beads and articles.
- (iii) Export goods for display/sale in the permitted shops set up abroad.
- (iv) Display/sell in the permitted shops set up abroad or in the show rooms of their distributors/agents.
- (v) Set up show rooms/retail outlets at the International Airports.

Personal Carriage of Import/Export Parcels Including through Foreign bound Passengers

6.22 Import/export through personal carriage of gem and jewellery items may be under-taken as per the procedure prescribed by Customs. The export proceeds shall, however, be realized through normal banking channel. Import/export through personal carriage by units, other than gem and jewellery units, shall be allowed provided the goods are not in commercial quantity.

Export/Import by Post/Courier

6.23 Goods including free samples, may be exported/imported by airfreight or through Foreign Post Office or through courier, subject to the procedure prescribed by Customs.

Administration of EOUs/Power of Development Commissioner

6.24 Details of administration of EOUs and Power of Development Commissioner are given in Handbook (Vol. I).

Revival of Sick units

6.25 Subject to a unit being declared sick by the appropriate authority, proposals for revival of the unit or its take over may be considered by the Board of Approval.

Approval for EHTP/STP

6.26 In the case of units under EHTP/STP Schemes, necessary approval/permission under relevant paragraphs of this Chapter shall be granted by the officer designated by the Ministry of Communication and Information Technology, Department of Information Technology for the purpose instead of the Development Commissioner and by the Inter-Ministerial Standing Committee (IMSC) instead of BOA.

Approval of BTP

6.27 Bio-Technology Parks (BTP) would be notified by the DGFT on the recommendations of Department of Biotechnology. In the case of units in the BTP, necessary approval/permission under relevant provisions of this chapter will be granted by designated officer of the Department of Biotechnology.

CHAPTER-7

SPECIAL ECONOMIC ZONES

The policy relating to Special Economic Zones is governed by SEZ Act, 2005, and the Rules framed thereunder.

CHAPTER-7A

FREE TRADE & WAREHOUSING ZONES

The policy relating to Free Trade and Warehousing Zones is governed by SEZ Act, 2005, and the Rules Framed thereunder.

CHAPTER-8

DEEMED EXPORTS

Deemed Exports

8.1 "Deemed Exports" refers to those transactions in which the goods supplied do not leave the country and the payment for such supplies is received either in Indian rupees or in free foreign exchange.

Categories of Supply

8.2 The following categories of supply of goods by the main/sub-contractors shall be regarded as "Deemed Exports" under this Policy, provided the goods are manufactured in India:

- (a) Supply of goods against Advance Authorisation/ Advance Authorisation for annual requirement;
- (b) Supply of goods to Export Oriented Units (EOUs) or Software Technology Parks (STPs) or electronic Hardware Technology Parks (EHTPs) or Bio Technology Parks (BTP);
- (c) Supply of capital goods to holders of Authorisations under the Export Promotion Capital Goods (EPCG) scheme;
- (d) Supply of goods to projects financed by multilateral or bilateral agencies/funds as notified by the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance under International Competitive Bidding in accordance with the procedures of those agencies/ funds, where the legal agreements provide for tender evaluation without including the customs duty;
Supply and installation of goods and equipment (single responsibility of turnkey contracts) to projects financed by multilateral or bilateral agencies/funds as notified by Department of Economic Affairs, Ministry of Finance under International Competitive Bidding in accordance with the procedures of those agencies/funds, which the bids may have been invited and evaluated on the basis of Delivered Duty Paid (DDP) prices for the goods manufactured abroad.
- (e) Supply of capital goods, including in unassembled/disassembled condition as well as plants, machinery, accessories, tools, dies and such goods which are used for installation purposes till the stage of commercial production and spares to the extent of 10% of the FOR value to fertilizer plants;
- (f) Supply of goods to any project or purpose in respect of which the Ministry of Finance, by a notification, permits the import of such goods at zero customs duty;
- (g) Supply of goods to the power projects and refineries not covered in (f) above;
- (h) Supply of marine freight containers by 100% EOU (Domestic freight containers-manufacturers provided the said containers are exported out of India within 6 months or such further period as permitted by the customs;
- (i) Supply to projects funded by UN agencies; and
- (j) Supply of goods to nuclear power projects through competitive bidding as opposed to International Competitive Bidding.

The benefits of deemed exports shall be available under paragraph (d), (e), (f) and (g) only if the supply is made under the procedure of International Competitive Bidding (ICB).

Benefits for Deemed Exports

8.3 Deemed exports shall be eligible for any/all of the following benefits in respect of manufacture and supply of goods qualifying as deemed exports subject to the terms and conditions as given in Handbook (Vol. I):—

- (a) Advance Authorisation
- (b) Deemed Export Drawback.
- (c) Exemption from terminal excise duty where supplies are made against International Competitive Bidding. In other cases, refund of terminal excise duty will be given.

Benefits to the Supplier

8.4.1(i) In respect of supplies made against Advance Authorisation in terms of paragraphs 8.2 (a) of the Policy, the supplier shall be entitled to Advance Authorisation for intermediate supplies.

(ii) If the supplies are made against Advance Release Order (ARO) or Back to Back Letter of Credit issued against Advance Authorisation in terms of paragraphs 4.1.11 and 4.1.12 of the Policy, supplier shall be entitled to the benefits listed in paragraphs 8.3 (b) and (c) of the Policy, whichever is applicable.

(iii) If the supplies are made against Advance Release Order (ARO) or Back to Back Letter of Credit issued against DFRC, the supplier shall be entitled to the benefit listed in paragraph 8.3 (b) of the Policy.

8.4.2 In respect of supply of goods to EOU/EHTP/STP/BTP in terms of paragraphs 8.2 (b) of the Policy, the supplier shall be entitled to the benefits listed in paragraph 8.3 (a), (b) and (c) of the Policy, whichever is applicable.

8.4.3 In respect of supplies made under paragraph 8.2 (c) of the Policy, the supplier shall be entitled to the benefits listed in paragraphs 8.3 (a), (b) and (c), of the Policy, whichever is applicable.

8.4.4 (i) In respect of supplies made under paragraphs 8.2 (d), (f) and (g) of the Policy, the supplier shall be entitled to the benefits listed in paragraphs 8.3 (a), (b) and (c), whichever is applicable.

(ii) In respect of supplies mentioned in paragraph 8.2 (d), supplies to the projects funded by such agencies alone, as may be notified by Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, shall be eligible for deemed export benefits. A list of such agencies/funds is given in Appendix-13 of Handbook (Vol. I).

(iii) The benefits of deemed exports under para 8.2 (f) of the Policy shall be applicable in respect of items, import of which is allowed by the Department of Revenue at zero customs duty subject to fulfillment of conditions specified under Notification No.21/2002-Customs dated 1-3-2002, as amended from time to time.

(iv) Supply of Capital goods and spares up to 10% of the FOR value of the capital goods to the power projects in terms of paragraph 8.2 (g) shall be entitled for deemed export benefits provided the International Competitive Bidding procedures have been followed at Independent Power Producer (IPP)/Engineering and Procurement Contract (EPC) stage. The benefit of deemed exports shall also be available for renovation/modernization of power plants. The supplier shall be eligible for benefits listed in paragraph 8.3 (a) and (b) of the Policy, whichever is applicable. However, supply of goods required for setting up of any mega power projects as specified in S. No. 400 of Department of Revenue Notification No.21/2002-Customs dated 1-3-2002, as amended, shall be eligible for deemed exports benefits as mentioned in paragraph 8.3 (a), (b) and (c) of the Policy whichever is applicable, if such mega power project is :—

- (a) an inter state thermal power plant of capacity of 1000 MW or more; or
- (b) an inter state Hydel power plant of capacity of 500 MW or more.
- (c) Supplies under paragraph 8.2(g) of the Policy to the new refineries being set up during the Ninth plan period and spilled over to the Tenth plan period shall be entitled for deemed export benefits in respect of goods mentioned in list 17 specified in S. No. 228 of Notification No. 21/2002-Customs dated 1-3-2002, as amended from time to time. The supplier shall be eligible for benefits listed in paragraphs 8.3(a) and (b) of the Policy, whichever is applicable.

8.4.5 In respect of supplies made under paragraph 8.2(e) of the Policy, the supplier shall be eligible for the benefits listed in paragraphs 8.3(a) and (b) of the Policy, whichever is applicable. The benefit of deemed exports shall be available in respect of supplies of capital goods and spares to fertilizer plants which are set up or expanded/revamped/retrofitted/modernized during the Ninth Plan period. The benefit of deemed exports shall also be available on supplies made to Fertilizer plants, which have started in the 8th/9th Plan periods and spilled over to the 10th Plan period.

8.4.6 The supplies of goods to project funded by UN agencies covered under Para 8.2(i) of the Policy are eligible for benefits listed in paragraphs 8.3(a) and (b) of the Policy, whichever is applicable.

8.4.7 In respect of supplies made to nuclear Power Projects under para 8.2(j) of the policy, the supplier would be eligible for benefits given in paras 8.3 (a), (b) and (c) of the Policy, whichever is applicable. Supply of only those goods required for setting up any nuclear power project specified in list 43 at S. No. 401 of Notification No. 21/2002-Customs dated 1-3-2002, as amended from time to time having a capacity of 440 MW or more as certified by an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India in the Department of Atomic Energy shall be entitled for deemed exports benefits in cases where the procedure of competitive Bidding (and not International competitive Bidding) has been followed.

Eligibility for refund of terminal excise duty/drawback

8.5 Supply of goods will be eligible for refund of Terminal Excise Duty in terms of para 8.3(c) of Policy provided the recipient of the goods does not avail CENVAT credit/rebate on such goods. Similarly, supplies will be eligible for deemed export drawback in terms of para 8.3(b) of Policy on the Central Excise paid on inputs/components, provided CENVAT credit facility/rebate has not been availed by the applicant. Such supplies will however be eligible for deemed export drawback on the customs duty paid on the inputs/components.

Supplies to be made by the main/sub-contractor

8.6.1 In all cases of deemed exports, supplies shall be made directly to the designated Projects/Agencies/Units/Advance Authorisation/EPCG Authorisation holders. The sub-contractor may, however, make the supplies to the main contractor as per paragraph 8.4 of Handbook instead of designated projects/agencies.

8.6.2 Supplies made by an Indian sub-contractor of an Indian or foreign main contractor, shall also be eligible for deemed export benefits provided the name of the sub-contractor is indicated either originally or subsequently in the contract, and payment certificate is issued by the project authority in the name of the sub-contractor in the form given in Appendix 22C of Handbook (Vol. I).

Chapter-9

Definitions

9.1 For the purpose of this Policy, unless the context otherwise requires, the following words and expressions shall have the following meanings attached to them.

9.2 "Accessory" or "Attachment" means a part, sub-assembly or assembly that contributes to the efficiency or effectiveness of a piece of equipment without changing its basic functions.

9.3 "Act" means the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992).

9.4 "Actual User" means an actual user who may be either industrial or non-industrial.

9.5 "Actual User (Industrial)" means a person who utilises the imported goods for manufacturing in his own industrial unit or manufacturing for his own use in another unit including a jobbing unit.

9.6 "Actual User (Non-Industrial)" means a person who utilises the imported goods for his own use in:

- (i) any commercial establishment carrying on any business, trade or professions; or
- (ii) any Laboratory, Scientific or Research and Development (R&D) institution, university or other educational institution or hospital; or
- (iii) any service industry.

9.7 "AEZ" means Agricultural Export Zones notified by DGFT in Appendix 8 of Handbook (Vol. I).

9.8 Deleted.

9.9 "Applicant" means the person on whose behalf the application is made and shall, wherever the context so requires, include the person signing the application

9.9.1 "Authorisation" means a permission as included in Section 2(g) of The Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) to import or export as per provisions of this policy.

9.10 "BOA" means the Board of Approval as notified by the Department of Commerce.

9.11 "BTP" means Biotechnology Park as notified by Director General of Foreign Trade on the recommendation of the Department of Biotechnology.

9.12. "Capital Goods" means any plant, machinery, equipment or accessories required for manufacture or production, either directly or indirectly, of goods or for rendering services, including those required for replacement, modernisation, technological upgradation or expansion. Capital goods also include packaging machinery and equipment, refractories for initial lining, refrigeration equipment, power generating sets, machine tools, catalysts for initial charge, equipment and instruments for testing, research and development, quality and pollution control. Capital goods may be for use in manufacturing, mining, agriculture, aquaculture, animal husbandry, floriculture, horticulture, pisciculture, poultry, sericulture and viticulture as well as for use in the services sector.

9.13 "Competent Authority" means an authority competent to exercise any power or to discharge any duty or function under the Act or the Rules and Orders made thereunder or under this Policy.

9.14 "Component" means one of the parts of a sub-assembly or assembly of which a manufactured product is made up and into which it may be resolved. a component includes an accessory or attachment to the component.

9.15 "Consumables" means any item, which participates in or is required for a manufacturing process, but does not necessarily form part of the end-product.

Items, which are substantially or totally consumed during a manufacturing process will be deemed to be consumables.

9.16 "Consumer Goods" means any consumption goods, which can directly satisfy human needs without further processing and includes consumer durables and accessories thereof.

9.17 "Counter Trade" means any arrangement under which exports/imports from/to India are balanced either by direct imports/exports from the importing/exporting country or through a third country under a Trade Agreement or otherwise. Exports/Imports under Counter Trade may be carried out through Escrow Account, Buy Back arrangements, Barter trade or any similar arrangement. The balancing of exports and imports could wholly or partly be in cash, goods and/or services.

9.18 "Developer" means a person or body of persons, company, firm and such other private or Government undertaking, who develops, builds, designs, organises, promotes, finances, operates, maintain or manages a part or whole of the infrastructure and other facilities in the Special Economic Zones as approved by the Central Government.

9.19 "Development Commissioner" means the Development Commissioner of the Special Economic Zone.

9.20 "DFRC" means Duty Free Replenishment Certificate.

9.21 "Domestic Tariff Area" means area within India which is outside the Special Economic Zones and EOU/ EHTP/STP/BTP.

9.22 "Drawback," in relation to any goods manufactured in India and exported, means the rebate of duty chargeable on any imported material or excisable material used in the manufacture of such goods in India. The goods include imported spares, if supplied with capital goods manufactured in India.

9.23 "EHTP" means Electronic Hardware Technology Park.

9.24 "EOU" means Export Oriented Unit for which an LOP has been issued by the Development Commissioner.

9.25 "Excisable goods" means any goods produced or manufactured in India and subject to a duty of excise under the Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944).

9.26 "Exporter" means a person who exports or intends to export and holds an Importer-Exporter Code number unless otherwise specifically exempted.

9.27 "Export Obligation" means the obligation to export the product or products covered by the Authorisation or permission in terms of quantity, value or both, as may be prescribed or specified by the licensing or competent authority.

9.28 "Group Company" means two or more enterprises which, directly or indirectly, are in a position to—

- (i) exercise twenty-six per cent, or more of the voting rights in the other enterprise; or

- (ii) appoint more than fifty percent. of the members of the board of directors in the other enterprise.

For the group companies to claim benefits or have their exports counted for benefits to be claimed by another member of the group, the group company should have been in existence at least 2 years prior to the date of application under any of the export promotion schemes notified in the Policy.

9.29 "Handbook (Vol. 1)" means the Handbook of Procedures (Vol. 1) and "Handbook (Vol. 2)" means Handbook of Procedures (Vol. 2) published under the provisions of paragraph 2.4 of the Policy.

9.30 "Importer" means a person who imports or intends to import and holds an Importer-Exporter Code number unless otherwise specifically exempted.

9.31 "Infrastructure facilities" means industrial, commercial and social infrastructure or any other facility for the development of the Special Economic Zone as notified.

9.32 "ITC (HS)" means ITC (HS) Classifications of Export and Import Items Book.

9.33 "Jobbing" means processing or working upon of raw materials or semi-finished goods supplied to the job worker so as to complete a part of the process resulting in the manufacture or finishing of an article or any operation which is essential for the aforesaid process.

9.34 "Licensing Authority" means the authority competent to grant an Authorisation under the Act/Order.

9.35 "Licensing Year" means the period beginning on the 1st April of a year and ending on the 31st March of the following year.

9.36 "Managed Hotel" means hotels managed by a three star or above hotel/hotel chain under an operating management contract for a duration of at least three years between the operating hotel/hotel chain and the hotel being managed. The management contract must necessarily cover the entire gamut of operations/management of the managed hotel.

9.37 "Manufacture" means to make, produce, fabricate, assemble, process or bring into existence, by hand or by machine, a new product having a distinctive name, character or use and shall include processes such as refrigeration, re-packing, polishing, labelling, Reconditioning repair, remaking, refurbishing, testing, calibration, re-engineering. Manufacture, for the purpose of this Policy, shall also include agriculture, aquaculture, animal husbandry, floriculture, horticulture, pisciculture, poultry, sericulture, viticulture and mining.

9.38 "Manufacturer Exporter" means a person who export goods manufactured by him or intends to export such goods.

9.39 "MAI" means Market Access Initiative Scheme notified by the Department of Commerce.

9.40 "Merchant Exporter" means a person engaged in trading activity and exporting or intending to export goods.

9.40.1 "NC" means the Norms Committee in the Directorate General of Foreign Trade for recommending grant of Authorisations under Duty Exemption Scheme and for recommending Input Output norms and value addition norms to be notified by Director General of Foreign Trade.

9.41 "NFE" mean Net Foreign Exchange Earning.

9.42 "Notification" means a notification published in the Official Gazette.

9.43 "Order" means an Order made by the Central Government under the Act.

9.44 "Part" means an element of a sub-assembly or assembly not normally useful by itself and not amenable to further disassembly for maintenance purposes. A part may be a component, spare or an accessory.

9.45 "Person" includes an individual, firm, society, company, corporation or any other legal person.

9.46 "Policy" means the Foreign Trade Policy 2004—2009 as amended from time to time.

9.47 "Prescribed" means prescribed under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) or the Rules or Orders made thereunder or under this Policy.

9.48 "Public Notice" means a notice published under the provisions of paragraph 2.4 of the Policy.

9.49 "Raw material" means:

- (i) basic materials which are needed for the manufacture of goods, but which are still in a raw, natural, unrefined or unmanufactured state; and
- (ii) for a manufacturer, any materials or goods which are required for his manufacturing process, whether they have actually been previously manufactured or are processed or are still in a raw or natural state.

9.50 "Registration-cum-Membership Certificate" (RCMC) means the certificate of registration and membership granted by an Export Promotion Council/Commodity Board/Development Authority or other competent authority as prescribed in the Policy or Handbook (Vol. I).

9.51 "Rules" means Rules made by the Central Government under Section 19 of the Act.

9.52 "Services" include all the tradable services covered under General Agreement on Trade in Services and earning free foreign exchange.

9.53 "Service Provider" means a person providing

- (i) Supply of a 'service' from India to any other country;

- (ii) Supply of a 'service' from India to the service consumer of any other country in India; and

- (iii) Supply of a 'service' from India through commercial or physical presence in the territory of any other country;

- (iv) Supply of a 'service' in India relating to exports paid in free foreign exchange or in Indian Rupees which are otherwise considered as having being paid for in free foreign exchange by RBI.

9.54 "SEZ" means Special Economic Zone notified by the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce.

9.55 "Ships" mean all types of vessels used for sea borne trade or coastal trade and shall include second hand vessels.

9.56 "SION" means Standard Input Output Norms notified by DGFT in the Handbook (Vol. 2), 2002—2007/ approved by Board of Approval.

9.57 "Spares" means a part or a sub-assembly or assembly for substitution, that is ready to replace an identical or similar part or sub-assembly or assembly. Spaces include a component or an accessor.

9.58 "Specified" means specified by or under the provisions of this Policy.

9.59 "Status holder" means an exporter recognized as One to Five Star Export House by DGFT/Development Commissioner.

9.60 "STP" means Software Technology Park.

9.61 "Supporting Manufacturer" means any person who manufactures any product or part/accessories/ components of that product. The name of the supporting manufacturer as well as the exporter must be endorsed on the export documents.

9.62 "Third-party exports" means exports made by an exporter or manufacturer on behalf of another exporter(s). In such cases, export documents such as shipping bills etc. shall indicate the name of both the manufacturing exporter/manufacturer and third party exporter(s). The BRC, GR declaration, export order and the invoice should be in the name of the third party exporter.

9.63 "Transaction Value" as defined in the Customs Valuation Rules of the Department of Revenue.

9.64 "Unit Approval Committee" means the Committee notified for Special Economic Zones to consider proposals on matters relating to Special Economic Zone unit under its jurisdiction.

9.65 "Wild Animal" means any wild animal as defined in Section 2(36) of the Wildlife (Protection) Act, 1972.